

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol.XI, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No.13, Wednesday, August 11, 2010/Sravana 20, 1932(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.241 to 243	2-28
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.244 to 260	29-96
Unstarred Question Nos.2761 to 2985	97-459

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RE: FINANCIAL ASSISTANCE TO THE VICTIMS OF CLOUDBURST AT LEH, JAMMU AND KASHMIR FROM MP LOCAL AREA DEVELOPMENT FUND	460
PAPERS LAID ON THE TABLE	461-464
MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA	465
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 9th Report	466
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE (i) 46th Report (ii) Evidence	466
STATEMENT BY MINISTER Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on "Constraints being faced by Kendriya Bhandar", pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Shri Prithviraj Chavan	467
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 928 DATED 25.11.2009 REGARDING EDUCATION CESS ALONGWITH THE REASONS FOR DELAY Shrimati D. Purandeswari	468-469
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (RAILWAYS), 2010-11 Shri K.H. Muniappa	470

MATTERS UNDER RULE 377**471-490**

- (i) Need to review the New Exploration Licensing Policy and bring the functioning of Production Sharing Contract (PSC) under the control of CAG to check the possibility of irregularities in accounting

Shri Harsh Vardhan

472

- (ii) Need to declare Kalagarh as a Revenue region of Uttarakhand and transfer the land of Kalagarh region from the Government of Uttar Pradesh to the Department of Irrigation, Uttarakhand

Shri Satpal Maharaj

473-474

- (iii) Need to constitute a Board to ensure checking of soil erosion in various districts along the rivers Ganga and Bhagirathi in West Bengal.

Shri Adhir Chowdhury

475

- (iv) Need to adopt a uniform procedure by University Grants Commission for admission of students in colleges of Uttar Pradesh

Shri Jagdambika Pal

476

- (v) Need to take steps to make the river Yamuna pollution free

Shri Jai Prakash Agarwal

477

- (vi) Need to take steps for proper storage of foodgrains in the country

Dr. Mahesh Joshi

478

- (vii) Need to make the B.S.N.L. landline service more attractive for the costomers with a view to check the decline in the number of B.S.N.L. landline users

Shri A.T. Nana Patil

479

- (viii) Need to release funds for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in Madhya Pradesh and also accord approval to the proposals sent by

	the State Government	
	Shri Ganesh Singh	480
(ix)	Need to enact a legislation for proper disposal and recycling of electronic waste in the country.	
	Shrimati Jayshreeben Patel	481
(x)	Need to re-start the Jodhpur Mail from Delhi to Jodhpur via Churu-Ratangarh in Rajasthan	
	Shri Ram Singh Kaswan	482
(xi)	Need to take steps to check corporal punishment in schools	
	Shri Ambica Banerjee	483
(xii)	Need to provide assistance to the people affected by severe erosion caused by various rivers in North Bengal	
	Shri Mahendra Kumar Roy	484
(xiii)	Need to allocate funds for repair and maintenance of Tindivanam-Krishanigiri NH-66 in Tamil Nadu	
	Shri E.G. Sugavanam	485
(xiv)	Need to ensure strict implementation of existing laws to curb female foeticide in country to bring the female sex ratio at par with male	
	Shrimati Supriya Sule	486
(xv)	Need to direct the leading TV Networks to provide their pay channels for running cable TV-multiple system operators in Tiruppur, Tamil Nadu	
	Shri C. Sivasami	487
(xvi)	Need to provide funds from Central Road Fund for repair and maintenance of various roads in Tenkasi Parliamentary Constituency, Tamil Nadu	
	Shri P. Lingam	488
(xvii)	Need to expedite construction work of ROB at Pandavapura railway station in Mandya Parliamentary Constituency, Karnataka	
	Shri N. Cheluvarya Swamy	489
(xviii)	Need to extend hassle free loan facility to Small and Marginal farmers in Siwan Parliamentary Constituency of	

Bihar through Kisan Credit Card
Shri Om Prakash Yadav

490

DISCUSSION UNDER RULE 193**491-645****RE: Bhopal Gas Tragedy**

Shrimati Sushma Swaraj	491-512
Shri Manish Tewari	513-530
Shri Mulayam Singh Yadav	531-536
Dr. Baliram	537-539
Shri Mangani Lal Mandal	540-543
Shri Pinaki Misra	544-549
Shri Prabodh Panda	550-552
Shri Sher Singh Ghubaya	553-556
Shri Basu Deb Acharia	557-561
Shri Kailash Joshi	562-566 573-574
Shri Sajjan Verma	567-570
Shri Kalyan Banerjee	575-577
Shri S. Semmalai	578-579
Shri Nama Nageswara Rao	580-581
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	582-585
Shri Prasanta Kumar Majumdar	586-587
Shri Narahari Mahato	588
Shri Naranbhai Kachhadia	589
Dr. Kirit Premjibhai Solanki	590
Shri B. Mahtab	591-593
Dr. Tarun Mandal	594-595
Shri Arjun Ram Meghwal	596
Shri Ravindra Kumar Pandey	597-599
Shrimati Yashodhara Raje Scindia	600-601
Shrimati Jayshreeben Patel	602

Shri Charles Dias	603-604
Dr. Prasanna Kumar Patasani	605-610
Shri Premdas	611
Shri S.S. Ramasubbu	612-613
Shri Srikant Jena	614-628
Shri P. Chidambaram	629-645

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	666
Member-wise Index to Unstarred Questions	667-671

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	672
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	673

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, August 11, 2010/Sravana 20, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): अध्यक्ष महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है।

सारे पूर्वांचल में सूखा पड़ा हुआ है।... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि इस पर सदन में चर्चा कराई

जाए।... (व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली) महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए विशेष

सहायता दी जाए। ... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): हम तैयार हैं।... (व्यवधान)

श्री रामकिशुन अध्यक्ष महोदया, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है इसलिए मेरी बात को सुना

जाए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं और प्रश्न काल चलने दें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं। कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दीजिए। धर्मेन्द्र यादव जी आप सवाल पूछें।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): अध्यक्ष महोदया, हाउस को व्यवस्थित कर दीजिए, मैं सवाल पूछना चाहता

हूँ।... (व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह : इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए, कल नहीं तो परसों कराई

जाए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो चिंता है, आप जिस बात को लेकर उद्वेलित हैं, वह हम समझ रहे हैं। आपकी चिंता को भी हम समझ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि इस अत्यंत गम्भीर विषय पर चर्चा हो। इसके लिए आप नोटिस दे दें, उसके बाद चर्चा कराई जाएगी। अब प्रश्न काल चलने दें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: योगी जी आप बैठ जाएं। श्री धर्मेन्द्र यादव, आप सवाल पूछें।

* Not recorded.



(Q. No.241)

MADAM SPEAKER : Shri Dharmendra Yadav, Q. No.241.

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत विश्वगुरु कहलाता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद तमाम बड़े-बड़े स्थानों पर गये और दुनिया की तरक्की में भारत के शिक्षाविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि मानव-संसाधन मंत्री जी क्यों ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिस विधेयक के माध्यम से, दुनिया के तमाम शिक्षा-संस्थान भारत को एक बाजार के रूप में इस्तेमाल करके, भारतीय पूंजी को लूटकर अपने देशों में ले जाना चाहते हैं। मैं मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कराना चाहता हूँ। प्रो. यशपाल जी जो यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे और आपने उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की थी। उस समिति की संस्तुति कहती है कि किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना में वहां की भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय ही क्यों न हो, जब तक वहां की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं होंगी, तब तक वह विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर जाकर स्थापित नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी उद्योगपति आयें, वे भारत में बड़ी-बड़ी इमारतें जरूर बना सकते हैं लेकिन जो भारतीय परिवेश है, जो भारत की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को देखते हुए ये जो विदेशी विश्वविद्यालय का विधेयक आ रहा है। जो तमाम विदेशी शिक्षण-संस्थान इस देश में आ रहे हैं, ये संस्थान भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर पायेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपका ध्यान दादाभाई नौरोजी, जो देश के बहुत बड़े शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक “ पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया” में वैल्थ-ड्रेन की बात की थी, जिसके माध्यम से भारत का पैसा विदेश में जाता है। अध्यक्ष जी, आज परिस्थितियां बदली हैं, माध्यम बदला है, पहले जहां दुनिया में पैसा सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, आज ज्ञान सबसे बड़ी ताकत हो चुकी है। आज इस विधेयक के माध्यम से हमारा जो दिमाग है, वह दुनिया में विस्थापित होगा, इस बात की मुझे पूरी शंका है। क्या मानव संसाधन मंत्री जी इस सदन को और देश को आश्वस्त करा पाएंगे कि हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, उसे बाहर जाने से रोक पाएंगे।

श्री कपिल सिब्बल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ गंभीर बातें हमारे सामने रखी हैं और यह बात सही है कि प्राचीन जमाने में बाहर से पढ़ने के लिए लोग हिंदुस्तान में आते थे। लेकिन 21वीं सदी की व्यवस्था आज कुछ अलग है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यहां से लाखों की तादाद में लोग

पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। हिंदुस्तान में जो ग्रास-इंरोलमेंट रेशो हैं और इसका मतलब यह है कि जो बच्चे 18 से 24 साल की उम्र के हैं, अगर 100 बच्चे इस उम्र के हैं और 12वीं पास करते हैं तो केवल 12.4 प्रतिशत बच्चे ही यूनिवर्सिटी जा पाते हैं, 88 प्रतिशत बच्चे यूनिवर्सिटी जा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि यहां ना तो इतनी यूनिवर्सिटीज हैं और ना ही यहां इतने साधन हैं और आज हमारा देश सबसे यूवा देश है जहां लगभग 55 करोड़ बच्चे 25 वर्ष की उम्र से कम के हैं। अगर उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर शिक्षा मिलेगी तो 12वीं कक्षा के बाद वे कौन सी संस्थाओं में जाएंगे? अगर आप डिवेलप देश और डिवेलपिंग देश का अंतर कीजिए, हर डिवेलप देश में ग्रास-इंरोलमेंट-रेशो 50 प्रतिशत से ज्यादा है। अगर बाकी देशों में कोई बच्चा 12वीं पास करता है, अगर 100 बच्चे हैं 18 से 24 साल की उम्र के, 50 प्रतिशत बच्चे आगे पढ़ाई के लिए जाते हैं, यहां वह संख्या 12.4 प्रतिशत है। हमारा लक्ष्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुलें ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के इंटेग्रिटीयूअर्स और एकेडमिक यूनिवर्सिटीज लगाएं। अगर बाहर से भी हम ग्रास एनरोलमेंट रेशो बढ़ा सकते हैं, तो वहां भी बढ़ाएं। यह हमारा लक्ष्य है।

माननीय सदस्य ने बिल के संबंध में जो बात सभा पटल पर रखी है, वह बिल स्टैंडिंग कमेटी के दायरे में है और वहां उसकी चर्चा हो रही है। अगर आप चाहें, तो मैं उसके बारे में विस्तार से बोल सकता हूं। माननीय सदस्य की जो चिंता केपिटल बाहर जाने की है, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि 50 करोड़ रुपया उनको पहले यहां as a deposit रखना पड़ेगा, before they want to set up a university. इसके बिना कोई यूनिवर्सिटी सेट-अप नहीं कर सकता है। दूसरी बात जो भी इन्वेस्टमेंट यहां होगी, वह हमारे कानून के अंतर्गत बाहर जा ही नहीं सकती है। जो भी मुनाफा कमाया जाएगा, 75 प्रतिशत वह मुनाफा वापिस यहां इन्वेस्ट होगा। माननीय सदस्य ने यशपाल समिति की बात कही है। मैं यशपाल समिति का उदाहरण दे कर यह बात पढ़ना चाहता हूं :

“But giving an open license to all and sundry carrying a foreign ownership tag to function like universities in India, most of them not even known to their own countries would only help them earn profit for their parent institutions located outside or accrue profit to the shareholders. If the best of foreign universities, say amongst the top 200 in the world, want to come here and work, they should be welcomed.”

This is Yash Pal Committee, जिसे माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं है। कहने का मतलब है कि हम उच्च स्तर की संस्थाएं लाना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी को मैंने छात्र जीवन से देश के बहुत बड़े वकील के रूप में जाना है और मंत्री के रूप में हम उम्मीद करते थे कि हमारे देश के अंदर गरीब, किसान, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनकी वकालत जरूर करेंगे। लेकिन मंत्री जी के उत्तर से न केवल मुझे, बल्कि मेरे जैसे तमाम नौजवान जो माननीय मंत्री जी के लिए दिल में बहुत सम्मान रखते हैं, उन्हें जरूर निराशा हुई होगी। हम मंत्री जी की इस बात से सहमत हैं कि शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है और शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता को ले कर न केवल केंद्र सरकार, बल्कि देश की विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने भी कई प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी है, जिसकी माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्न पूछने की भूमिका बहुत लम्बी होती है।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आज जितने भी प्राइवेट कालेज चल रहे हैं, चाहे किसी भी पाठ्यक्रम के हों, कहीं भी बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं हो पा रहा है। संविधान की प्रस्तावना में स्वीकार किया गया था कि हमारा देश समाजवादी राष्ट्र और लोक कल्याणकारी राष्ट्र बनेगा। लोक कल्याणकारी राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसी जरूरतों को केंद्र सरकार पूरी करे। क्या मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि वे लोक कल्याणकारी राष्ट्र के दायित्वों को नहीं निभा पा रहे हैं? इसके लिए उन्हें विदेशी लोगों की जरूरत पड़ रही है। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इसी सदन में पारित हुआ और आपसे पूर्व के मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने पुरजोर वकालत की थी कि प्राइवेट और विदेशी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण हो, चाहे वह दलितों का मामला हो, चाहे पिछड़ों का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों का मामला हो, चाहे गरीबों का मामला हो। क्या माननीय मंत्री जी विदेशी संस्थाओं को बाध्य करेंगे कि वे कम से कम पैसे में इन वर्गों के लोगों को शिक्षा देने का प्रावधान करें?

श्री कपिल सिब्बल : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार ने इन्क्लूसिव एजुकेशन एजेंडा को आगे किया है, तो हमारी सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने किया है...(व्यवधान)। मुझे बताइए हिन्दुस्तान...(व्यवधान) के इतिहास में...(व्यवधान)



अध्यक्ष महोदया : उनको उत्तर देने दीजिए। शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। अभी प्रश्न नहीं पूछिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

*(Interruptions) ... **

श्री कपिल सिब्बल : माननीय सदस्य ने जो चिंता माइनोंरिटी और गरीब के बारे में प्रकट की है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम उनसे ज्यादा चिंतित हैं। हम चाहते हैं...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) ... **

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदया, 90 प्रतिशत इंवेस्टमेंट शिक्षा के दायरे में प्रदेश करते हैं और अगर प्रदेश में डूनेशंस की व्यवस्था है तो आप अपने चीफ मिनिस्टर से पूछिए कि क्यों है क्योंकि यह ज्यादातर प्रदेशों में स्टेट यूनिवर्सिटीज द्वारा होता है। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें अपना उत्तर तो पूरा करने दीजिए। बीच में टोका-टाकी क्यों कर रहे हैं। रामकिशुन जी, बैठ जाइए। कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*(Interruptions) ... **

श्री कपिल सिब्बल : जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल जो अभी संसद में आएगा, उसके अन्तर्गत जो भी ट्रीटमेंट हम अपने इंस्टीट्यूशंस को देंगे, वैसा ही ट्रीटमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा।...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि मैकाले के नाती-पोतों को भी यहां बुला रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन आज की तारीख में हमारी जो टेक्नीकल एजुकेशन है, कहीं न कहीं प्राध्यापकों की कमी है और गुणवत्ता में कमी आती जा रही है। निजी कॉलेजों में शिक्षा शुल्क पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन सभी बातों से मंत्री जी वाकिफ हैं। उसके लिए आज भी नियम कानून हैं। आपने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। क्या इसकी कोई गारंटी है कि आपने जैसे कहा, विदेशों से यहां पर

* Not recorded.

संस्थान आएंगे कि ये संस्थान गुणवत्ता वाले ही संस्थान होंगे और कमर्शियल लुक-आउट वाले नहीं होंगे क्योंकि यहां भी वही बात हो रही है। लोकमान्य तिलक जी ने जब पहला शिक्षा संस्थान खोला था तो अपने हाथ से वहां प्रांगण में सफाई की थी। अपने सिर पर टाइपराइटर इत्यादि सामान उठाया था। यह हमारे यहां की भावना रही है। आज वह भावना नहीं रही है। यह बात भी सही है। हमारे यहां भी कमर्शियलाइजेशन हो रहा है लेकिन विदेशों से जो संस्थान आएंगे, वे हमारे हिन्दुस्तानियों पर प्रेम करते हुए यहां शिक्षा देने के लिए ही आएंगे, कमर्शियली नहीं आएंगे। क्या इसकी कोई गारंटी आप ले रहे हैं? मैं यह जानना चाहूंगी कि बजाए उसके हमारी जो अपनी संस्थाएं हैं, माननीय अटल जी ने हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्था हर राज्य में राष्ट्रीय स्तर की स्थापित की थी। उसके द्वारा हमारी शिक्षा संस्थाओं की भी गुणवत्ता बढ़ी। ऐसी संस्थाएं राज्य में एक के बजाए दो भी बढ़ें। क्या इस प्रकार की व्यवस्था पर माननीय मंत्री जी का कोई विश्वास है?

श्री कपिल सिब्बल : जो सवाल माननीय सदस्या ने पूछा कि क्या उच्च स्तर की संस्थाएं बाहर से आएंगी या नहीं आएंगी? उसके बारे में मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि उसकी चर्चा भी संसद में होगी।

क्योंकि जो नेशनल एक्क्रेडिटेशन एक्ट के अंतर्गत हमारी एक्क्रेडिटेशन अथॉरिटी है, उसके द्वारा वहां यह प्रावधान है कि यदि कोई भी बाहर की संस्था आये तो उसे एक्क्रेडिटेशन प्रोसेस पारित करना पड़ेगा और उसके बिना वह यहां कोई पाठशाला, यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम नहीं चला सकते। जैसे एक्क्रेडिटेशन अथॉरिटी हिंदुस्तान की संस्थाओं पर लागू होगी, वैसे ही एक्क्रेडिटेशन अथॉरिटी उन संस्थाओं पर लागू होगी। जब तक एक्क्रेडिटेशन प्रोसीजर सही नहीं होगा, तब तक उन संस्थाओं को यहां शिक्षा देने का कोई हक नहीं होगा।

जहां तक एआईसीटीई का सवाल है, आपको मालूम है कि हमारे लॉज हैं, रेगुलेशंस भी हैं। लेकिन उनके बावजूद हिंदुस्तान में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में खास तौर पर स्टेट्स में जो हो रहा है, वह हम सब जानते हैं। लॉ होने के बाद भी हम वहां कुछ नहीं कर पाये। इसीलिए हम पूरा सिस्टम रिफॉर्म कर रहे हैं। अब सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेन्ट होगा, वेबसाइट पर दिखाया जायेगा कि संस्था क्या दे सकती है, उनकी फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये सब प्रोसपेक्टस द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और यदि उसमें कोई बात गलत निकली *that will be treated as an educational malpractice*. उसके लिए हम दोबारा एक सैपरेट बिल ला रहे हैं। हम इन चीजों का ध्यान रखकर इन्हें ठीक करना चाहते हैं, उसमें यदि आपकी सहमति होगी तो यह सब ठीक होगा। परंतु यदि ऐसे ही बहस चलती रही कि किसी भी संस्था के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जितना हम कर रहे हैं, उतना शायद ही इतिहास में कभी किसी सरकार ने किया होगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

SHRI R. DHIRUVANARAYANA: Madam, I would like to ask the hon. Minister that State-wise how many foreign institutions will be sanctioned. Will it be State-wise or population-wise?

SHRI KAPIL SIBAL: It is neither State-wise nor population-wise. It depends on where the foreign institution wishes to come. Supposing the foreign institution wants to collaborate with the Central University, it is possible. Our Central laws will apply and the foreign university will collaborate. If it wants to collaborate with the State University, the State laws will apply and it will be entitled to collaborate. If it wants to set up a private unaided institution like our private unaided institution, those laws will apply, and where they want to set up is to be decided by the university and not by the Government of India.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Madam, there is no doubt that with quality education, the youth of India becomes its strength and not its burden. But if we look at the number of students who are going abroad every year, if it was 1,70,000 students in 2007, today it is over three lakhs. If I look at the global rankings of universities, in America there are approximately 168 universities that have made it to the top 500, 40 each in U.K. and Germany. Even our neighbouring country, China has 18 universities. But in India there are only three universities which have got into the top 500 ranking. On one side we are losing billions of dollars because of these students going abroad and through our students our money is going abroad. I would like to know what we are doing to our existing universities so that they also come into world ranking and we do not lose the best talents of our country to the foreign countries but on the other hand we attract those students from their countries to our country. So, what are we doing to the existing universities?

Madam, secondly there is another question related to this only.

MADAM SPEAKER: Thank you, just one question only.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Madam, a lot of our youth cannot make it to these top universities. They need technical and polytechnic kind of education also, vocational training. Well, in our country there are only 6,700 polytechnics providing technical education whereas in a country like China there are five lakhs, out of which three-and-a-half lakhs are in the rural areas. Today, the rural areas do not have a good college, forget about having a polytechnic. Is the Government going to do anything to look towards providing the rural youth also?

SHRI KAPIL SIBAL: I just want to inform the hon. Member that I have known of many instances where our children do not get into the IITs but get into MIT. So, this tells you that our present IITs may not be in the first 200 but the quality of students that go into our IITs may be better than the quality of students who go into MIT.... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें पूरा जवाब देने दीजिए। मंत्री जी, आप बोलिये।

SHRI KAPIL SIBAL: The hon. Member has mentioned about world ranking. The world rankings are based on certain criteria. Two of the major criteria in world rankings are firstly the number of foreign faculty teaching in those institutions and secondly how many foreign students are being taught in those institutions. These are the major criteria. As you know, we have none of those. That is why we are not in the top 200. But, if you take those away, we will be in the top 200.

As far as the rural areas are concerned, yes, it is this Government that is in fact talking to the States. Some of our Central Universities are in rural areas. Koraput is one example. The hon. Member from Orissa will know that we have set it up in Koraput. A Central University in Tamil Nadu is in a rural area. It is this Government that is giving a great thrust for investment in the rural areas. ... (*Interruptions*)

DR. RATNA DE : Entry of foreign educational institutions is welcome. But it should not scuttle the national academic institutions in our education sector. It should be ensured that it helps our education sector in getting vocational training and development of skill which would help Indian studies to know more about the global trend in the education sector. Has the hon. Minister set up a regulatory body in this regard to ensure that no second rate, poor quality or substandard foreign educational institutions are coming into the education sector in India?

SHRI KAPIL SIBAL: Two very important issues have been raised by the hon. Member; firstly, about vocational training. I would like to inform the hon. Member that the maximum investment that we are looking at is in the vocational areas, because in this country we lack para-medics, we lack para-legals, there are no air-conditioning engineers, there are no automobile engineers, there are no artisans, there are no people who are in the field of financial services at the lower end. Very little skill development experts are in this country. So, if you want to employ a workman in a particular area, he has no certification. A lot of the foreign investment is going to come into the vocational sector and the maximum will come. Hospitality services, tourism services are very important areas where there is no expertise in this country. The young people are looking for jobs. They do not want to become doctors or engineers. They want to embrace vocational training and get jobs and earn money for their families. We are in the process. We have so far denied them because we have never had a law in place. So, the hon. Member is absolutely right. We are going to set up a national vocational educational framework in this country within the next one year and we will have hundreds of skill development courses in the 10+2 sector so that children, when they pass out of Class 12, will actually be able to be employed. Please allow our youth these opportunities. Please do not oppose these opportunities for employment of our own kids. ... (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या यह मामूली सवाल है? हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद प्रोफ़ेसर रह चुके हैं। क्या हमारे यहां विद्वानों की कमी है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। श्री धर्मेन्द्र यादव जी का प्रश्न था जिस पर चर्चा हो चुकी है। अब आप बैठ जायें। We have moved..

श्री मुलायम सिंह यादव : देश में आईआईएम के लोग प्रोफ़ेसर बनकर गये हैं, ये क्या कर रहे हैं?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें. श्री धर्मेन्द्र यादव जी का प्रश्न था जिस पर विस्तार से चर्चा हो गयी है। मुलायम सिंह जी, इतना नाराज़ नहीं होते हैं, अगर आप ऐसे नाराज़ होंगे तो सदन कैसे चलेगा?... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ...*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप पूछेंगे, वह बतायेंगे।

* Not recorded.

(Q. No. 242)

श्री जयंत चौधरी: अध्यक्ष महोदया, एक प्रगतिशील और सभ्य समाज की नींव शिक्षा के माध्यम से रखी जा सकती है। आज हमारे देश में यही सब से बड़ी चुनौती है कि गरीब परिवार के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की खोज में जुटे हुये हैं।

उनका परिवार उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन वे वंचित रह जाते हैं। अनिवार्य और निशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम उसी दिशा में मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस कानून के क्रियान्वयन के एक पहलू पर मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। भारतीय संविधान में हमारे देश की परम्पराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं को पहचानते हुए, जातिगत आधार पर पीढ़ियों से जो शोषण हो रहा है, उसे समझते हुए, एससीएसटी और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है और आरक्षण दिया गया है। इस पहलू पर यह कानून शांत है। यहां तक कि इसमें एक विशेष श्रेणी बनायी है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की है। अच्छे कानूनों में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। यदि कहीं न कहीं इसे परिभाषित करते तो इसके दुरुपयोग की जो छूट स्थानीय एजेंसियों और राज्य सरकारों को मिल रही है, वह नहीं मिल पाती। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में भी आप 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोई वित्तीय सहायता आप उन संस्थानों को प्रदान करेंगे?

(श्री कपिल सिब्बल): इस कानून के अंतर्गत उन संस्थानों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है। हम अपने बच्चों पर जो खर्च करेंगे, उतना ही धन उन्हें भी दिया जाएगा। जहां तक एससीएसटी का सवाल है, इस एक्ट के तहत शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का संवैधानिक हक है। इसलिए हमने सोचा कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा तो इसमें आरक्षण का कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि एससीएसटी के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार होगा।

श्री जयंत चौधरी : अध्यक्ष महोदया, इस कानून के तहत वित्तीय संसाधनों की कमी को लेकर कुछ सवाल सामने आए हैं। राज्यों के मंत्रियों के साथ आपकी जो बैठक हुई, उसमें भी यह बात सामने आयी है। केन्द्र सरकार के मंत्रालय का अनुमान है कि 2,31,000 करोड़ रुपये का आउट-ले इसके लिए चाहिए और 2,7,000 करोड़ रुपये का भार प्रदेश सरकारों को वहन करना होगा। कमेटी या बोर्ड ने बताया है कि वर्ष 2009-10 के वर्ष में सर्वशिक्षा अभियान का 60-40 की शेयरिंग में भी अनुभव रहा है कि 14 प्रदेश ऐसे थे, जो कि डिफाल्टर थे। यहां तक कि जो पैसा दिया जाता है, कई प्रदेश वह भी खर्च नहीं कर पाते हैं। मैं इस संदर्भ में मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि कई प्रदेशों ने अपनी राय व्यक्त की है कि उनके पास

संसाधन नहीं है, विशेषकर बीमारू प्रदेशों की बात करें, जहां इसका क्रियान्वयन बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई नियम बना लें कि स्कूल में आप मूर्ति खड़ी कर सकते हैं, तो शायद प्रदेश सरकार में कुछ परिवर्तन सामने आए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और बिहार राज्य में प्रदेश सरकार सामने नहीं आ रही हैं तो उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज या सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार तैयार है?

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, 2,31,000 करोड़ रुपये अगले पांच साल में इस योजना के तहत आरटीए को दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र और राज्यों का शेयर 55 और 45 प्रतिशत है। अगले साल वह 50 प्रतिशत हो जाता है। चूंकि हम सर्व शिक्षा अभियान को आटीए के साथ एलाइन कर रहे हैं, इसलिए इस व्यवस्था की गंभीरता को सोचते हुए, सरकार ने यह तय किया है कि शेयरिंग पैटर्न 65 और 35 होगा, 65 प्रतिशत केन्द्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। लेकिन यह 65 और 35 नहीं है, एक्चुअली यह 68 और 32 है। यह इसलिए है क्योंकि 24 हजार करोड़ रुपये वित्त आयोग ने अलग से दिया है। 2,7,000 करोड़ का शेयरिंग 65 और 35 है। मेरे हिसाब से कुल मिलाकर शेयरिंग पैटर्न 68 और 32 बनता है। यह हम सभी राज्यों पर लागू करेंगे। लेकिन यूपी और बिहार को स्पेशल पैकेज देना मुमकिन नहीं है। सभी राज्यों को इसी पैटर्न के हिसाब से धन दिया जाएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। रघुवंश बाबू को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, देश में छः से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या लगभग 22 करोड़ है, जो स्कूल में जाते हैं और एक करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। शहर में बड़े लोगों के बच्चे प्ले स्कूल में तीन वर्ष से जाना शुरू कर देते हैं। सरकार के कानून में शिक्षा के अधिकार का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है और वह छः से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। हमारा सवाल यह है कि जो तीन वर्ष-चार वर्ष, पांच वर्ष और छः वर्ष तक के बच्चे हैं, जिनकी संख्या करीब आठ से दस करोड़ होगी, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? उनका कोई ख्याल नहीं किया गया है, ये छः के बाद राइट टू एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, यह मेरा पहला सवाल है।...(व्यवधान) मेरा दूसरा सवाल है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप एक ही सवाल पूछिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, राइट टू एजुकेशन का प्रश्न है। 22 करोड़ लड़कों के लिए 55 लाख शिक्षक चाहिए और स्वीकृत पद 46 लाख हैं। इनमें नौ लाख लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त ही नहीं की, वे

शिक्षा देने के योग्य ही नहीं हैं। सात लाख पद खाली हैं, पांच लाख पदों की और जरूरत है। मतलब, 31 लाख शिक्षकों की कमी है तो कैसे राइट टू एजुकेशन होगा?...(व्यवधान) यह जो सवाल उठा है कि दो लाख 33 हजार करोड़ रुपए चाहिए, 15 हजार करोड़ सालाना बजट है और 46 हजार करोड़ चाहिए। $15 \times 3 = 45$, जितना बजट है, ये कहते हैं कि 13वें वित्त आयोग का पैसा 24 हजार करोड़ रुपया राज्यों को गया है, उसे भी हम मान लेते हैं। वह भी पांच हजार करोड़ सालाना हुआ। 15 से पांच, बीस हजार करोड़ के बाद भी 26 हजार करोड़ रुपया सालाना जो डेफिसिट है, ये कहां से पूरा करेंगे? उसके बाद अल्पसंख्यक विद्यालयों, गरीब, पिछड़े और दलित संगठनों ने इनके यहां रिप्रेजेंट किया है। ये सारे सवाल हैं। राइट टू एजुकेशन केवल जुबानी जमा खर्च है, जहां शिक्षक और स्कूल नहीं रहेगा तो उन सब का क्या होगा?...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: The hon. Member is right. We will look at the practical side of all these issues.... *(Interruptions)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यह बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर सदन में चर्चा कराई जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप नोटिस दे दीजिए, हम इस पर चर्चा करा देंगे।

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदया, देश के अनेक प्रदेशों में विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-काश्मीर के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कुछ बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिन्हें ड्रॉप आउट्स कहते हैं, ऐसे बच्चों को रोकने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल: यह बहुत गंभीर समस्या है और यह बात बिल्कुल सही है कि जब तक बच्चा पांचवी, छठी तक पहुंचता है तो वह ड्रॉप आउट कर जाता है। उसकी वजह क्या है, उसके बारे में गंभीर खयाल किया जा रहा है। हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत सोच रहे हैं कि सभी बच्चों को स्कूल भेजना लाज़िमी है। इसीलिए हमने जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां बनाई हैं, उनमें 75 प्रतिशत लोग लोकैलिटी के होंगे। जिस मां का बच्चा स्कूल जाता है, वह मैनेजमेंट कमेटी में होगी ताकि जो ऑनरशिप है, वह कम्युनिटी की हो और जब ऑनरशिप कम्युनिटी की होगी तो जिस बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, वह खुद हमें बताएगी कि इस बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है।

इस तरह से इस व्यवस्था को हम ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में ऐसी कितनी मां हैं, जो उस कमेटी की मैम्बर होंगी ?

श्री कपिल सिब्बल : अरे भाई, मां की बात नहीं, बाप की बात हो रही है।

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

... (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : केवल मां की बात नहीं हो रही है, बल्कि बाप की भी बात हो रही है। ... (व्यवधान)

SHRI DUSHYANT SINGH : Madam, I would like to ask this, through you, from the hon. Minister. The hon. Minister has mentioned that the Government of India's stake is 68 per cent, and 32 per cent comes from the State Government. How is the Government going to assist the State Governments when they themselves have mentioned to you by writing letters that they do not have funds available with them? Apart from that, they cannot carry on with your 6-14 age group students going to school and helping them out. What is the Government going to do about it?

Is the Government fixing a norm for student-teacher ratio in far-off areas? As mentioned by a hon. Member earlier that you do not have teachers available to teach. How are you going to carry on with this project?

SHRI KAPIL SIBAL : Madam, the hon. Member has put many questions into one question. The first question that he has asked was as to what the Chief Ministers have written. Yes, several Chief Ministers have written that : "We need 100 per cent and we cannot contribute anything." Most of them have written that : "We need 90 per cent." Now, it is not possible for the Government of India to fund the entire RTE with 90 per cent contribution. So, you must take a practical view of this issue.

The Finance Minister, at several times, has said that : "The States on any given day have surpluses in their Budgets." There was a time when there were deficit States, but today most of the State Budgets have surpluses. So, I think that efforts should be made by the State Governments too. Please remember that this is

not a State-Centre issue. This is a National issue. You want your children to be educated and so does every parent. ... (*Interruptions*) So, everybody will have to make an effort in this. If you say that : “No, the Central Government must give 100 per cent and that we are not going to make any effort”, then it is not going to work. ... (*Interruptions*) Therefore, it is clear that we have done the maximum possible. In fact, the Finance Minister has been exceptionally kind to give Rs. 2,31,000 crore for this. I am thankful to the Finance Minister. Now, the States must also contribute in this.

As far as the student-teacher ratio is concerned, the Act provides for a 30:1 ratio, that is, one teacher for 30 students and this will apply to rural areas as well. In fact, the Act provides that we will have a school -- where the population of children in the rural areas is dispersed -- and give transportation facility to the children for them to actually be able to go to that school, which will be borne by us. All these provisions are there in the Act itself.

As far as the teachers are concerned, this is a very big issue. We are asking the State Governments to recruit more teachers. Many States have started the process. I have to tell you that no matter what might be said in this hon. House, every State Education Minister has come to me and said that : “We accept; we are willing to collaborate with you; and we want to move forward with you.”

(Q. No.243)

MADAM SPEAKER: Shri S. Alagiri -- not present.

Shri Ramashanker Rajbhar

श्री रमाशंकर राजभर : अध्यक्ष महोदया, मुझे प्रश्न पूछने के लिए समय देने हेतु मैं आपका आभारी हूँ।

महोदया, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पशुओं पर यदि क्रूरता होती है, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास कानून हैं। जब से ट्रैक्टर आया है, तब से यदि गाय के बछिया पैदा होती है, तो उसकी सेवा होती है, लेकिन अगर बछड़ा पैदा होता है, तो यह सोचा जाता है कि उसे जल्दी निकालो, क्योंकि अब देश के कई भागों में किसान अपनी जमीन को बैलों से नहीं जोतते, इसलिए उसे निकालने की बात सोची जाती है। इसी प्रकार भैंस के अगर बच्चा हुआ और अगर पड़िया पैदा हो गई, तो भैंस बनाना है, इसलिए उसे पालो और बड़ी करो। अगर पड़ा पैदा हो गया, तो उसे मार कर उसकी खाल में भूसा भरा जा रहा है। भैंस को इंजेक्शन लगाकर उसके सामने मरे और भूसा भरे हुए पड़े को रख कर दूध निकाला जा रहा है। कुछ लोग उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं और वे पशु आवासा पशुओं के रूप में घूमते रहते हैं और उनके इधर-उधर भागने के कारण कई बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिनमें लोगों की कई टांगें तक टूट जाती है। पशुओं पर जो इस तरह की क्रूरता हो रही है, उसके लिए आपके पास अधिनियम भी है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में अभी तक कितने ऐसे कृत्य करने वालों पर कार्रवाई हुई?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, as the hon. Member has acknowledged, we have the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. We set up an Animal Welfare Board in 1962. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उनका उत्तर सुनिये।

SHRI JAIRAM RAMESH: We have an elaborate legal network and an institutional network for implementing both the law as well as the rules that have been enacted under the law. Madam, there is the Animal Welfare Board of India, the State Prevention of Cruelty to Animals Authorities, and every district has also been asked to set up these institutional authorities. It is not humanly possible in our country for a Central Government alone to implement this Act and these rules.

It is only when we get the full cooperation of the States, when we get the full cooperation of the civic authorities that we will be able to implement this law.

As far as the specific question on the number of actions taken, the number of cases registered, Madam Speaker, I will have to get back to the hon. Member.

अध्यक्ष महोदया : दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री रमाशंकर राजभर : अध्यक्ष महोदया, पहले प्रश्न का जो उत्तर आया, इससे तो सदन अवगत हो ही गया। मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के पशुओं का इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर है? जो बड़े शहर हैं या गांव हैं, जहां पर आवारा पशु मानकर जो घूम रहे हैं और बीमार पड़कर जो कराह रहे हैं, माननीय मंत्री जी उन पशुओं के इलाज के लिए क्या कोई इन्तजाम करेंगे?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, through the Animal Welfare Board of India, there are 2,800 NGOs ... (*Interruptions*) Madam Speaker, I cannot answer if I am going to be interrupted, however senior the Members are. This cross-talk is very, very distracting, Madam.

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए। यह पशुओं पर क्रूरता का मामला है, बहुत संवेदनशील है। आप ध्यान से सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : माननीय सदस्य हिन्दी में उत्तर जानना चाह रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री जयराम रमेश: नहीं, वे यह नहीं कह रहे हैं, वे और कुछ कह रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इस पर मुझे भी पूछने दीजिए। यह हमारे क्षेत्र का मामला है।... (व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, the Animal Welfare Board of India has registered 2,800 NGOs on its books out of which something like 1700 are *Goshalas*. These are run by various institutions and the purpose of these *Goshalas* which are all across the country is precisely to take care of migrant, roaming, unacknowledged animals which you see on the streets. The purpose of these *Goshalas* is to provide a home largely, of course, to cattle. There are animals which are migrant animals which are also part of the *Goshala* network. So, to the Animal Welfare Board of India, every year, we provide about Rs. 13 crore by way

of Plan and non-Plan support through the Ministry of Environment and Forests, and it is through these NGOs, this network of 2,800 NGOs and 1700 *Goshalas* that the problem of stray animals particularly cattle is being adhered to.

I entirely accept the fact that in spite of all these, there are still visible cases of cruelty, and as I mentioned to you, Madam Speaker, we have the laws, and we have to ensure the implementation of these laws. There are organized cases of cruelty, and I want to mention here that in many States, for example, bull-fighting is an accepted cultural practice. On the 4th of December, 2009, this very House debated a Private Members' Resolution on allowing bull-fighting in the State of Goa, and I rejected that demand from the Private Member.

Similarly, the Tamil Nadu Government has the *jallikattu* cultural practice. Now, my Ministry has gone to the Supreme Court and has asked for a ban on this practice of *jallikattu*. The Tamil Nadu Legislative Assembly has passed guidelines to regulate this practice.

So, I think, Madam Speaker, it is not just a question of my Ministry or the Animal Welfare Board assuming responsibility. Unless the State Governments also play their role, we are going to continue to see cruelty to animals.

SHRI N.S.V. CHITTHAN : As the hon. Minister has stated just now, in Tamil Nadu, bull-fighting is commonly called as *jallikattu* and it is being celebrated every year during the festival of harvest. Thousands of youth with strength and valour participate in the game of heroism and deed. From time immemorial, it is being celebrated throughout Tamil Nadu. Madam, it cannot be treated as cruelty to animals. May I ask the hon. Minister, through you, whether the Government will take appropriate steps to continue this practice in Tamil Nadu? If there is a will, there is a way.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, my position on this, I would like to make it absolutely clear. Not every cultural practice is sustainable; not every cultural practice should be continued with in the modern day era, and *jallikattu* happens to be one of the practices of cruelty to animals... (*Interruptions*)

SHRI N.S.V. CHITTHAN : It cannot be treated as cruelty to animals.

SHRI JAIRAM RAMESH: It has also seen the death of human beings and that is why the Animal Welfare Board moved the Supreme Court in 2007 to ban *jallikattu*. Now, in response to this, the Tamil Nadu Legislative Assembly passed regulations. I do not believe that regulations are the answer. The bull-fighting in Spain – Spain is associated with bull-fighting – the Catalonia Province of Spain has banned bull-fighting, and I see no reason why Tamil Nadu cannot ban *jallikattu*.

SHRIMATI MANEKA GANDHI : Actually, I have hundreds of questions, but I will stick to two really important points.

The Prevention of Cruelty to Animals Act was made in 1960, and the importance of this Act was recognized by Pandit Jawaharlal Nehru. It has been the only Private Members' Bill ever accepted by the Government. The House made a fine, which was a very, very serious fine for animal cruelty. In those days, when my father earned Rs. 1,200 as a Colonel in the Army, the fine for a single act of cruelty was Rs. 50. Today Rs. 50 is meaningless, but it has not been revised from 1960 till now. I would request you to change the Prevention of Cruelty to Animals Act, amend it to make it modern. It is the only Act in the country in which every single day, there are about 1,000 to 2,000 cases, but every single person caught for cruelty, it is the only Act which they plead guilty because if they say 'not guilty', the case goes on for ever; if they plead 'guilty', they pay Rs. 50 and they are out. So, we have the same offenders every night.

My colleague talked about cows being taken for slaughter every night. Every single night, I have caught between four to five trucks somewhere in India. In every case, they have got away with Rs. 50. So, I would like to know whether

your Government would bring in amendments to the Act to make the fines or the punishments more severe.

The second thing is animal sacrifice is an organized crime. It is done in many, many villages; it is now nearing Dussehra and it becomes really impossible, especially with the Army also involved and doing it all over the place. Could you please let us know whether you intend to ban animal sacrifice? It is banned in six States. Why can it not be banned all over India?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, the hon. Member is right, I am well aware of the historic importance of the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960, which is the contribution of Rukmini Devi Arundale to the legislation of our country. I am also conscious of the fact that the hon. Member is the Chairman of the Committee on Assurances. So, I should be very careful when I say anything lest she construe it as an assurance. But I do want to say to the hon. Member that the amendment to the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 is very much on our agenda. We would like to come forward with actually a comprehensive Animal Welfare Act, not just a Prevention of Cruelty to Animals Act, with steep penalties because the penalties today, under the 1960 legislation, is very, very laughable.

If this is construed as an assurance, this is an assurance and we will come forward with this legislation.

As far as the second question is concerned, the hon. Member is right that a number of States have, in fact, banned animal sacrifices in religious places. This is a sensitive issue. I would like to proceed with this with some caution because this is an issue that affects a large number of States. All I can say, at this stage, is that we will, from the Ministry of Environment and Forests, on behalf of the Animal Welfare Board, certainly send an advisory to all the States to emulate the States which have already banned animal sacrifices. This much I can assure the hon. Member.

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आप गवाह हैं कि एशिया का सबसे बड़े पशु मेला सोनपुर में...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : वह सबसे बड़ा इललीगल मेला है।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : वहां एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद दी, आप जल्दी प्रश्न पूछिए क्योंकि समय कम है और मंत्री जी को उत्तर भी देना है।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मेनका जी ने जवाब दे दिया है कि वह इललीगल मेला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : फिर आप क्या पूछ रहे हैं? आप प्रश्न जल्दी पूछ लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : वह देश का सबसे बड़ा मेला है। गंगा स्नान के अवसर पर देश के हर कोने से लोग हाथी, घोड़े, सूगा, गाय, भैंस आदि लेकर आते हैं और खरीद-बिक्री करते हैं।...(व्यवधान) ऊंट भी आते हैं।...(व्यवधान) महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एनीमल क्रुएलिटी के मामले में कल्याण बोर्ड किस शासन में बना है?...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : क्या उसमें गधा भी आता है?...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : गधा, घोड़ा आता है या नहीं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी से प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि उसे बनाने वाले कौन लोग थे और वह किनके इंस्टांस से बना? हम हरियाणा, पंजाब से गाय ले जाते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया है।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : रास्ते में क्रुएलिटी के नाम पर सारे पशुओं को छीन लिया जाता है। यह देश के बड़े तबके के पेट पर लात मारी गई है। मुझे बताया गया है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने खर्सी काटने पर भी रोक लगा दी है, बकरा काटने पर भी रोक लगा दी है। इस देश में क्या हो रहा है? इसलिए आप इस

कल्याण बोर्ड को रिव्यू कीजिए और बताइए। ...(व्यवधान) देश में सर्कस चलाने वाले लोग बेकार हो गए हैं। देश में सारे लोग बेकार पड़े हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई है। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : जिन्हें पशुओं से कुछ लेना-देना नहीं है, वे गाय, भैंस पर रोक लगाकर बड़े हमदर्द बने हुए हैं।...(व्यवधान)

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, I bow to the hon. Member's superior wisdom on matters relating to the animal kingdom. All I can say is that I am very conscious of the impact that the Sonpur Mela is having on the manner in which elephants particularly are treated. This is a matter of shame for all of us. One animal that is associated with Indian culture is the elephant and the manner in which elephant's are being traded illegally and the manner in which elephants are being treated in different parts of the country is a matter that should cause great concern to us. The Ministry of Environment and Forests has set up an Expert Group on Project Elephant. I am expecting the Report of this Group by the end of this month. One of the areas that I have asked them to look at is the future of Sonpur Mela because I think, as long as the Sonpur Mela remains, we are going to have this problem of elephant's trade with all its attendant consequences across the country. The manner in which elephants are treated privately and, if I may say so, with the greatest of respect to all the *Bhakts* in the House, the manner in which elephants are treated in some of the most sacred temples of our country, is a matter of great shame for all of us.

MADAM SPEAKER: Shri Jaswant Singh. I am afraid we just have one minute.

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदया, समय नहीं है इसलिए मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

MADAM SPEAKER: The Question Hour is over.

12.00 hrs.

**RE: FINANCIAL ASSISTANCE
TO THE VICTIMS OF CLOUDBURST AT LEH, JAMMU AND KASHMIR
FROM MP LOCAL AREA DEVELOPMENT FUND**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam Speaker, yesterday on behalf of the House you made a reference to the untold misery that was heaped upon the people of Leh as a result of the cloudburst there and you empathized with the families on behalf of the House and the Nation as such. In response to that, I would take this opportunity to suggest that out of the MP Local Area Development Fund, each one of us donates at least Rs.20 lakh for that. Though no amount of financial assistance would be adequate to compensate them for the human loss that they have suffered, a minimum of Rs.20 lakh we all can contribute to that. ... (*Interruptions*) Madam, you may kindly mention the Members in a letter from your side. Giving the details of that could be enough.

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Environment (Protection) Third (Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 485(E) in Gazette of India dated the 9th June, 2010, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 2819/15/10)

- (2)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 2008-2009.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 2820/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

- (1)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2008-2009.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2821/15/10)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2008-2009.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2008-2009.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2822/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Malaviya National Institute of Technology, Jaipur, for the year 2008-2009.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Malaviya National Institute of Technology, Jaipur, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2823/15/10)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2824/15/10)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2007-2008.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2008-2009.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 2825/15/10)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Agartala, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Agartala, for the year 2007-2008.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.
- (Placed in Library, See No. LT 2826/15/10)
- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Raipur, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Raipur, for the year 2007-2008.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.
- (Placed in Library, See No. LT 2827/15/10)
- (11) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.
- (Placed in Library, See No. LT 2828/15/10)
-

12.02 hrs

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA***

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

- (i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Trade Marks (Amendment) Bill, 2009, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th December, 2009, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 10th August, 2010, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, **for** the word "Sixtieth" the word "Sixty-first" be **substituted**.

CLAUSE-1

2. That at page 1, line 2, **for** the figure "2009" the figure "2010" be **substituted**.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

- (ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct **of** Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jharkhand Appropriation **Bill**, 2010, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th August, 2010 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

2. Sir, I lay on the Table the Trade Marks (Amendment) Bill, 2010, as returned by Rajya Sabha with amendments on the 10th August, 2010.

* Laid on the Table.

12.02 ¼ hrs.

**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES
9th Report**

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): I beg to present the Ninth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Communications and Information Technology on “Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-seventh Report (Fourteenth Lok Sabha) on – Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)”.

12.02 ½ hrs.

**STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
(i)46th Report**

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): I beg to lay on the Table the Forty-sixth Report of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010.

(ii)Evidence

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): I beg to lay on the Table the Evidence tendered before the Committee on the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010.

12.03 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on "Constraints being faced by Kendriya Bhandar", pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN):

Sir, with your permission I beg to lay a Statement on the Table of the House which indicates the status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on "Constraints being faced by Kendriya Bhandar" pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2829/15/10.

12.03 ½ hrs.**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 928 DATED 25.11.2009 REGARDING EDUCATION CESS ALONGWITH THE REASONS FOR DELAY***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Sir, with your permission, I would beg to lay on the Table of the House a statement correcting the reply given on the 25th November, 2009 to the Unstarred Question No.928 by Shri Jai Prakash Agarwal regarding Education Cess, along with the reasons or delay in correcting the reply.

"The details of Education Cess collected by the Government during last three years are given below:

Year	Primary Education Cess		Secondary & Higher Education Cess		Total Education Cess	
	On Direct Taxes	On Indirect Taxes	On Direct Taxes	On Indirect Taxes	Direct Taxes	! On On Indirect Taxes
2006-07	4395.23	5568	-		4395.23	5568
2007-08*	5977.86	6210	2978.90	1 2895	8956.76	9105
2008-09	6652.30	1 6171	3200.92	2659	9853.22	8830
2009-10 (Budget Estimates)	7400.00	1 5560	3700.00	2780	11100.00	8340

Secondary & Higher Education Cess was introduced w.e.f. 1.4.2007

Education Cess is not a part of the net proceeds of the divisible pool of sharable taxes based on constitutional provisions and as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission. The proceeds of 2% Education Cess for primary education credited into a non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) are utilized exclusively for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Mid-Day Meal (MDM) Scheme. Expenditure on SSA and MDM Scheme is incurred from PSK after the funds provided by way of Gross Budgetary Support (GBS) are fully utilized. No specified allocation is made separately to States/UTs against the amount collected through Education Cess. Assistance under PSK is released to States/UTs as per the schematic pattern and budgetary allocation for SSA and MDM Scheme. Regarding

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1830/15/10.

1% additional cess for Secondary & Higher Education, only Gross Budgetary Support is provided to Department of Higher Education (HE) to meet its budgetary requirement & no separate allocation is made from the funds generated from this 1% additional cess."

The Correcting Statement has been necessitated due to inadvertent error in the answer of Unstarred Question No. 928 dated 25th November, 2009.

Reasons for Delay. The correcting reply could not be carried out during the previous session due to late receipt of complete reply from the concerned departments.

The error is regretted.

12.04 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (RAILWAYS), 2010-11

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIAPPA): Sir, on behalf of Kumari Mamata Banerjee, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 2010-11.

12.04 ½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today who are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within twenty minutes. Only those matters will be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to review the New Exploration Licensing Policy and bring the functioning of Production Sharing Contract (PSC) under the control of CAG to check the possibility of irregularities in accounting

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): प्रकृति द्वारा संरक्षित तेल एवं प्राकृतिक गैस राष्ट्र की संपदा हैं। देश की राष्ट्रीय संपदा का लाभ इस देश के सौ करोड़ से ऊपर भारतीय पाने के असली हकदार हैं।

वर्ष 2000 में सरकार द्वारा बनाई गई नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) में व्यय का लेखा-जोखा संवैधानिक संस्था (सीएजी) द्वारा कराए जाने से बाध्यकारी नहीं बनाया गया।

नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण हेतु आज तक 85 उत्पाद हिस्सेदारी संविदाएं सरकार द्वारा निजी कंपनियों से की गई हैं। इस उत्पाद हिस्सेदारी संविदाओं का व्यय में प्रयुक्त होने वाली धनराशि लाखों करोड़ रूपयों में है।

राष्ट्रीय संपदा से संबंधित इस उत्पाद हिस्सेदारी संविदा के लेखा व्यय की परीक्षा के प्रावधान को संवैधानिक संस्था सीएजी की परिधि में नहीं रखना लाखों हजार करोड़ रूपए की इस संविदाओं में भारी अनियमितताओं की संभवनाओं को जन्म देता है।

मेरा आग्रह है कि सरकार की पारदर्शिता नीति की अवधारणा को संरक्षित रखने हेतु देश की राष्ट्रीय संपदा निजी कंपनियों के हित साधन के स्थान पर इस देश के करोड़ों आम नागरिकों का हित साधन कर सके इसके लिए सरकार तत्काल उत्पाद हिस्सेदारी संविदा के लेखा परीक्षा के प्रावधानों में संशोधन कर इसके लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप से संवैधानिक संस्था सीएजी की परिधि में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to declare Kalagarh as a Revenue region of Uttarakhand and transfer the land of Kalagarh region from the Government of Uttar Pradesh to the Department of Irrigation, Uttarakhand

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान कालागढ़ क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। कालागढ़ क्षेत्र का विकास रामगंगा नदी परियोजना के अंतर्गत 1960 के दशक में हुआ है, वर्तमान में यह क्षेत्र जनपद पौड़ी में कोटद्वार तहसील के अंतर्गत दुगड़डा ब्लाक की स्नेह पट्टी के अंतर्गत विस्तृत है। यहां की लगभग 4-5 हजार आबादी विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार तथा लोक-सभा क्षेत्र गढ़वाल के प्रतिनिधित्व में संचालित है।

कालागढ़ क्षेत्र की मुख्य समस्या यह है कि यह (कालागढ़) न तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और न ही किसी नगर पालिका/नगर क्षेत्र का हिस्सा बन पाया है। 1961 में कालागढ़ क्षेत्र में रामगंगा परियोजना के निर्माण की स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग से सिंचाई विभाग को लगभग 22235 एकड़ भूमि कुछ शर्तों के साथ स्थानांतरित कर दी, जोकि 99 साल के पट्टे पर है। उक्त लगभग 22235 एकड़ भूमि में से लगभग 20122 एकड़ भूमि जलाशय, लगभग 1259 एकड़ भूमि कार्यस्थल, सड़क आदि तथा 855 एकड़ भूमि कालोनियों, छात्रावास कार्यालय, कच्चे एवं पक्के बाजार, स्कूल, कालेज, चिकित्सालय, ट्रेजरी, बैंक, पोस्ट आफिस, कलब्स, स्टोर्स, वर्कशाप, पुलिस स्टेशन, नलकूप, हैलीपैडस आदि टाउनशिप के लिए वन विभाग से सिंचाई विभाग को स्थानांतरित की गई। टाउनशिप के लिए स्वीकृत लगभग 855 एकड़ भूमि में से लगभग 37 एकड़ भूमि की जरूरत सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बताई गई है।

शेष लगभग 491 एकड़ भूमि में से 448 एकड़ भूमि अब वन विभाग को वापस जा चुकी है। शेष 43 एकड़ भूमि वापस की जानी शेष है। लेकिन कालागढ़ निवासियों द्वारा इस पर ऐतराज किया जा रहा है, क्योंकि इसी भूमि पर कालागढ़ निवासियों की कालोनी, उत्तराखण्ड सरकार के कार्मिकों के आवास, स्कूल, चिकित्सालय एवं बाजार आदि का निर्माण होना है। वैसे भी अब जब उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आ चुका है और इस भूमि की लीज भी अभी 2060 तक है तो उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वह भूमि को वन विभाग को वापस करे।

कालागढ़ क्षेत्र के निवासियों का ऐतराज जायज है तथा यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक गलत फैसला है कि भूमि वन विभाग को वापस की जाये। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह कालागढ़ क्षेत्र को वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार को दिशानिर्देश दे तथा यह भूमि

सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन को वापस दे जिससे वहां के निवासियों के विकास के लिए आवास, स्कूल, चिकित्सालय एवं बाजार का निर्माण हो सके ।

(iii) Need to constitute a Board to ensure checking of soil erosion in various districts along the rivers Ganga and Bhagirathi in West Bengal

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The districts in West Bengal along the banks of river Ganga/Bhagirathi have been under constant threat of erosion. Many a historical places are also becoming vulnerable due to the perpetual erosion.

Central Government in the current year's budget took a serious note on this problem and announced the same in the budget document. The State Government does not have the requisite infrastructure even to execute the anti-erosion works as it is a stupendous job involving men and money.

But the situation does not permit any delay. Therefore, I would urge upon the Government to constitute one board as similar as Bharamputra so that the anti-erosion works could be done in a dedicated manner.

(iv) Need to adopt a uniform procedure by University Grants Commission for admission of students in colleges of Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों के स्कूलों में 22 करोड़ बच्चे पढ़ने जाते हैं जिसमें केवल 40 प्रतिशत बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 40 लाख बच्चे ही कालेज स्तर तक की शिक्षा के लिए पहुंच पाते हैं केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि सन 2020 तक देश में 30 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालय पहुंच जाएंगे। जबकि अभी केवल 12.4 प्रतिशत ही कालेज एवं विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी 500 विश्वविद्यालय एवं 25,000 महाविद्यालय हैं, जबकि चार करोड़ 60 लाख बच्चों को कालेज की शिक्षा के लिए 800 विश्वविद्यालय एवं 45 से 40 हजार डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता है। आज देश में राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में कक्षा संचालन के लिए 107 छात्रों को ही मान्यता दी जा रही है जबकि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों जैसे कानपुर में 560, लखनऊ विश्वविद्यालय में 420, पूर्वांचल में 360 सीटें एवं अवध विश्वविद्यालय में 360 सीटें प्रदान की जा रही है जबकि उपरोक्त सीटों के अन्तर को समाप्त करके प्रत्येक विश्वविद्यालय की सीटों के आवंटन में यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा एकरूपता कायम करने का निर्णय लेना चाहिए। यू0जी0सी0 के इस निर्णय से देश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का अधिक अवसर मिलेगा तथा एकरूपता आयेगी।

(v) Need to take steps to make the river Yamuna pollution free

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): राजधानी दिल्ली में इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल होने हैं, जिस कारण इस वर्ष बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है। लेकिन राजधानी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी की स्थिति अत्यन्त ही बदतर है। यमुना की सफाई पर आज तक अरबों रुपया व्यय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यमुना प्रदूषित है। यमुना में 70 प्रतिशत प्रदूषण देश की राजधानी से हो रहा है, जबकि बाकी जिन शहरों से यमुना गुजरती है, उनमें से केवल 30 प्रतिशत से ही यमुना मैली होती है। स्थिति यह है कि राजधानी दिल्ली में यमुना वजीराबाद से लेकर दक्षिण में ओखला बैराज तक 22 कि.मी. के रेंज में प्रदूषित होकर नाले में परिवर्तित हो चुकी है। यमुना में 17 बड़े नाले गिरते हैं। इनमें सबसे ज्यादा गंदगी नजफगढ़ व शाहदरा ड्रेन से होती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यमुना में लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण इस समय यमुना में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) 41 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि मानकों के मुताबिक बीओडी लेवल 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले कुल कॉलीफॉर्म की संख्या 100 मिलीलीटर पानी में 5 हजार से कम ही रहनी चाहिए। इन्हीं के कारण यमुना में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजधानी दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी को प्रदूषण रहित बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए।

(vi) Need to take steps for proper storage of foodgrains in the country

श्री महेश जोशी (जयपुर): प्रकाशित रिपोर्ट्स के आधार पर मालूम हुआ है कि हमारे देश में कई जगहों पर खासतौर पर उत्तरी भारत में खाद्य भंडारण का तरीका ठीक नहीं है या इसमें लापरवाही बरती जा रही है। आज कई स्थानों पर हमारा अनाज खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। इस मानसून सीजन के बाद इसमें से आधे से ज्यादा अनाज सड़ जायेगा और ये पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहेगा। कई जगहों पर यह भी देखने में आया है कि गोदामों में पेयजल की बोतलें रखी हई हैं और अनाज बाहर सड़ रहा है। जिन अधिकारियों और संस्थाओं ने ऐसा कार्य किया हुआ है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो।

इस विषय में मैं कुछ सुझाव और देना चाहता हूं। अनाज को साधारण बोरियों में भरने की बजाए पोलीथीन की बोरियों में भरा जाए ताकि अनाज नमी की वजह से खराब न हो। पक्के गोदाम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाए जाएं जिससे की भंडारण की समस्या उत्पन्न ना हो। अगर हमारे पास गोदामों की कमी हो तो हमें कोशिश करके निजी क्षेत्र के गोदामों को किराये पर लेना चाहिए। सरकारी एजेंसियों की कोशिश रहनी चाहिए कि एक भी बोनी अनाज खुले आसमान के नीचे न रखा जाए ताकि अनाज को सड़ने से बचाया जा सके। यदि अनाज अतिरिक्त मात्रा में हो तो उसे गरीबों में बांटने में भी किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए।

**(vii) Need to make the B.S.N.L landline service more attractive for the customers
with a view to check the decline in the number of B.S.N.L. landline users**

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारी प्रगति हो रही है, लेकिन आज भी लैंड लाइन फोन का महत्व बना हुआ है। आज दूर संचार के क्षेत्र में सरकारी कम्पनी बीएसएनएल के साथ निजी कम्पनियां भी प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन बीएसएनएल का रूख उपेक्षा का दिखाइ दे रहा है। आज देश में मोबाइल के प्रतिस्पर्धा के चलते मोबाइल के काल दरों में काफी कमी आई, इससे मोबाइल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में फैल गया। इसकी पहुंच आम आदमी तक हो गई है। लेकिन आज लैंड लाइन की दरों में कोई कमी नहीं की गई है। उस क्षेत्र की निजी कम्पनियां सस्ती दरों में लैंड लाइन उपलब्ध कराकर बीएसएनएल से उसका व्यवसाय छीन रहीं हैं। बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्र के लैंड लाइन उपभोक्ताओं को सस्ती सेवा देने के नाम पर थोड़ी कटौती की, मगर शहरों और महानगरों में क्रमशः 120 रुपये प्रतिमाह और 50 कॉल मुफ्त और महानगरों में यह बढ़कर 165 रुपये प्रतिमाह किया गया। अन्य कोई रियायत भी नहीं दी जा रही, इसमें टैक्स को जोड़ा जा रहा है। आज दूरसंचार साधनों का महत्व बढ़ा है। शहरों से देशभर में काल करने के लिए एसटीडी की दरें कम करने की आवश्यकता होते हुए भी बीएसएनएल ने इसे कम नहीं किया। अगस्त 2008 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक योजना के द्वारा मासिक शुल्क 20 रुपये और 250 भरकर 2 साल बिना शुल्क और एसटीडी एक रुपया रखा। बीएसएनएल को दूरसंचार क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखना है तो उसे और प्रतिस्पर्धा बनाना होगा। लैंड लाइन के कम हो रहे उपभोक्ताओं को फिर से जोड़ने के लिए ग्रामीण -शहरी भेद खत्म कर सभी की दरें समाप्त करें तथा लैंड लाइन उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक रियायतें देकर उन्हें लैंडलाइन कायम रखने में सुविधा दे, इससे बीएसएनएल के बंद पड़े कनेक्शन पुनः शुरू हो सकते हैं। मैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से आपके माध्यम से उपरोक्त अनुसार तत्काल कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

(viii) Need to release funds for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in Madhya Pradesh and also accord approval to the proposals sent by the State Government

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत 15 हजार कि०मी० सड़कों का निर्माण का कार्य चल रहा है लेकिन अक्टूबर, 2009 से केन्द्र सरकार द्वारा धन आबंटन नहीं किया गया। इतना ही नहीं जो सड़क निर्माण के प्रस्ताव राज्य शासन ने स्वीकृति हेतु भेजे थे, उन्हें भी बिना कोई कारण बताये वापस कर दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। मध्य प्रदेश देश में उन प्रमुख राज्यों में से एक है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक तरफ केन्द्र सरकार दावा कर रही है कि प्रतिदिन 20 कि०मी० सड़कों का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि नहीं दी जा रही है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल मध्य प्रदेश को सड़कों के निर्माण की बकाया राशि का भुगतान किया जाये एवं भेजे गये नये प्रस्तावों की स्वीकृति दी जाये।

(ix) Need to enact a legislation for proper disposal and recycling of electronic wastes in the country

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): देश में इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे और उनकी अवैध तरीके से रिसाइकलिंग से पर्यावरण कुप्रभावित हो रहा है। भारत में ई कचरे के निस्तारण की कोई चार-चौबंद व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यापारी इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को तोड़ कर उनमें मौजूद तत्व निकलते हैं। इस रिसाइकलिंग से जुड़े मजदूर न तो दस्ताने पहनते हैं न ही उनके मुंह पर कोई मास्क होता है। इस तरीके से निस्तारण में मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, जिनका असर पेड़-पौधों, प्राणी और मानव जाति पर पड़ रहा है। खतरनाक रासायनिक तत्व भूजल पर भी असर डालते हैं। ई-कचरे से हुए परिणाम से कोई भी अनजान नहीं है, मगर अभी तक इसे रोकने के लिए अपने देश में कोई कानून नहीं है और न ही विदेश से आयात होने वाले ई-कचरे को रोकने के लिए कोई कानून बना है। हाल ही में हुए कोबाल्ट कचरे के परिणाम, दिल्ली वाले अभी तक भुगत रहे हैं। आई.टी. युग के शुभ एवं दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सरकार ई-कचरे के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाये।

(x) Need to re-start the Jodhpur Mail from Delhi to Jodhpur via Churu-Ratangarh in Rajasthan

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): दिल्ली से जोधपुर वाया चुरू - रतनगढ़ जोधपुर मेल चालू करने की मांग काफी समय से की जा रही है। आमान परिवर्तन के कारण उक्त गाड़ी को लगभग 15 वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था। उक्त गाड़ी को उत्तर रेलवे की सबसे अच्छी गाड़ी होने का गौरव प्राप्त था। अब आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग पर मालगाड़ियों का आना-जाना शुरू हो गया है। गाड़ी संचालन का संपूर्ण सिस्टम तैयार है। पिछले रेल बजट में रेवाड़ी से डेगाना पैसेंजर नई गाड़ी व दिल्ली सराय रोहिल्ला से सादुलपुर एक्सप्रेस गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलने वाली गाड़ी को छः दिन संचालन की घोषणा की थी। इन गाड़ियों का संचालन अविलम्ब करते हुए एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन सादुलपुर तक संचालित किया जाये।

मेरा सरकार से आग्रह है कि 15 वर्षों से बंद दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर मेल को अविलम्ब संचालित किया जाये। अगर इस समय यह संभव नहीं हो तो आने वाले रेल बजट में उक्त गाड़ी को चालू करने की घोषणा की जाये ताकि इस क्षेत्र की महती आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(xi) Need to take steps to check corporal punishment in Schools

SHRI AMBICA BANERJEE (HOWRAH): Even after the ruling given by the Apex Court on corporal punishment to school children, the country is continuing to adhere to the philosophy of spare the rod and spoil the child.

I would like to mention that such action reflects a perverse streak among certain educators. The problem is symptomatic of virulent mindset within the education system that sees believers in corporal punishment as a legitimate mean to discipline students and build character.

So far, there have been hundreds of cases across the country where children have sustained severe physical injuries by corporal punishment and in many cases it has led to deaths.

I, therefore, urge upon the Government to prevent such atrocities on school children and the perpetrators should quickly be brought to book through specific laws to erase this blot on our education system.

(xii)Need to provide assistance to the people affected by severe erosion caused by various rivers in North Bengal

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): A large number of rivers originating from the Himalayas and Bhutan Hills pass through the districts of North Bengal specially Jalpaiguri, part of Cooch Behar and Siliguri. The people living along both sides of these rivers like Teesta, Kaljani, Torsa, Mohananda, Raidak are affected due to erosion caused by rivers. A large number of people of these districts namely Vivekananda pally colony near Jalpaiguri town, areas in and around Siliguri, Apalchand village in Changmari mopuza in Jalpaiguri district, Mekliganj, Magumari and Kuchlibari in the district of Cooch Behar are the worst affected victims of heavy erosion of soil due to current of these rivers. Some of the villages have also been completely washed away. The State Government are trying their best with their limited sources to check the onslaught but of no use. It has now become imperative on the part of the Government of India to take a note of the situation and takes some effective measures before the situation goes out of control.

(xiii)Need to allocate funds for repair and maintenance of Tindivanam-Krishnagiri NH-66 in Tamil Nadu

SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): In my Krishnagiri district, Tamil Nadu, number of Highways are passing through. Out of which Tindivanam-Krishnagiri- NH 66 (200kms.) is an important NH project. This highway was earlier maintained by the State Government and later it was upgraded as National Highway (NH 66). This highway connects important places viz., Thiruvannamali Temple – Where tourists from all parts of the country visit throughout the year, JIPMER Hospital & Arvindo Ashram (Union Territory of Pondicherry) – where people from within and the outside country visit for medical treatment and darshan. This NH 66 is in a very dilapidated condition and there are pot-holes at many places. As there is huge traffic on this road, often vehicles get damaged. The Government of India has identified this project for upgradation at a cost of Rs. 700 crore. However, till date, there seems to be no progress on this project.

I, therefore, urge upon the Union Government to take up the Upgradation of Tindivanam- Krishnagiri-NH 66 (200 Kms.) on priority basis and allocate necessary funds for the same at the earliest.

(xiv) Need to ensure strict implementation of existing laws to curb female foeticide in country to bring the female sex ratio at par with male

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): A UNICEF report mentions that close to 50 million girls are missing because of the systematic gender discrimination cause female foeticide. Though the practice of female foeticide has been made difficult by the Indian state, the non-registered medical practitioners have made it possible for the typical patriarchal family to have access to illegal abortion services. According to another study over 2000 unborn girls are illegally aborted every day in India. Prosperous states like Punjab and Haryana are leading in such Cases as far as their sex ratios are concerned. It's not uncommon for these states to register a sex ratio of as low as 800 girls per 1000 boys. In this context, I request the Government to ensure that there is strict implementation of existing legislations, which were passed to curb the heinous crime of female foeticide. There should also be a regular assessment of indicators of status of women in society, such as sex ratio, female mortality, female literacy, female participation in the workforce etc. by the Government or a Government sponsored agency.

(xv)Need to direct the leading TV Networks to provide their pay channels for running cable TV- multiple system operators in Tiruppur, Tamil Nadu

SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Television play important role in the modern world. Now a days, the programme shown on television display vulgarity. This should be regulated immediately.

The pay channels like Star, Sony, Sun, Vijay, ESPN, Raj and KTV are not providing their channels to the Cable TV-MSO in Tamil Nadu. So the private MSO's are avoiding moving to court since they are unable to find justice by competing with those big channels. For example 'Tirupur Cable Vision' running cable TV-MSO in my Tiruppur constituency has made several requests from the above pay channels to provide the connection. But till now there is no response from them.

Hence, I request the Government to intervene in the matter and to direct the above said TV networks to provide their pay channels to Tiruppur Cable Vision.

(xvi)Need to provide funds from Central Road Fund for repair and maintenance of various roads in Tenkasi Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI P. LINGAM (TENKASI): Rajapalam Municipal town in my Tenkasi Lok Sabha constituency is situated at 560 Km. on the Chennai-Kollam National Highway No. 208. This emerging agro-industrial town has cotton textile mills, power looms, handloom units and bandaging cloth manufacturing units. Sugar cane, paddy, cotton, mango, coconut and several fruits and food grains are grown in the surrounding areas and are transported from Rajapalam Municipal Town. There are many industrial units in the neighbourhood like Sethur, Chettianpathi, Thalavacupuram, Chathirapatti. These places are connected to both the National Highways and State Highways. But still many of the roads need attention. Hence, I urge upon the centre to release necessary funds from the Central Road Fund for repair and maintenance of the following roads:-

1. Pugalenthi road.
2. Madasamy road.
3. Manikathankulam road.
4. Alaguthaakulam road.
5. T.P. Mills road.
6. Malaiyadipatti 60 road.
7. Malaiyadipatti 40 road.
8. Alaga Puri road.
9. Railway Feeder road.
10. Kamarajar Nagar road.
11. Singaraja Kottai Big Street.
12. Bye pass road to New Bus Stand.
13. Thiruvalluvar Nagar Main road.

(xvii) Need to expedite construction work of ROB at Pandavapura railway station in Mandya Parliamentary Constituency, Karnataka

SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways, through you Madam, towards the very slow pace of construction work of a ROB near Pandavapura Railway Station in my Mandya Parliamentary Constituency in Karnataka.

The construction work of this ROB was started about 8 years back. About 50% of the work has been completed in first four years. But after that no work has been progressed in the last four years. There are huge traffic congestions on this route. The people are facing great difficulties in crossing the railway line as the gates are frequently closed due to train movements. The Hon'ble Minister of State for Railways had also visited this site about 8 to 10 months ago and assured that the work on this flyover would be taken on war-footing basis. But, even after his assurance, no work has been started so far. This is one of the most important proposals in respect of my Parliamentary Constituency, Mandya, Karnataka.

Keeping in view of the above, I urge upon the Railway Minister to issue necessary instructions to the Railway authorities concerned for early completion of this ROB for the benefit of the people of my Constituency, Mandya, Karnataka.

(xviii) Need to extend hassle free loan facility to Small & Marginal farmers in Siwan Parliamentary Constituency of Bihar through Kisan Credit Card

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): भारत सरकार ने किसानों को वित्त व्यवस्था प्रदान करने, साहूकारों के शोषण से मुक्त कराने एवं किसानों को अपने खेतों में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने हेतु समय पर आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिए जाने की शुरुआत की है। मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान जिले में इस व्यवस्था से किसानों को वित्तीय सुविधा तो मिल रही है, परन्तु इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं तथा कई कठिन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। सीमांत एवं छोटे किसान वर्ग को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाये हैं और मिल भी गये तो उन बैंकों से ऋण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। साथ ही कृषि फसल बीमा योजना से जो प्रीमियम मिलता है, वह किसान क्रेडिट कार्ड धारक को समय पर नहीं मिल पाता है एवं किसानों को समय पर अपने कृषि कार्य के लिए आवश्यक बीज, खाद एवं अन्य सामग्री जुटाने में अनेकों दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान जिले में किसान क्रेडिट कार्ड संबंधित कार्य एवं इससे मिलने वाले ऋणों के कार्यों की समीक्षा की जाये और इसके लिए सार्थक ढंग से सिस्टम बनाया जाये, जिससे किसान को फायदा मिल सके।

12.05 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Bhopal gas tragedy

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अत्यंत वेदना के साथ इस दुखदायी प्रकरण पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरी इच्छा थी कि यह चर्चा नियम 184 के तहत होती और उसके बाद सदन एक ठोस प्रस्ताव पारित करता, लेकिन मुझे बताया गया कि कार्य सलाहकार समिति में नियम 193 के तहत चर्चा कराने की सहमति बनी है। उस सहमति के चलते मैंने अपने नोटिस को परिवर्तित कर दिया और मैं नियम 193 के तहत चर्चा कर रही हूं।

महोदय, वर्ष 1984 के आखिरी तीन महीने हिंदुस्तान में तीन बड़ी त्रास्दियों के लिए जाने जाते हैं। अक्टूबर की 31 तारीख को, मतलब महीने के आखिरी दिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके अगले दिन नवम्बर के पहले सप्ताह में हजारों हजार सिख भाइयों को सड़कों पर जिंदा जला दिया। इसके एक महीने बाद दिसम्बर की 2 तारीख और 3 तारीख की मध्य रात्रि को एक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों भोपालवासियों को मौत की नींद सुला दिया। ये तीन त्रास्दियां तीन तरह के कारणों से हुईं। पहली त्रास्दी विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। दूसरी त्रास्दी यानी सिखों का नरसंहार क्रूरता की पराकाष्ठा थी और भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव लापरवाही की पराकाष्ठा थी।

महोदय, अभी चंद दिनों पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक फोटो प्रदर्शनी इस हादसे की विभीषिका को दर्शाते हुए लगी थी। मैं स्वयं वहां गई थी। वहां रखी हुई तस्वीरें उस त्रास्दी की व्यापकता भी बता रही थीं और उसकी भयावहता भी दिखा रही थीं। उन तस्वीरों ने 25 वर्ष बाद भी इस हादसे को जीवंत रूप में उजागर कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोगों ने वह फोटो प्रदर्शनी देखी है, लेकिन वह फोटो प्रदर्शनी उस हादसे की एक जीवित कहानी कह रही थी, जो 25 साल पहले भोपाल में हुआ था। अभी पिछले दिनों टीवी पर एक कार्यक्रम भोपाल गैस त्रास्दी का आ रहा था, जिसमें गैस पीड़ित अपना-अपना बयान दे रहे थे। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि उस कार्यक्रम में एक महिला बोल रही थी, जिसके दो वाक्य मुझे कभी नहीं भूलेंगे। उसने कहा था कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थीं। लोगों को केवल स्वयं को बचाने की फिक्र थी। माँ बच्चों को छोड़ कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े माँ-बाप को छोड़ कर भाग रहे थे।

दूसरा वाक्य उसने कहा कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी। क्योंकि उस गैस के कारण फेफड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी, उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ कोई इन्सान जब मर जाता था तो मुंह से निकलता था -ईश्वर तुमने इसे मुक्ति दी। हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त करो, मुझे भी मौत दो।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बरसी थी। यह मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। इस मौत ने दरवाजा खटका-खटका कर कहा था इस फैक्टरी वालों को, दस्तक देकर कहा था, तीन साल तक मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूं, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो। अगर अंदर प्रवेश कर गई तो मैं हजारों को लील जाऊंगी। मौत घंटियां बजा-बजा कर सुना रही थी अपने आने की आवाज़, अपने आने की आहट। लेकिन यह आवाज़ बस्ती वालों ने सुनी, यह आवाज़ श्रमिक संगठनों ने सुनी, यह आवाज़ वहां के पत्रकारों ने सुनी और बार-बार वहां के सियासतदानों को सुनाने की कोशिश की, फैक्टरी के प्रशासकों को सुनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि प्रशासन ने केवल पैसे के लालच में और राजनेताओं ने सत्ता के मद में मौत की इस आवाज़ को अनसुना कर दिया।

मेरे पास जनसत्ता अखबार की एक प्रति है। इसमें काफी बड़ा लेख है। वहां के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, श्री राजकुमार केसवानी। यह अखबार 16 जून, 1984 का है। यह घटना दो और तीन दिसम्बर, 1984 की अर्धरात्रि की है। हिसाब लगाओ तो इस घटना से साढ़े पांच महीने पहले राजकुमार केसवानी ने यह लेख लिखा, जिसका शीर्षक है 'भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर'। इतना बड़ा लेख मैं पढ़ कर नहीं सुना सकती, लेकिन उसके कुछ प्रासंगिक अंश आपको सुनाना चाहूंगी। मैं इस पर गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान चाहूंगी।

उपाध्यक्ष जी, 1982 की एक घटना का जिक्र करते हुए राजकुमार केसवानी 16 जून, 1984 को जनसत्ता अखबार में लिखते हैं-

“ कि 5 अक्टूबर, 1982 मंगलवार का वह दिन, जब रात के अंधेरों में घिरकर बुधवार की शक्ल में तब्दील हो रहा था, तभी एमआईसी प्लांट पर काम कर रहे ऑपरेटर वाड़ेकर द्वारा वॉल्व खुलते ही पाइप लाइनों को जोड़ने वाली फिलिंज एक धमाके के साथ फूट पड़ी और जहरीला मिथाइल लावे की तरह उबल पड़ा। प्लांट पर काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने को बदहवासी में बाहर की तरफ भागने लगे और खतरे की सूचना देता अपशकुनी सायरन अपनी मनहूस आवाज़ में गूंज उठा। इस दुर्घटना में जहां प्लांट के चार लोग गम्भीर रूप से घायल हुए, वहीं दूसरी ओर भगदड़ के कारण कई लोगों को शारीरिक चोटें आईं और कुछ लोगों ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया।”
आगे की लाइन भी सुनने वाली है।


“1983 का साल भी ऐसी ही दो घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया।”

यह सन् 1982 की घटना बताई। आगे कहा -

“कि 1983 का साल भी ऐसी ही दो घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया। न मालूम यह 1984 का वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है।”

यह 16 जून, 1984 को राजकुमार केसवानी ने लिखा कि पता नहीं 1984 का यह वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है। इस वाक्य में उपाध्यक्ष जी आशंका भी है और भविष्यवाणी भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो इस प्लांट में पिछले तीन वर्षों से हो रही थीं, वे रोकी नहीं गईं। इसलिए यह एक औद्योगिक आपराधिक लापरवाही का मामला है। ऐसी लापरवाही जिसका इलाज हो जाता तो यह हादसा रुक सकता था। लेकिन पैसे बचाने के लालच में ये दुर्घटनाएं होने दी गईं और उन्हें सुधारा नहीं गया, उसका इलाज नहीं किया गया।

मैं इस फैक्ट्री का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहती हूँ। उपाध्यक्ष जी, 1969 में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन ने यूनियन कार्बाइड आफ इंडिया लिमिटेड का यह प्लांट भोपाल में लगाया।

यह कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें एमआईसी गैस इस्तेमाल होती थी। लेकिन एमआईसी यहां बनती नहीं थी, उसका यहां उत्पादन नहीं होता था, उसका आयात अमरीका से किया जाता था। वर्ष 1970 में इस कंपनी ने एक आवेदन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी कंपनी में उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, वर्ष 1970 का यह आवेदन पांच वर्ष तक पड़ा रहा, लेकिन वर्ष 1975 में, जब ऐसा  आया, जहां न अपील थी, न दलील, न वकील। जब भारत के लोगों के जनतांत्रिक अधिकार छीन लिये गये, जब देश में आपातकालीन स्थिति लागू थी, तब अक्टूबर 1975 में यह लाइसेंस इस कंपनी को दिया गया कि आप एमआईसी का उत्पादन यहां कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मृत्यु के तांडव ने पहला कदम भोपाल में उसी दिन रख दिया था जिस दिन इस कंपनी को एमआईसी बनाने का लाइसेंस केन्द्र सरकार द्वारा दे दिया गया था। एमआईसी की गैस साधारण गैस नहीं होती है, एमआईसी की गैस छोटी-मोटी जहरीली गैस भी नहीं होती है। उपाध्यक्ष जी, एमआईसी की गैस वह गैस है जो द्वितीय विश्वयुद्ध में इस्तेमाल हुई थी, यह वह गैस है जो हिटलर ने गैस-चैम्बरों में इस्तेमाल की थी, यह वह गैस है जो जिनेवा कंवेंशन से प्रतिबंधित थी। इस गैस को लगाने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ सावधानियां बरतने के नियम हैं। इस तरह की फैक्ट्री नगर की सीमा से कम से कम 20-25 किलोमीटर बाहर लगनी

चाहिए थी। लेकिन यह कंपनी जहां लगी वहां बहुत घनी आबादी थी, बड़ी-बड़ी कॉलोनियां इसके आस-पास बसी हुई थीं। इन सभी नियमों की अवेहलना की गयी। नियम यह है कि यह गैस बड़े-बड़े टैंकों में नहीं रखी जाती है, छोटे-छोटे टैंकों में रखी जाती है और वे छोटे टैंक भी आधे खाली रखे जाते हैं कि अगर कभी पानी उस टैंक में चला जाए और गैस उफनने लगे, तो वह जो आधा भरा हुआ टैंक है, वह गैस वहीं तक रह जाए, बाहर न छलके। उसके साथ खाली टैंक भी रखे जाते हैं। अगर गैस उफनने लगे तो गैस बराबर के टैंक में डाल दी जाए। वहां टैम्प्रेचर जीरो डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। इस कंपनी की बनावट में इनमें से एक भी सावधानी नहीं बरती गयी और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, जिस समय यह हादसा हो गया, तो बहुत सी जांच एजेंसियों को इस कंपनी में जांच के लिए भेजा गया। जांच के आधार पर सीबीआई ने एक चार्ज-शीट फाइल की है, वह चार्ज-शीट उस सीजीएम के आर्डर का हिस्सा है जो अभी 7 जून को उन्होंने फ़ैसला दिया है। माननीय गृह मंत्री जी वकील हैं, मैं उस फ़ैसले में वह हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहती हूं कि क्या-क्या लापरवाहियों का जिक्र चार्जशीट में किया गया।

Mr. Home Minister I would like to draw your attention to what the CGM says according to the charge sheet and I would quote:

“The procedure for storage of MIC has been given at page 7. MIC should be stored in underground tanks of stainless steel type 304 and 316 for safety reasons. The size of the tank should be kept twice to the volume required for storage. As an alternative an empty tank should be kept available at all the times.

Now, the CSIR Report reveals that the main *causa causan* for the incident were:

- The needless storage of large quantity of MIC in large tanks like tank number 610.
- Insufficient caution in design.
- Choice of material.
- Other alarming instruments.
- Inadequate control on system of storage
- and on quality of stored material and as well as necessary facilities for quick effective disposal of material which led to the incident.”

There is one more thing, Mr. Home Minister:

“More so on the date of incident, refrigeration system was not working. The flare tower was also out of order. VGS was incapable of neutralizing the large quantity of MIC. The MIC which is highly



dangerous and toxic poison and stored in large quantity was an act of omission on the part of the accused person and no step was taken by the then authorities, namely, Shri Warren Anderson, the Chairman, Union Carbide Corporation, USA.”

यह है वह लापरवाही का मामला जो मैंने आपके सामने रखा है, जिस चार्जशीट के आधार पर उन्होंने कहा कि यह हादसा हुआ। इसीलिए मैंने कहा, यह मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं है, यह मामला केवल एक्सीडेंट का नहीं है, यह मामला सामूहिक हत्या का मामला है। आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं, this is a case of corporate man slaughter. केवल यही बात उस अमेरिकन कंपनी को समझ में आएगी, सामूहिक हत्या उसको समझ में नहीं आएगी। This is a case of corporate man slaughter. जहां केवल आर्थिक लाभ उठाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हिन्दुस्तान की जान को सस्ता समझते हुए यह हादसा होने दिया गया। यह हादसा हुआ नहीं, यह हादसा करवाया गया, लापरवाही के कारण करवाया गया। यह मेरा पहला आरोप है।

महोदय, उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग मरे, जब लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से फुरसत पाए, तो शुरू हुई कानूनी लड़ाई। अनेक संगठन बने गैस पीड़ितों के, उन्होंने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग अदालतों में मुकदमे डाले, केसेज दर्ज हुए। जबलपुर, भोपाल, दिल्ली में केस डाले गए। तरह-तरह के केसेज अलग-अलग जगह पर चलने लगे, तो भारत सरकार को लगा कि इतने केसेज ये लोग अलग-अलग व्यक्तिगत तौर पर लड़ें, यह सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक एक्ट बनाकर लड़ाई के सारे अधिकार खुद ले लें और इन सभी की तरफ से हम लड़ें। इस सोच के साथ एक एक्ट पारित हुआ- भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोशेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, 1985। इस एक्ट को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया और सारे अधिकार केन्द्र सरकार ने ले लिए। इस एक्ट की धारा -3 कहती है : “The Central Government shall and shall have...” आप विधिवेत्ता हैं, जानते हैं कि जब किसी चीज पर एम्फेसाइज करना होता है, तो दसे दुबारा कहा जाता है।

“The Central Government shall and shall have the exclusive right to represent and act in place of whether within or outside India every person who has made or is entitled to make a claim for all purposes connected with such claim in the same manner and to the same effect as such person.”

यानी केन्द्र सरकार ने कहा कि सारे अधिकार हमें दे दो, कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता, हम यह लड़ाई लड़ेंगे, उस हर व्यक्ति की तरफ से जिसने कहीं भी मुकदमा डाल रखा है। लोगों को लगा कि इससे बड़ी सोच नहीं हो सकती, इससे बड़ी मदद भारत सरकार नहीं कर सकती है। अकेला आदमी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से कैसे लड़ेगा, उनके पास इतना पैसा, इतना बड़ा अमला, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से लड़ेगी, तो भारत सरकार के आगे वह बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी पड़ जाएगी। भारत सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि वह हम सभी की ओर से उस कंपनी को दबोच लेगी और हमें न्याय दिलाएगी। भोपाल के गैस पीड़ितों ने भरोसा किया।

गैस पीड़ितों ने अंत का विश्वास करके यह बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिये। लेकिन उसके बाद जो घटा है, उसे मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। चार साल के बाद 1985 में यह एक्ट आया। वर्ष 1989 में उस भारत सरकार ने जिस पर गैस पीड़ितों ने भरोसा किया था, जो दावा उन्होंने डाला था, वह दावा 1113 (19860, उस दावे में उन्होंने तीन बिलियन डॉलर यानी 3900 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया था। 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कॉरबाइड कॉरपोरेशन से एक सुलहनामा किया, आउट ऑफ दि कोर्ट सैटिलमेंट किया। कोर्ट के अंदर मेरिट पर फैसला नहीं हुआ और आउट ऑफ दि कोर्ट भारत सरकार ने और यूनियन कॉरबाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोगों ने बैठकर एक सुलहनामा तय किया और 615 करोड़ रुपये में उनकी सारी देनदारियां खत्म कर दीं, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दीं। आप हैरान होंगे। मेरा खून खौलता है जिस समय मैं इस समझौते को पढ़ती हूं। 14 फरवरी को यह समझौता हुआ। 15 फरवरी को ऑर्डर हुआ और उसके बाद एक टर्म ऑफ सैटिलमेंट बनीं। वे टर्म ऑफ सैटिलमेंट क्या हैं? वे अंग्रेजी में हैं, इसलिए पहले मैं अंग्रेजी में पढ़कर बताती हूं और बाद में उसका हिन्दी शब्दार्थ बताऊंगी।


“This settlement shall finally dispose of all past, present and future claims, causes of action, civil and criminal proceedings of any nature whatsoever wherever pending by all Indian citizens and of public and private entities with respect to the past present and future dates, personal injuries, health effects, compensation, losses, damages and civil and criminal complaints of any nature whatsoever against the Union Carbide Corporation....”

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): Who was the Prime Minister at that time?...

(Interruptions) Shri V.P.Singh was the Prime Minister... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अरे, मत बोलिए। पोल खुल जाएगी।... (व्यवधान) 14 फरवरी 1989 को प्रधान मंत्री कौन था, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, नारायण स्वामी जी। क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें खुद फंस जाएंगे।... (व्यवधान) सुनिए।

“Union Carbide India Limited, Union Carbide Eastern and all of their subsidiaries and affiliates as well as each of their present and former Directors, officers, employees, agents, representatives, attorneys, advocates and solicitors arising out of, relating to or connected with the claims, causes of action and proceedings against each other. All such claims and causes of action whether within or outside India, all Indian citizens public or private entities are hereby extinguished including, without limitation, each of the claims filed or to be filed under the Bhopal Gas Leak Disaster registration and processing of claims 1985 and all such civil proceedings in India are hereby transferred to this court and are dismissed without prejudice and all such criminal proceedings including contempt proceedings stands quashed and accused deemed to be acquitted upon full payment and in accordance with the court’s direction. The undertaking given by UCC pursuant to the order dated 30th November, 1986 in the district court of Bhopal stands discharged and all orders passed in suit no. 113 of 1986 and or any revision therefrom also stands discharged.”

उपाध्यक्ष महोदय, यह समझौता अंग्रेजी में था, इसलिए अंग्रेजी वालों को तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं हिन्दी का शब्दार्थ इस सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूँ कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि 615 करोड़ रुपये भारतीय सरकार को देकर यूनियन कार्बाइड के लोगों ने गैस पीड़ितों से कहा - ये पकड़ो 615 करोड़ और गायब हो जाओ। खबरदार अगर कल से दीखे, किसी कोर्ट, कचहरी, अदालत में मत दीखना। आज से हमारी भूत, ष्य और वर्तमान की सारी देनदारियां खत्म, आज से हमारे खिलाफ चल रहे दीवानी और फौजदारी के सारे मुकदमे खारिज। आज से हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे किसी भी वर्तमान या भावी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ तुम कोई मुकदमा नहीं डाल सकते, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे रहनुमाओं के साथ हमारा समझौता हो गया है।

उपाध्यक्ष जी, 615 करोड़ रुपये के दो ड्राफ्ट, जिनमें एक 420 मिलियन अमरीका डालर का और दूसरा 68 करोड़ भारतीय रुपये के दो ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी ताकत पर इठलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्डाईड के लोग बाहर निकल गये। बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे। गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किये। मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए तो भारत सरकार के कुछ लोगों ने बाहर निकलकर समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको यह भी मिलता कि नहीं मिलता। जब वे लोग उन्हें यह समझा रहे थे तो उस समय मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा था, जो मेरे मुंह से निकल रहा था -

“तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि कारवां क्यों लुटा,
हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।”


हम उनसे क्या शिकायत करें, वे तो व्यापारी थे, व्यापार करने और कमाने आये थे, वे हमें पैसा क्यों देते। लेकिन जिसे रहबर बनाया था, 1985 के एक्ट के तहत अपने हाथ काटकर जिसे सारे अधिकार दिये थे, जिसे अपना रहनुमा बनाकर बैठाया था, जिस पर विश्वास किया था, उस रहबर ने क्या किया। उस रहबर ने 3900 करोड़ का दावा 615 करोड़ में दीवानी और फौजदारी सारी देनदारियों से मुक्त करके उन्हें बरी कर दिया। शायद कुछ लोगों को यहां यह लगता हो कि 1989 में 615 करोड़ रुपये उस समय बहुत रहे होंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, यह तो बड़ा अमाउंट था, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि यह बड़ा अमाउंट नहीं था। क्योंकि 615 करोड़ रुपये कितने लोगों में बंटने थे, यह आप जानते हैं। वहां 10 लाख लोगों का क्लेम था और साढ़े पांच लाख लोगों में यह 615 करोड़ रुपये बंटे। क्या आना था - दो-दो हजार, तीन-तीन हजार या पांच-पांच हजार रुपये। यह बात मैं नहीं कह रही हूं कि कितने क्लेम्स थे और कितने लोगों में यह पैसा बंटा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था। उस सवाल का जवाब 29 जुलाई को दिया गया। उस प्रश्न का नम्बर 70 था। सरकार से सवाल पूछा गया था कि कितने दावे थे, कितने लोगों का मुआवजा बंटा, यह आपकी सरकार का जवाब है।

“A total of 10,29,517 claim cases were filed and the Office of the Welfare Commissioner, after adjudication, awarded compensation in 5,74,376 cases.”

5,74,376 लोगों के दावे वैध पाये गये। हो सकता है कि उनमें से बहुत से वैध दावे रह गये हों। लेकिन जिन्हें कल्याण आयुक्त, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल ने वैध पाया, उन दावों की संख्या 5,74,376 है।

आप बताइये कि उनके लिए 615 करोड़ रुपये क्या थे। इसके बाद मुझे और दुख हुआ, जब मैंने उनसे पूछा तो किसी ने कहा 25-25 हजार की दो किस्में मृतकों को मिली।

कुछ लोगों को पांच हजार रुपया मिला, कुछ लोगों को दस हजार रुपया मिला क्योंकि 615 करोड़ रुपये में आप क्या बांटेंगे? रुपया कोई खबड़ तो नहीं है कि जिसे आप खींच लेंगे। मैं अब उसके बाद की बात करूंगी। वहां तो सरकार ने जो किया सो किया लेकिन जब बावेला मचा, सीजीएम का नया ऑर्डर आया, दुबारा से यह मामला चर्चा में आया, पत्र-पत्रिकाओं में इसके खिलाफ लिखा जाने लगा, टी.वी. पर कार्यक्रम आने लगे तो वर्तमान सरकार ने मंत्रियों का एक समूह । वर्तमान सरकार के जीओएम ने तय किया कि जो मृतक हैं, हम उन्हें दस लाख रुपया देंगे माइनस जितना उन्हें मिल चुका है। जो टोटली डिसेबल्ड हैं, उन्हें राशि देंगे। ऐसा करके उन्होंने एक निर्णय किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताते हुये दुख हो रहा है कि जिस सवाल में सरकार ने पहले पृष्ठ पर यह कहा कि 5,74,376 दावे वैध थे, उसी सवाल में एक अनुलग्नक, एक अनैक्सर लगाया क्योंकि उस सवाल का एक भाग यह भी था कि जीओएम बना है, उसकी सिफारिशें क्या हैं और उसने क्या तय किया ? सरकार ने जीओएम की सिफारिशें उसी सवाल संख्या 70 में लिखी हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुनाती हूं -

“Compensation to the following categories of claims of victims and the families may be enhanced as under: Death – 5,295; permanent disability – 3,199; cancer cases about 2,000; total renal failure about 1,000; temporary disability – 33,672.”

मैंने इस आंकड़े को जोड़ा है जो 45,166 बनता है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप उस जीओएम में थे। सवाल के भाग-एक में आप कहते हैं कि गैस प्रभावित लोगों के 5,74,376 दावे वैध पाये गये और जब आपका जीओएम बैठता है तो वह 45,166 लोगों के लिये व्यवस्था करता है। अगर आप यह राशि 45,166 लोगों के लिये दे रहे हैं तो फिर वह राशि 5,74,376 लोगों में बंटेगी, फिर उनका वही हाल होगा कि किसी को हजार रुपया मिलेगा, किसी को दो हजार रुपया मिलेगा या किसी को तीन हजार रुपया मिलेगा। सरकार ने 5295 व्यक्ति डैड माने हैं लेकिन 15,342 लोग मृत हैं। यह वैलफेयर कमिश्नर ने माना है। आप कहेंगे कि हमने आंकड़ा तो भोपाल से लिया है। जो 5,295 लोग हैं, वे तुरंत मर गये लेकिन जो अगले 2-3 दिनों में मर गये, जो लोग पैर पटकते-पटकते पांच दिन में मर गये, दस दिन में मर गये, सालभर में मर गये लेकिन उसी गैस के कारण मरे जिस गैस ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। क्या आप उन्हें मृत लोगों की श्रेणी में नहीं मानेंगे? मेरे पास भोपाल का आंकड़ा है जहां उन्होंने कहा है - “15,342 people were found dead.” यहां भी 22 हजार मरे हुये लोगों के दावे आये थे लेकिन 15,342 लोगों

को उन्होंने मृत पाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज 25 वर्ष के बाद जब आप प्रावधान करने लगे हैं, अगर एक जीओएम बनाया है, आप वापस इस मामले को खोल रहे हैं तो कम से कम 5,74,376 तमाम लोगों के लिए प्रावधान करने का काम करें जिनके दावे वैध पाये गये हैं। जो दस लाख रुपये देने की बात है, वह कम से कम 5,295 से उठाकर 15,342 लोगों की बात करें जिन्हें वैलफेयर कमिशनर ने मृत पाया है। यह मत करिये कि उस दिन कौन मरा था या 6 महीने बाद कौन मरा था या एक साल के बाद कौन मरा था। अगर मृत्यु का कारण भोपाल गैस त्रासदी है तो आप उसके लिये व्यवस्था करें, यह मेरी मांग है।

उपाध्यक्ष जी, अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। भारत सरकार यह पैसा अपनी तरफ से दे रही है। जीओएम में जो लिखा गया है कि एनहैंसड कम्पनसेशन भारत सरकार अपनी तरफ से दे रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत सरकार पैसा उगाती है?

मैं पूछना चाहती हूँ क्या भारत सरकार पैसा उगाती है? क्या भारत सरकार के यहां पेड़ लगे हुए हैं, जहां पैसा लटकता है? भारत सरकार का पैसा भारत के करदाताओं का पैसा है। भारत सरकार का पैसा इंडियन टैक्स पैयर्स का पैसा है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारतीय मरें और भारतीय ही मुआवज़ा भरें और फिरंगी मौज करें, यह कहां का न्याय है? होना तो यह चाहिए कि यह पैसा हम उनके हलक से निकालकर लाएं। लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें वापस छूट दे रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि यह पैसा हम अपने खजाने से देंगे। लेकिन यह खजाना आपका कहां है? यह खजाना भारतीय जनता का है, भारत के लोगों का है। आप उन फिरंगीयों को क्यों नहीं पकड़ते हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अपराध करके चले गए, जिन्हें आपने 615 करोड़ रुपये में बरी कर दिया, उनका बाकी भुगतान आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे नहीं लेना चाह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके अपने यहां क्या स्थिति है? गृह मंत्री को भी यह मालूम होगा। यह अप्रैल का केस है, अमरीका में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक घटना घटी, जिसमें ऑयल स्पिल हुआ। उसमें 11 लोग मरे और बाद में दो लोग मरे, यानी कुल 13 लोग मरे। अमरीकी प्रशासन ने ब्रिटिश पेट्रोलियम को बुलाकर कहा कि 90 हजार करोड़ रुपये मुआवजे के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण खराब हुआ है। इन 11 लोगों को तो देंगे ही, हम अपना पर्यावरण भी सुरक्षित करेंगे। 90 हजार करोड़ रुपये जिस ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी से एक तरफ रखवाया है, उसी अमरीका की कंपनी को आप 615 करोड़ रुपये लेकर छोड़ देते हैं।...(व्यवधान) आप कहेंगे कि हम यह कैसे करें? मैं आपको रास्ता बताती हूँ कि कैसे करें? गैस पीड़ित संगठनों ने आपके उस समझौते के बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ी है। उन्होंने एक केस यूनाईटेड स्टेट्स में डाल रखा है, जो कि न्यूयार्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है। वह केस पर्यावरण पर है। उनके यहां तो तेल छलका, हमारे यहां भोपाल की यह हालत हो गई, हमारे

भोपाल के माननीय सांसद आपको बताएंगे। इस फैक्ट्री के पांच स्कवैयर किलोमीटर में पीने का पानी जहरीला हो गया है, न वहां ट्यूबवैल खुद सकता है, न हैण्डपम्प लग सकता है। वहां पानी नहीं आ सकता है। वहां का पानी जहरीला है, जिसे कोई नहीं पी सकता है। पानी के जहरीले होने के कारण आस-पास की जमीन बिकनी बंद हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि 90 हजार करोड़ रुपये का जो मुकदमा अमेरिका ने डाला है, उसमें एक कारण यह बताया गया है कि हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लैक्सिज़ की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, यानी उनके सैलानियों का सैर-सपाटा बंद हो जाए, इसके लिए 90 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। उनके सैलानी सैर-सपाटे को नहीं आ सके। इसलिए 90 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा मांगते हैं और हमारे यहां 15 हजार लोग मर गए, लाखों-लाख लोग घायल हो गए, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और हम यहां 615 करोड़ रुपये में छोड़ दें। यह मुकदमा वहां चल रहा है। पांच स्कवैयर किलोमीटर में पानी जहरीला है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं है, हमारी तीसरी पीढ़ी अपाहिज हो रही है। मेरे पास प्रैस की कटिंग और एक पत्र है। हमारी एक कार्यकर्ता डॉ. फिरोज़ा बानो ने यह पत्र लिखा है और प्रैस की कटिंग के साथ भेजी है, जिसका शीर्षक है- गैस त्रासदी का दंश तीसरी पीढ़ी भुगत रही, अली ने गंवायी किडनी। यह दस वर्ष का बच्चा है। जिसमें लिखा है सिंदी कालोनी निवासी ए.यू. खान और उनका परिवार 2 दिसम्बर, 1984 को यूनियन कार्बाइड से निकली गैस की चपेट में आया था। बच्चे के दादा ने बताया कि बच्चे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। लेकिन बीएमएचआरसी अस्पताल में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस बच्चे को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दस लाख रुपये का एस्टीमेट दिया गया है।

इसमें दस लाख रुपए का एस्टीमेट दिया गया है, लेकिन सरकार ने मुआवजे की केवल 25 हजार रुपए की राशि दी है। 615 करोड़ रुपए में से मात्र 25 हजार इस बच्चे को दिए गए, जिसके इलाज पर दस लाख रुपए खर्च होने हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारी तीसरी पीढ़ी दंश भुगत रही है। दस वर्ष के बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गईं, पांच स्कवैयर किलोमीटर में पानी जहरीला हो गया है। जो केस युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट में पड़ा है, उसमें आप पार्टी बनिए और ब्रिटिश पेट्रोलियम के केस का तर्क देते हुए अमेरिकन कम्पनी को जिसने खरीद लिया है, उस दाऊ केमिकल से हजारों-हजार करोड़ का मुआवजा लेकर आएँ, जिससे पर्यावरण भी बचाएँ और उन गैस पीड़ितों को मुआवजे की और राशि भी दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस केस के जो दंड के प्रावधान हैं, उन पर आती हूं। कानूनी लड़ाई दो तरह की थी - एक मुआवजे की और दूसरी दंड की थी कि दोषी लोगों को दंड दिया जाए। सीबीआई ने जो

चार्जशीट फाइल की, उसमें पहला अभियुक्त वारन एंडरसन, युनियन कार्बाइड कार्पोरेशन का चेयरमैन है। चार्जशीट फाइल करने के बाद एफआईआर में इनका पहला नाम था। वारन एंडरसन भारत आए और भोपाल भी गए। शाम को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के चंद घंटे के बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें केवल रिहा ही नहीं किया गया, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी विमान में बैठा कर दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली से अमेरिका वापस भेज दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूँ कि यह काम किस के निर्देश पर किया गया था? पूरा देश इसका जवाब मांग रहा है कि यह काम किस के निर्देश पर किया गया था? सब मौन हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा मौन हैं प्रधान मंत्री जी मौन हैं और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी मौन हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि "हादसा वह था नहीं, जो घट गया, हादसा यह है कि सब चुपचाप हैं।" मैं पूछना चाहती हूँ कि यह निर्णय किस के निर्देश पर किया गया था? जीओएम ने दबी जुबान से कहा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को उसकी खबर एंडरसन के जाने के बाद मिली। इस असत्य का पर्दाफाश हिन्दू अखबार ने किया। मेरे पास हिन्दू अखबार की दो कतरनें हैं। मेरे पास 26 जून, 2010 का अखबार है, जब आपने यह बोला कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को उनके जाने के बाद खबर मिली थी। इस विषय में हिन्दू अखबार में लिखा है -

“As our front page story notes, the Group of Minister’s conclusion that “contemporary media reports also indicate that the Prime Minister was briefed on the matter after Mr. Anderson left the country” is factually incorrect.

Assuming that G.K. Reddy’s reports in *The Hindu* (especially the front page story of December 8, 1984) are part of the contemporary media reports:” referred to by the GoM, its conclusion is either a careless misreading of the reports, or, more likely, a clumsy attempt at a cover-up.”

हिन्दू अखबार कह रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं, या तो आपने उनकी रिपोर्ट्स को जानबूझ कर सही से पढ़ा नहीं और या इसे कवरअप करने की, लीपापोती करने की कोशिश है। वह रिपोर्ट उन्होंने उस दिन दोबारा लिखी, 8 दिसम्बर, 1984 की वह रिपोर्ट, जो जी.के. रेड्डी ने हिन्दू में दी थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने जस का तस 26 जून के अखबार में दोबारा छाप दिया। उसे मैं पढ़ कर बताती हूँ, उसमें जी.के. रेड्डी ने लिखा था -

“The American Charge d’Affairs, Mr. Gordon Creeb called on the Foreign Secretary Mr. M.K. Rasgotra, to voice the US Government’s concern over Mr. Anderson’s arrest despite the assurances of safe passage given by the Government of India.”

इस रिपोर्ट को क्या मैं दुबारा पढ़ूं ? अमेरिकन चार्ज-डी-अफेयर्स गॉर्डन स्ट्रीब ने आकर श्री एम.के. रसगोत्रा के पास इस बात की शिकायत की थी कि भारत सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि एंडरसन को सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, भोपाल में गिरफ्तार क्यों किया गया? इंडियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? बताइए नारायणसामी जी। प्रधान मंत्री कौन थे, यह भी आपको पता है। ...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी कर के सुनिए। ...(व्यवधान) Mr. Deputy Speaker, Sir, newspaper reports will not form part of the proceedings of this House. Several rulings have been given in this House and the hon. Leader of the Opposition also knows it. She is quoting from newspaper reports which cannot be admitted in Parliament. ... *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, नारायणसामी जी, मैं यह कह रही हूँ कि जी.ओ.एम. ने कंट्रेरी मीडिया रिपोर्ट्स का ही जिक्र किया था। यह अलग कैसे है? ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: You are quoting from The Hindu. There are several rulings that newspaper reports cannot be quoted in this House by any Member. ... *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट है। नारायणसामी जी, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए, उसकी ओट लेते हुए जी.ओ.एम. कहता है कि अगर उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री को पता होता, तो कम से कम मीडिया रिपोर्ट तो करता। कंट्रेरी मीडिया रिपोर्ट भी यह कहती है कि उस समय के प्रधान मंत्री को बाद में खबर दी गई। इसलिए कंट्रेरी मीडिया रिपोर्ट निकाल कर हिन्दू ने यह कहा कि आपने हमारी रिपोर्ट को जानबूझ कर गलत पढ़ा है या लीपा-पोती कर रहे हैं और उन्होंने 26 जून, 2010 को, अपनी 8 दिसम्बर, 1984 की खबर छपी। मैं वह पढ़कर सुना रही हूँ, जो उस समय 8 दिसम्बर को लिखा गया था। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी लोग कहते हैं कि एंडरसन को भगा दिया गया। मैं कहना चाहती हूँ कि यह ‘भगाई’ का मामला नहीं है, बल्कि ‘विदाई’ का मामला है और शाही विदाई का मामला है। लेकिन इसके साथ-साथ इस संदर्भ में सी.बी.आई. की कार्य-शैली पर भी प्रश्न-चिह्न लगता है। मैं यहां गृह मंत्री जी से पूछना चाहती

हूं कि एक कुख्यात आतंकवादी, घोर अपराधी, सोहराबुद्दीन के मामले में तो सी.बी.आई. एक राज्य के गृह मंत्री को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन 15 हजार लोगों के हत्यारे एंडरसन को देश से भगाने का काम करती है। ...(व्यवधान) क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। माननीय सुषमा जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैं कोई गढ़कर नहीं कह रही हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सोराबुद्दीन 'टाडा' कन्विक्ट था, जिसके घर से 28 ए.के.47 और 2 ए.के. 56 मिलीं। उसके घर के पीछे कुआं बना था, जिसमें हथियारों का जमावड़ा था। ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, we are not discussing Mr. Amit Shah's case here. He is in jail now. He was the Home Minister of Gujarat, but he is in jail now. We are not discussing his case here now. ... *(Interruptions)*

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : निरुपम जी, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बता रही हूं।...(व्यवधान)



उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर सिर्फ सुषमा जी की बात जायेगी, बाकी किसी की नहीं जाएगी।

*(Interruptions) ... **

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप लोग बैठ जाओ। आप लोग चुप रहो। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। शान्ति बनाये रखिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। निरुपम जी, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, मैं कतई विषयान्तर नहीं करूंगी। मैं अपने विषय की सीमा जानती हूं। उस विषय की परिधि में रहकर के बात करूंगी। हमने सी.बी.आई. के राजनैतिक दुरुपयोग पर अलग से चर्चा मांगी हुई है। हम ये सारे उदाहरण तब देंगे। मैं केवल एक तुलना कर रही हूं कि एक तरफ

* Not recorded.

एक राज्य के गृह मंत्री को आप जेल में डालते हैं और दूसरी तरफ आप एंडरसन को भगाते हैं, जो 15,000 लोगों का हत्यारा है। दूसरी तुलना मैं यह कर रही हूँ कि...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : और दूसरी तुलना मैं यह करना चाहती हूँ कि एक तरफ एक व्यक्ति, जिसके घर में हथियारों का जमावड़ा, एक जखीरा मिलता है, जो टाडा का कन्विक्ट है, उसकी मौत के केस को तो सी.बी.आई. इतनी प्राथमिकता देती है कि एक-एक दिन के लिए अगर सम्मन की तामील न हो तो टी.वी. पर चलवाती है, लेकिन दूसरी तरफ एंडरसन के लिए 27 मार्च, 1992 को वारंट निकले, 22 जुलाई, 2009 को वारंट निकले, लेकिन आज तक सी.बी.आई. उन वारण्टों को तामील नहीं करा सकी है। इसके लिए मैं इस विषय को लाई हूँ। मैं एकदम प्रासंगिक बोल रही हूँ। मैं तुलना कर रही हूँ। हमारे पास ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं। वे उदाहरण हम देंगे, जब सी.बी.आई. की कार्यशैली पर चर्चा करेंगे तो हम वे उदाहरण देंगे। आज मैं उस चर्चा में भाग नहीं ले रही हूँ, लेकिन...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इनकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*(Interruptions) ...**

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन मेरा यह कहना है कि सी.बी.आई. अपने आकाओं के निर्देश पर काम कर रही थी और इसीलिए उसको गिरफ्तार करने के बाद उसने उसको रिहा भी किया, भगा भी दिया और एक बार नहीं, सारे फिरंगी भगाये जाते हैं, चाहे क्वात्रोची हो या एंडरसन, कोई यहां नहीं रहता। आज ही अखबार में है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठिये-बैठिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज ही अखबार में है कि सी.बी.आई. ने कहा कि क्वात्रोची के केस की फाइलें हटा दी जायें, और केस बन्द कर दिया जाये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।

* Not recorded.



13.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहिएगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, आज ही समाचार पत्र में छपा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज ही समाचार पत्र में छपा है कि क्वात्रोची का केस बंद करने के लिए सीबीआई ने अर्जी दी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार को फिरंगियों से इतना मोह क्यों है? ...(व्यवधान) क्वात्रोची और एंडरसन, एंडरसन को भगा दो, क्वात्रोची को भगा दो और बाद में कहो कि हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल सुषमा जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

*(Interruptions) ...**

श्रीमती सुषमा स्वराज : और बाद में कहो कि हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए उन पर चार्ज नहीं लगा और केस बंद करवा दिया। ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वह घटना वर्ष 1984 की है। एंडरसन को बुलाने के लिए पहली बार लेटर **रोगेटरी मई**, 2003 में भेजा गया। ...(व्यवधान) तब एनडीए की सरकार थी। यह मैं खुद नहीं कह रही हूँ। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी, यह जवाब भी इसी सदन में दिया गया। इसी सदन में जो जवाब दिया, उसको मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ। प्रश्न संख्या 54 - जिसमें पूछा गया था, यह 28 जुलाई का है, 28 जुलाई को एक्स्ट्राडीशन आफ वारेन एंडरसन पर जवाब दिया गया। जवाब में उन्होंने कहा :

“In May 2003, it was decided to forward the request for the extradition of Warren Anderson on the basis of the available evidence.”

For the first time मई, 2003 में वारेन एंडरसन के एक्स्ट्राडीशन के लिए रिक्वैस्ट लेटर भेजा गया। ...(व्यवधान) उसके बाद वर्ष 2004 में हम चले गए। तब से लेकर आज तक सीबीआई ने उसके

* Not recorded.

प्रत्यर्पण के लिए क्या किया? मैं यह पूछना चाहती हूँ। यह केवल वारेन एंडरसन का मामला नहीं है। महोदय यह दासतां बहुत बेवफाईयों से भरी हुयी है। मैंने जिस समझौते का जिक्र किया ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए। भोजन का समय हो गया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : वर्ष 1989 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया था, उस समझौते को भी गैस पीड़ित संगठनों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय नहीं मिला, पर यह सच था। उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ न्यायाधीशों को जरूर न्याय मिल गया। उस समझौते का आर्डर पास करने वाले एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में नियुक्ति मिल गयी थी। एक जज को कई आयोगों का अध्यक्ष बनाते-बनाते राज्य सभा भी मिल गयी थी। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया था, अगर ठगे गए तो केवल गैस पीड़ित ठगे गए थे। लेकिन उन लोगों ने जब समझौते को चुनौती दी तो वर्ष 1991 में उन्हें आधा न्याय मिला। वर्ष 1991 में एक आर्डर पास करके जस्टिस वेंकटचलैय्या जी ने, यह भी पांच लोगों का कांस्टीच्यूशन बेंच था, लेकिन जजमेंट वेंकटचलैय्या जी का था, उन्होंने कहा कि जो दिवानी मामला मुवाअजे का है, उसको हम नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने क्वेश कर दी हैं, उनको हम खत्म करेंगे और हम चाहेंगे कि आप अगर फौजदारी मुकदमा चलाना चाहो, तो चला सकते हैं। उस आर्डर की चार लाइनें पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।

“The contention that the Court had no jurisdiction to quash the criminal proceedings in exercise of power under Article 142 (1) is rejected. But, in the particular facts and circumstances, it is held that the quashing of the criminal proceedings was not justified. The criminal proceedings are, accordingly directed to be proceeded with.”

उन्हें आधा न्याय मिला। वे खुश हुए और उन्होंने फौजदारी मुकदमे दुबारा डाले। सभी अदालतों में चल रहे फौजदारी मुकदमे वापिस शुरू हो गए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : वे जो फौजदारी मुकदमे शुरू हुए, लोग खुश हुए। उन्होंने कहा, हम दिवानी लड़ाई अमरीका की कोर्ट में लड़ रहे हैं, भारतीय कोर्टों में कम से कम फौजदारी मुकदमे जीतेंगे। लेकिन उसके

बाद 1996 में फिर एक धोखा हुआ, फिर एक बेवफाई हुई। जो मुकदमे आईपीसी की धारा 304 (II) के नीचे चल रहे थे, जिसमें दस साल की सजा का प्रावधान था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहमदी ने 304 (II) से घटाकर 304 (ए) में कर दिए जिसमें केवल दो साल की सजा का प्रावधान था। उन्होंने क्या कहा, उसे मैं पढ़कर बताना चाहती हूँ।

It says:

“It is held that on the material laid by the prosecution, appropriate charges which are required to be framed against the accused concerned are under Section 304 (A) of the IPC. In the result of the appeals filed by the accused, charges framed against them under Section 304 Part II are quashed and set aside.”

जस्टिस अहमदी को बीएमएचआरसी की लाइफ लॉग ट्रस्टिशिप मिली। दस साल की सजा का प्रावधान लेने वाली धारा हटाकर दो साल की सजा के प्रावधान में बदल दी गई। यह दूसरा धोखा था, दूसरी बेवफाई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि यह दास्तान इतनी लम्बी है कि इसमें किस-किसने क्या खेल खेला है, वह मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूरा मत बताइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : लोग जो कहते हैं कि सीजीएम ने दो साल की सजा दी। बड़े-बड़े अखबारों ने लिखा - “Justice is blind. After 25 years, only two years’ punishment.”

सीजीएम क्या करता? उसके हाथ बंधे थे। इस फैसले की नींव जस्टिस अहमदी ने उसी दिन डाल दी थी जिस दिन वह धारा बदलकर दो साल की सजा के प्रावधान में कर दी गई थी। सीजीएम दो साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता था। उसने अधिकतम सजा सुना दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ। एक जीओएम यहां बना, एक जीओएम मध्य प्रदेश में बना। यहां इन्होंने तय किया कि हम एक क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल में एक पिटीशन डालेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश सरकार जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल में पार्टी बनने गई, तो सीबीआई ने कहा कि आपको कोई लोकस ही नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार पार्टी बन ही नहीं सकती। मुझे दुख है कि चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम पार्टी बन जाएंगे तो सीबीआई का क्या नुकसान होगा। सीबीआई के हाथ मजबूत ही होंगे। हम दोनों मिलकर गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक यह सच नहीं है कि सीबीआई दोषियों को सजा नहीं दिलवाना चाहती, तब तक मध्य प्रदेश सरकार

को पार्टी बनने से क्यों मना कर रही है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है और कहा है कि हमें पार्टी बनने दीजिए, लेकिन सीबीआई इंकार क्यों कर रही है, क्यों उनके लोकस को मना कर रही है? अगर मध्य प्रदेश सरकार वहां पार्टी बनेगी, तो केस मजबूत होगा। मैं कह रही हूँ कि यहां से एक प्रस्ताव पारित होकर हम 1989 का समझौता रद्द करें जिसे मैं नियम 184 के तहत लाना चाहती थी। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपके जीओएम ने क्यूरेटिव पिटीशन डालने का तय किया है। अगर संसद वह प्रस्ताव पारित करेगी तो आपका केस बलवती होगा, आपके हाथ मजबूत होंगे कि भारतीय संसद ने एक साथ मिलकर उस समझौते को निरस्त कर दिया जिस समझौते ने गैस पीड़ितों के साथ धोखा किया। क्या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को यहां विधेयक पारित कर-करके निरस्त किया गया। यह तो आर्डर भी नहीं है, यह तो आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट है और आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट को आर्डर बनाकर दिया गया।

आप क्यों मना करते हैं? अगर यह प्रस्ताव संसद पारित करेगी, तो क्यूरेटिव पेटीशन को बल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहेंगे कि भारतीय संसद जो पूरे जन-मानस का प्रतिनिधित्व करती है, उसने इस समझौते को रिजेक्ट कर दिया, तो हम इसे क्यों बनाये रखें?

उपाध्यक्ष जी, इसके साथ एक और प्रश्न है, जो बहुत बड़ा है। वह यह है कि इस फैक्टरी में आज भी 20 हजार मीट्रिक टन रसायन बचा हुआ है। उस कचरे का विनाश कैसे किया जाये, उसे नष्ट कैसे किया जाये, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फैक्टरी वाले कहते हैं कि इसे प्रीतमपुर ले जाओ। प्रीतमपुर इंदौर के पास धार का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहां इस कचरे को ले जाकर नष्ट कर दो। वहां ले जाकर नाश करने का मतलब है कि एक और हादसे की नींव रखना। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब एमआईसी आयात करके अमेरिका से आती थी और जब यह रसायन भोपाल से बंद टैंकरों में प्रीतमपुर ले जाया जा सकता है, तो यह रसायन बंद टैंकरों में अमेरिका वापिस क्यों नहीं भेजा जा सकता? ...(व्यवधान) उनके यहां बड़े-बड़े अच्छे इन्सिनरेटर्स हैं। हमारे यहां वे उपकरण नहीं हैं। उनके यहां हजारों-हजार, लाखों-लाखों मीट्रिक टन का नाश किया जाता है। हमारे यहां अगर थोड़ा सा रसायन भी नष्ट होने से पहले एक और विनाश कर गया, तो एक और भोपाल घट जायेगा। इस पूरे कचरे के नाश के लिए हमें इसे वापिस अमेरिका भेजना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पहली बार है कि मेरे बोलते समय घंटी बजी। मैं तो घंटियां खड़का-खड़का कर इन्हें सुनाना चाह रही थी, क्योंकि धीरे-धीरे लोगों की आत्मा जाग रही है। मैं अभिनंदन करती हूँ कि जीओएम ने जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों से यह लगा है कि वर्तमान सरकार की आत्मा जाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक केस में यह कहा, जिस अभियुक्त को दो साल की सजा

मिली, वह जब सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने गया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने कहा कि अब आप और 25 वर्ष लगाना चाहते हैं। 25 वर्ष बाद तो यह फैसला हुआ है। अब 15 साल हाई कोर्ट में लगेंगे और 10 साल यहां लगेंगे। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी आत्मा जाग रही है। मैं चाहती हूं, आज इस सदन से मांग करती हूं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि सारा हाउस राजनीतिक दल की सीमाओं को लांघते हुए आज यह प्रस्ताव पारित करे कि वर्ष 1989 का समझौता रद्द किया जाये और एक नया समझौता किया जाये। जिस समझौते के माध्यम से गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले, दोषियों को पर्याप्त दंड मिले। इस कचरे को वापिस अमेरिका भेजा जाये।

गृह मंत्री जी, मैं आपसे दरखास्त करना चाहती हूं कि जो मुकदमा अमेरिका के न्यूयार्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है, उसमें भारत सरकार पार्टी बने। मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनने दे और हजारों-हजार, करोड़ों रुपये की मुआवजे की राशि, वे लोग जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए गये हैं, जो हमें ठेगा दिखाते हुए गये हैं, उन्हें ब्रिटिश पेट्रोलियम का केस सामने दिखाकर उनका नया अवतार जो डाऊ केमिकल है, उससे हजारों-हजार करोड़ों रुपये का मुआवजा आप अमेरिका से लेकर आइये। दोषियों को पर्याप्त दंड दिलाइये और यहां एक नये न्याय की नींव रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सुषमा जी, अगर सदन की सहमति हो, तो क्या लंच ब्रेक को कैंसिल करके इस चर्चा को जारी रखा जाये?

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे बीच में मत रोकिये। आप इस चर्चा को जारी रखिये। ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Let the House be adjourned for one hour for lunch.... *(Interruptions)* It seems there is no consensus on this. Let the House decide.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, आप यह चर्चा जारी रखिये। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आप बहस जारी रखिये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जैसी आप लोगों की अनुमति होगी, वैसा ही होगा।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप बहस चलने दीजिए। ...(व्यवधान)



श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): उपाध्यक्ष जी, 25 साल बीत गए।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, हाउस को ऑर्डर में कीजिए। जो लोग चर्चा चलाना चाहते हैं, वे लोग उठकर जा रहे हैं। इनको भूख लग रही है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप अपनी बात रखिए।

... (व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I already requested you that the House may be adjourned for some time. ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : इन लोगों ने आपकी बात सुनी है, अब आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री मनीष तिवारी : महोदय, 25 साल बाद भी भोपाल की वह दुर्घटना रूह को झंझोर कर रख देती है और सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि मुत्क का, कौम को इतना भी न मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। आज 25 साल बाद, मैं नेता प्रतिपक्ष की व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्जत करता हूँ।... (व्यवधान) आप लोग कृपया इंटरप्ट मत कीजिए, हमने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। मुझे आज यह उम्मीद नहीं थी कि इतने गंभीर मसले पर, इतने संवेदनशील मसले पर उन बेगुनाहों की लाशों पर इस सदन में राजनीतिक रोटियां सेंकी जाएंगी।... (व्यवधान) मैं अपनी चर्चा इस आपत्ति से शुरू करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) 25 years down the road there are various aspects to this issue. ... (*Interruptions*)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : आप क्या बात कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : आप लोग थोड़ा धीरज रखिए। ... (व्यवधान) जब नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं, तो हम सुन रहे थे। कृपा करके बैठिए, सुनिए की आदत डालिए।... (व्यवधान) थोड़ा धीरज रखिए।... (व्यवधान)

13.18 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

Yashwantji, you are a senior Member of the House; kindly control your people. 25 years down the road, there are various aspects to this issue. There is rescue, there is relief, there is rehabilitation, there is remediation, there is compensation and there is punishment. I entirely agree with you.

Since the Leader of the Opposition has concentrated extensively on the legal aspects of this issue, I would also confine my intervention only to the legal aspects of the issue and leave it to my colleagues, who will speak after me, to deal with the other aspects. I am going to base my presentation only on the basis of Acts passed by this House and judgments of the Supreme Court. Some of them have been read by the Leader of the Opposition, and I would like to read them in my own way. We owe it to those innocent deaths, we owe it to a generation which has come of age, to a child who was born in 1985.

सन् 1985 में जो बच्चा पैदा हुआ था, आज उसकी उम्र 25 वर्ष है। We owe it to that generation that the truths about these events should be told in the manner that it requires to be. I will base my submission on eight questions. First of all –Why did we or did this House pass the Bhopal Relief Act which the hon. Leader of the Opposition referred to. Second - Was the litigation pursued in the United States of America or not? Third –How was the figure of 470 million dollars arrived at? Fourth – Was Warren Andersen assured a safe passage? Fifth –Why was he bailed out? Sixth –Why was he allowed to leave Bhopal and India? Seventh –Why was the extradition pursued in the manner that it was? Eighth - why was the criminal charge mitigated and where does the legal matters which were referred to stand as of today? I will divide my submission into these parts and I will answer each of these questions.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the first question which arises is that why did the Government of India, why did this House enact the Bhopal Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 and why did they frame the accompanying scheme. The hon. Leader of the Opposition is absolutely correct when she says that there were multiple claims which were being filed in different courts around the country. The Government in its wisdom at that point in time felt that it would be appropriate to consolidate all those claims and, I think, that the Statement of Objects and Reasons of the Bill which was enacted into law unanimously by this House or by this Parliament speaks eloquently of the reasons as to why the

Government decided to pursue that course of action. I would just read out one paragraph of that Statement of Objects and Reasons :

“Government has been anxious to ensure that the interests of victims of the disaster are fully protected and that the claims for compensation or damages for loss of life or personal injuries or in respect of other matters arising out of or connected with the disaster are processed speedily, effectively, equitably to the best advantage of all the claimants.

The legal position has been examined carefully with reference to the laws in the United States of America and in our country. In the light of the examination it was felt that special provision should be made for processing the claims. Accordingly, the President promulgated on the 20th day of February, 1985 the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Ordinance to confer powers on the Central Government to represent the claimants and take all necessary steps for the processing of the claims. The Ordinance also provides for the appointment of a Commissioner for the welfare of victims.”

बहुत ही बुनियादी प्रश्न खड़ा होता है कि यह वेलफेयर कमिश्नर कौन था! यह एक हाई कोर्ट रैंक का जज था। सरकार ने उस समय इस कानून को पारित किया, अपने हाथ में अधिकार लिए और एक हाई कोर्ट रैंक के जज को वेलफेयर कमिश्नर बनाकर भोपाल भेजा। दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है, was the litigation not pursued in the United States of America? ... (*Interruptions*) I wish the hon. Leader of the Opposition should have been here to hear the answer. The litigation was pursued. ... (*Interruptions*) My apologies. ... (*Interruptions*)

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): जब आपके मंत्री जी जा रहे थे, तब आपने उन्हें क्यों नहीं रोका?...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : मंत्री जी बैठे हैं, जिन्हें जवाब देना है। उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपा करके आसन ग्रहण करें। अगर कुछ कहना है तो एक माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया करके आप लोग अपना आसन ग्रहण कीजिए। जिसे बोलना हो, एक आदमी आपमें से बोल सकता है ...(व्यवधान)



श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति जी, एक भी मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं है। इतनी गंभीर चर्चा यहां चल रही है, गृह मंत्रालय से न तो एमओएस हैं न गृहमंत्री जी हैं, इस चर्चा का क्या मतलब है?

SHRI MANISH TEWARI : Mr. Chairman, Sir, the second question which arises is whether the Government of India pursued the litigation in the United States of America. क्या भारत सरकार ने वह मुकदमा अमरीका की अदालतों में लड़ा और उसका जवाब है हां और उसका प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं - सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट। I will base myself only on the public record in the form of Supreme Court judgements or the proceedings of this House and it tells a very eloquent story. This is a case *1990(1) Supreme Court Cases 613*. The judgement is delivered by the Constitution Bench. It upheld the Bhopal Claims Act which I just referred to.

I will just read two paragraphs of this judgement which will demolish the claim of the Opposition that the matter was not pursued in the United States of America. I quote :

“It has been stated that within a week after the disaster, many American lawyers, described by some as ‘ambulance chasers’, whose fees were stated to be based on a percentage of the contingency of obtaining damages or not, flew over to Bhopal and obtained powers of attorney to bring actions against UCC and UCIL. Some suits were also filed before the District Court of Bhopal by individual claimants against UCC (the American Company) and the UCIL.

On or about February 6, 1985, all the suits in various U.S. District Courts were consolidated by the Judicial Panel on Multi-District Litigation and assigned to U.S. District Court, Southern District of New York. Judge Keenan was at all material times the presiding judge there.

On March 29, 1985, the Act in question was passed. The Act was passed to secure that the claims arising out of or connected with the Bhopal gas leak disaster were dealt with speedily, effectively and equitably. On April 8, 1985 by virtue of the Act, the Union of India filed a complaint before the U.S. District Court, Southern District of New York.”

भारत सरकार ने अधिकृत तौर पर अमरीका की अदालत में अपना मुकदमा दायर किया। It further reads:

“On April 16, 1985 at the first pre-trial conference in the consolidated action transferred and assigned to the U.S. District Court, Southern District, New York, Judge Keenan gave the following directions. ”

मैं उन डायरेक्शन्स में जाना नहीं चाहता, मैं आठवां पैरा पढ़ता हूं और इस पाइंट को समाप्त करता हूं। It goes on to read:

“On May 12, 1986 an order was passed by Judge Keenan allowing the application of UCC on *forum non conveniens* as indicated hereinafter. On May 21, 1986 there was a motion for fairness hearing on behalf of the private plaintiffs. By an order dated May 28, 1986 Judge Keenan declined the motion for a fairness hearing. The request for fairness hearing was rejected at the instance of Union of India in view of the meagerness of the amount of proposed settlement.

On July 10, 1986, UCC filed an appeal before the U.S. Court of Appeal for the Second Circuit. It challenged Union of India being entitled to American mode of discovery, but did not challenge the other two conditions imposed by Judge Keenan, it is stated. On July 28, 1986 the Union of India filed a cross-appeal before the U.S. Court of Appeal praying that none of the conditions imposed by Judge Keenan should be disturbed. In this connection it would be pertinent to set out the conditions incorporated in the order of Judge Keenan dated May 12, 1986 whereby he had dismissed the case before him on the ground of *forum non conveniens*, as mentioned before. The conditions were the following.”



इसका सार यह निकलता है कि भारत सरकार अपना मुकदमा लेकर अमरीका की अदालत में गई थी और अमरीका की अदालत के न्यायाधीश ने पाया कि यह मुकदमा हिंदुस्तान की अदालत में चलना चाहिए, इसलिए यह कहना गलत है कि...(व्यवधान)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या आप अमरीका के स्पोर्ट में बोल रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : आप बैठ जाएं, यह बात आपको समझ नहीं आएगी। यह कहना सरासर गलत है कि भारत सरकार अमरीका की अदालत में मुकदमा ले कर नहीं गई। ...(व्यवधान) Yes, this is the way the judicial process works, that is, somebody wins and somebody loses. ... *(Interruptions)* Mr. Kirti, this is not sports. ... *(Interruptions)*

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): Please do not think that only you are intelligent and nobody else is intelligent. ... *(Interruptions)*

श्री मनीष तिवारी : नेता प्रतिपक्ष ने संस्थाओं पर भी हमला किया है। आलोचना करना अलग बात है और हमला करना अलग बात है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शायद सोया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि how and why did this figure of \$ 470 million come about. Was it an out of court settlement, as is being alleged by the Leader of Opposition (LoP) or was it a court interceded settlement for reasons, which are most eloquently described by the court itself in its judgement?

I will just read out two paragraphs of this judgement since the LoP had also referred to it. इन्होंने कुछ न्यायाधीशों का जिक्र किया। पांच जजों की यह खंडपीठ थी। श्री आर.एस. पाठक चीफ जस्टिस थे। उसके बाद श्री ई.एस. वेंकटरमैया थे। श्री रंगनाथ मिश्रा उसके बाद चीफ जस्टिस बने और श्री वेंकटचलैया, जिन्हें इनकी सरकार ने संविधान रिव्यू कमीशन का चेयरमैन बनाया था, वे भी उसी बेंच में बैठे थे। Justice M. N. Venkatachaliah was a part of the same Bench, which delivered this judgement. Let me just read out some of the relevant paragraphs as to how and why the court arrived at this conclusion, which is being described by the LoP as an out of the court settlement.

The paragraph 7 of the judgement states that :

“The basic consideration motivating the conclusion of the settlement was the compelling need for urgent relief...” ...
(*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD : It was a settlement and not an order.... (*Interruptions*)

SHRI MANISH TEWARI: Yes, I will come to it. The LoP, I will come to it. ...
(*Interruptions*)

It further states that :

“The suffering of the victims has been intense and unrelieved. Thousands of persons who pursued their own occupations for a humble and honest living have been rendered destitute by this ghastly disaster. Even after four years of litigation, basic questions of the fundamentals of the law as to liability of the Union Carbide Corporation and the quantum of damages are yet being debated. These, of course, are important issues, which need to be decided. But, when thousands of innocent citizens were in near destitute conditions, without adequate substantial needs of food and medicine and with every coming morrow haunted by the specter of death and continued agony, it would be heartless abstention, if the possibilities of immediate sources of relief were not explored. Considerations of excellence and niceties of legal principles were greatly overshadowed by the pressing problems of very survival for a large number of victims...”

What impelled the Supreme Court to move was the suffering of the people that between 1985 and 1989. वर्ष 1985 से 1989 तक जो बेगुनाह लोग मारे गए थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिला था। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूँ..(व्यवधान) I am not yielding. ...
(*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD : It was a fight for compensation and not for what you are describing. ... (*Interruptions*)

SHRI MANISH TEWARI: I am not accepting these interruptions, and I will not yield. ... (*Interruptions*) Please sit down. It is not Commonwealth Games. ...
(*Interruptions*)

सभापति महोदय : रिकार्ड में नहीं जा रहा है। केवल मनीष तिवारी जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री मनीष तिवारी: सभापति जी, मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार थी।...(व्यवधान) I will answer it the way I want to. ... (*Interruptions*) I will come to that. I am answering that. ... (*Interruptions*) सुनने की क्षमता होनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार थी जिसने 102 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की सरकार को जो लोग पीड़ित थे, उनकी सहायता के लिए दिया था।...(व्यवधान) and now Kirti, I will answer your question as to why did the Government agree. I will answer that question also. I am answering that question, just sit down please. ... (*Interruptions*) मैं कोट करता हूं। 11वां पैराग्राफ है। ... (*Interruptions*) Mr. Chairman, Sir, I cannot reply, I cannot speak if they cannot keep their Members in order. ... (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइए। कार्यवाही में नहीं जा रहा है।

(*Interruptions*) ... *

श्री मनीष तिवारी : संस्थाओं के दस्तावेज पढ़ रहा हूं। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी तरह से जवाब दूं।...(व्यवधान) 102 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को जो लोग पीड़ित थे, उनको राहत पहुंचाने के लिए दिया था।...(व्यवधान) Now, I will come to the question why US \$ 470 million. I would request the Leader of the Opposition to restrain her Members. I quote:

“The court asked the learned Counsel to make available particulars of offers and counter-offers made on previous occasions for a mutual settlement. Learned Counsel for both parties furnished particulars of the earlier offers made for an overall settlement and what had been considered as a reasonable basis in this behalf. The progress made by previous negotiations was graphically indicated and these documents form part of the record. Shri Fali Nariman (who was the hon. Member of the other House) stated that his client (Union Carbide Corporation) would stand by its earlier offer of US \$ 350 million and also submitted that his client had also offered to pay or add appropriate interest at the rates prevailing in the US to the sum of US \$ 350 million which raised the figure to US \$ 426 million. Shri Nariman stated that his client was of the view that the amount

* Not recorded.

was the highest it could be up to. In regard to this offer of US \$ 426 million, learned Attorney-General submitted that he would not account this offer. He submitted that any sum less than US \$ 500 million would not be reasonable. Learned Counsels for both parties stated that they would leave it to the court to decide what should be the figure of compensation.”

It was not an out of court settlement. It was a settlement which was arrived at in court. ... (*Interruptions*) Mr. Chairman, Sir, they do not have the courage to listen; they do not want to hear my answer. ... (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइए। कार्यवाही में नहीं जा रहा है।

(*Interruptions*) ... *

SHRI MANISH TEWARI: Learned Counsel for both parties stated that they would leave it to the Court to decide what should be the figure of compensation. The range of choice for the Court in regard to the figure was, therefore, between a maximum ... (*Interruptions*) आप ध्यान से सुनिये, यह जरूरी है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मनीष तिवारी के अलावा किसी की बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी।

... (व्यवधान) *

SHRI MANISH TEWARI : Sir, please bring this House to order. The range of choice for the Court in regard to the figure was, therefore, the maximum of 426 million US dollars offered by Shri Nariman and the minimum of 500 million dollars suggested by the Learned Attorney General. Ultimately, this figure of 470 million US dollars was arrived at as a result of an adjudication process by the Supreme Court. The Supreme Court of India applied its mind to the offers and counter offers and came to the figure of 470 million dollars. It was not an out of the court settlement, as has been alleged by the Leader of the Opposition.... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Was it a judicial verdict?

SHRI MANISH TEWARI : Yes. It was a judicial verdict.

* Not recorded.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : It was an order passed on the basis of an out of court settlement. Again you are reading it like that.... *(Interruptions)*

SHRI MANISH TEWARI : That is your reading of the situation. That is not my reading of the situation. It was not an out of court settlement. ... *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह समझौता था और जिस फाली नरीमन की आप बात कर रहे हैं, वह फाली नरीमन कहते हैं कि अगर कोई मुझे कहेगा कि यह केस लेना है तो मैं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बदले मैं पीड़ितों का वकील बनना चाहूंगा। फाली नरीमन यह कहते हैं। ... *(Interruptions)*

SHRI MANISH TEWARI: This was not an out of court settlement. About 470 million dollars was an adjudicated figure by five judges of the Constitution Bench of India and I would like to place that on record. The fourth question जो इन्हें बहुत परेशान करता रहा है। क्या वारेन एंडरसन को भारत सरकार ने सेफ पैसेज दिया था या सेफ पैसेज की एश्योरेंस दी थी? उसका सीधा-सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, भारत सरकार के किसी दस्तावेज में यह बात नहीं लिखी हुई है कि वारेन एंडरसन को सेफ पैसेज भारत सरकार ने कभी प्रोमिस किया था और मैं इसका प्रमाण देता हूँ। श्री एम.के.रसगोत्रा, महाराज कृष्ण रसगोत्रा, भारत के विदेश सचिव थे।...(व्यवधान) पानी नेता प्रतिपक्ष ने भी पीया था। पानी पीने पर आपत्ति मत कीजिए। ...(व्यवधान) महाराज कृष्ण रसगोत्रा भारत के फॉरेन सैक्रेटरी थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हां, अगर किसी की जिम्मेदारी थी तो यह जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने गृह मंत्री से बात की थी, इसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री का कभी कोई लेना-देना नहीं था। यह जो पिछले एक महीने से भ्रमित प्रचार किया जा रहा है, मैं उसे आज यहां खारिज करना चाहता हूँ। If at all, assume for the sake of argument, any assurance was given, that assurance does not exist on the record of the Government of India and to the best of my knowledge, no assurance was ever given by any responsible functionary of the Government of India. Let this be recorded. Now comes the question, why was Mr. Warren Anderson granted bail? ... *(Interruptions)* आप सुनिये तो सही।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): उसे सेफ पैसेज आपने दिया था।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी की बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

श्री मनीष तिवारी : मैं एक-एक करके सुना रहा हूँ।...(व्यवधान) आप इसे बैठाइये। मैं आपको बताता हूँ
Why was Mr. Warren Anderson bailed out? When the FIR was registered, rightly or wrongly, Mr. Warren Anderson was not mentioned in that FIR. Then he came without any assurance of a safe passage of the Government of India. ...

(Interruptions) आप सुनने की क्षमता रखो ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग बैठिये ।

...(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI : When Mr. Anderson came to India he was not a fugitive from the law. He was not named in the FIR. Mr. Warren Anderson came here. ... (Interruptions)

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन के संचालन के लिये आसन सर्वोपरि होता है। जब एक माननीय सदस्य व्यवधान उपस्थित करता है तो हम आसन से आग्रह कर सकते हैं। लेकिन यहां माननीय सदस्य तिवारी जी दूसरे माननीय सदस्य को बैठने के लिये आदेश दे रहे हैं। आप बैठने के लिये कह सकते हैं। इस प्रकार यह आसन और सदन की मर्यादा के विपरीत है, यह अमर्यादित भाषा है...(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI : Mr. Chairman, Sir, if I have said anything which has even remotely assaulted the dignity of this House, I offer my unqualified apology.

श्री मंगनी लाल मंडल : माननीय सदस्य सदन की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य ने इसमें सुधार कर लिया है।

* Not recorded.

SHRI MANISH TEWARI : When Mr. Warren Anderson came to India he was not a fugitive by law. The FIR which was registered was under Section 304A of the Indian Penal Code which was a bailable offence. He was arrested; he was granted bail. If after that he decides to skip bail, the CEO of a company decides to skip bail, who is responsible? Is the Government of India responsible? It is for the court to impose conditions. इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि उसे भारत से क्यों जाने दिया? Whenever there is a criminal case which is lodged against anybody and the person is arrested, what happens? He secures bail. When bail is secured, bail conditions are imposed like you surrender your passport, you will not leave the municipal limits of Bhopal, you will not leave the municipal limits of this country, etc. Government of India only comes into action to implement those bail conditions. If the court does not impose bail conditions, who is responsible? Is Government of India responsible? Is the Government sitting at the Centre responsible? This is a wild allegation which is being made repeatedly.

I will now tell you why Warren Anderson was not extradited.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति महोदय, सरकारी हवाई जहाज का उपयोग किया गया और माननीय सदस्य हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप बैठिये। यह बात उत्तर में आ जायेगी। अब आप आसन ग्रहण कीजिये।

श्री मनीष तिवारी: सभापति महोदय, पार्लियामेंट के एक सवाल का यहां हवाला दिया गया। Why was Warren Anderson's extradition proceedings not pursued? मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। There is a legal opinion by the then Attorney-General Mr. Soli Sorabjee, on the 11th of July 1998 and I would like to read it out in full.

After that, I would also read the opinion given by the then Law Minister in 2001, who is the Leader of Opposition in the other House, Shri Arun Jaitley. I would read both of them out and please do not interrupt, listen to it patiently. The Government of India is seeking – this is Mr. Soli Sorabjee, the then Attorney



General in 1998 – extradition of Warren Anderson on the ground he should stand trial in India under Sections 304, 326, 324 and 429 (sections related to culpable homicide not amounting to murder, voluntary causing grievous injury/injury resulting in death, maiming of cattle, etc.) and potentially Section 304-A (death due to rash and negligent act) read with section 35 of the Indian Penal Code.

The Madhya Pradesh High Court had confirmed the order of the Additional District Judge, Bhopal dated 08.04.1993 by which he framed charges against the accused (company officials of UCIL) under Sections 304(II), 326, 324, and 429 read with Section 35 of the IPC. The accused (Keshub Mahindra and V.P. Gokhale and others) approached the Supreme Court against the order. In its judgement known as the “Keshub Mahindra Vs. Union of India” case, the Supreme Court quashed the charges under Sections 304(II), 326, 324, and 429 read with Section 35 of the IPC. It held that the material on record could only sustain a *prima facie* case under Section 304 A which penalises the causing of death by rash and negligent acts.

The same reasoning would apply to Warren Anderson also. In these circumstances, the request for extradition of Anderson would have to be limited to Section 304A of IPC.

The extraction treaty between USA and India covers the offence of death due to rash and negligent act under its offence of manslaughter referred in Article 3. The CBI is of the view that with the available evidence, Anderson would be extraditable under the treaty with the USA. However, in the legal proceedings initiated - this is Mr. Soli Sorabjee, Mr. Chairman, Sir – by the Government of India to fix civil liability of the UCC in USA for its role in the disaster, the Court of Appeals had turned down the India’s argument that UCC can be sued in the United States.

The standard of proof in a criminal case would be higher than in a civil case. The evidence should be to the effect that Mr. Anderson had knowledge of the

design defects in the plant and violation of safety precautions. If strict proof is, in fact, a requirement of American law for purposes of determining whether there is probable cause to believe that Warren Anderson was in any way responsible for the disaster, in my view, the evidence obtained by the CBI so far would not meet such a high standard of proof.

To a specific question that whether evidence submitted by the CBI is adequate to establish a *prima facie* case against Warren Anderson under the Indo-US extradition treaty, Shri Soli Sorabjee (then Attorney General) replied,

“*Prime facie*, in my view, the evidence so far collected does not appear to be sufficient at that time.” This was the view of their Attorney General.

Now, I will read to you what their then Law Minister, the Leader of Opposition in the Upper House, in his capacity as the then Law Minister on 25.09.2001 said,

“The Supreme Court in its judgement known as the “Keshub Mahindra Vs. Union of India” case, held that the accused in the Bhopal Gas Tragedy cannot be charged for offence under Section 304 but *prima facie* appear to be guilty of rash and negligent act not amounting to culpable homicide. Therefore, any request for extradition of Anderson would have to be limited to causing death by rash and negligent act.”

This is what Mr. Arun Jaitley said –

“The Bhopal plan had some design defects and there was negligence in taking safety precautions. The design was supplied by the parent company. An inspection by engineers of the parent company pointed out a number of deficiencies in safety precautions. MIC gas was stored in violation of safety norms. When the leakage was detected, the factory staff failed to rectify the defect and stop further leakage. They also failed to warn the public which would have saved many lives.”

यह सुनने वाला है, this is Mr. Arun Jaitley saying –

“It is not the case that Warren Anderson committed any act - - that led to the direct result of the leakage of gas and consequent loss of lives and injuries.”

I will read out further:



“There is no evidence that he had knowledge of design defects and violation of safety norms and yet, he failed to take remedial measures.”

... (*Interruptions*) Please hear me out. He said: ... (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री मनीष तिवारी : आप सुनने की क्षमता रखिए।

“His knowledge has been presumed as Chairman of the parent company; there is no evidence either to show that the parent company exercised control over the day-to-day operations of the running of the plan. In view of the above, our extradition case appears to be weak. ”

अरुण जेटली जी, जो तत्कालीन भारत के कानून मंत्री थे,...(व्यवधान) उनकी ओपिनियन मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यहां पर वारन एंडरसन और सोहराबुदीन शेख की तुलना की गई। मैं उस तुलना को सही मानता हूँ और अगर सोहराबुदीन शेख किसी का आतंकवादी था, फिरौती लेने वाला था तो वह भाजपा के नेताओं का आतंकवादी था और भाजपा की सरकार का आतंकवादी था। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

श्री मनीष तिवारी : अगर विषय निषेध करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक लिया होता, It would have been allright. ... (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, क्या एक-एक घंटा एक-एक माननीय सदस्य को बुलवाएंगे, क्या ऐसा यह मामला है?...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : मुलायम सिंह जी, हम कभी-कभी बोलते हैं।

सभापति महोदय: अपनी पार्टी के समय को इस्तेमाल कर सकते हैं।

SHRI MANISH TEWARI: I will come to the next question which has been raised that why were the charges which were framed under culpable homicide not amounting to murder diluted to section 304 (A) causing death by a rash and negligent act. हमने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1996 में आई। ...(व्यवधान) मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। Unlike some people in the Opposition, I still have respect for the institutions in this country. मैं अभी भी संस्थाओं की इज्जत करता हूँ, इसलिए उन संस्थाओं ने जो लिखा है, उसे मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। 1996 की जजमेंट ने, जिसने इसे डायल्यूट किया, ठीक है वह जस्टिस अहमदी की जजमेंट थी, जस्टिस अहमदी अकेले नहीं बैठे थे, उनके साथ एक न्यायाधीश और भी बैठे थे। उन्होंने जो कहा, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ -

“Before any charge under section 304 (2) can be framed, the material on record must at least *prima facie* show that the accused is guilty of culpable homicide and the act allegedly committed by him must amount to culpable homicide. In view of section 299 IPC, the material relied upon by the prosecution for framing a charge under section 304 (2) must at least *prima facie* indicate that the accused has done any act that had caused death with at least such a knowledge that he was, by such act, likely to cause death. The entire material that the prosecution relied upon before the trial court for framing the charges, cannot support such a charge unless it indicates *prima facie* on the fateful night when the plant was run at Bhopal, it was run by the accused concerned with the knowledge that such running of the plant was likely to cause death of human beings. Mere act of running a plant as per the permission granted by the authorities would not be a criminal act even assuming that it was a defective plant and it was dealing with very toxic and hazardous substance like MIC, the mere act of storing such a material by the accused in the tank, could not even *prima facie* suggest that the accused concerned thereby had knowledge that they were likely to cause death of human beings; in fairness to the prosecution, it was not suggested and could not be suggested that the accused had an intention to kill any human being while operating the plant.”



14.00 hrs.

चेयरमैन साहब, मैं इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा के कारण मैं इसे पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 13 सितम्बर, 1996 को जब यह जजमेंट आया, उस समय सरकार किसकी थी? मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय श्री देवेगौडा जी की सरकार थी। उसके बाद श्री इन्द्र कुमार गुजराल साहब की सरकार आई और उसके बाद छः साल तक इनकी सरकार रही। क्यों नहीं इन्होंने उस समय रिव्यू-पिटीशन फाइल किया ? Why was this judgement not challenged by them? For long six years they kept quiet. This is criminal negligence. For eight years they sat on this judgement. Yes, it took the UPA Government, probably prompted by a trial court order, to review it because of a national outrage. I concede that, but that does not absolve them of the fact that they slept for eight years. आठ साल तक आप इस जजमेंट को लेकर सोए रहे और छः साल तक आपकी सरकार रही। आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि What is the status of the case? The GoM has met. A curative review petition has been filed. In the High Court a revision application has been filed. In the trial court, the Government has gone with a request to correct the errors which have occurred in this judgement with regard to the imposing of sentences.

14.01 hrs(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

सभापति महोदय, उसके साथ-साथ सी.बी.आई. को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप और प्रमाण इकट्ठे कीजिए और यह देखिए कि वॉरेन एंडरसन की एक्सट्रिडीशन हो सकती है कि नहीं। अगर इन्होंने 1996 में इस जजमेंट को चेलेंज किया होता, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा इनके ऊपर यह सीधा-सीधा आरोप है, And, in conclusion I would only like to humbly submit कि आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि 25 साल बाद, जब भोपाल गैस त्रासदी को लेकर चर्चा हुई, तो भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा नहीं हुई, बल्कि सोहराबुद्दीन की चर्चा हुई। उनकी बेगुनाह जिन्दगी पर, बेगुनाहों की मौत के ऊपर आज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं।

मैं यह उम्मीद करता था कि नेता प्रतिपक्ष, जो एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. का जो राजनीतिक एजेंडा है, उसका यहां प्रचार कर रही हैं। मैं चाहता था कि वे उसका यहां प्रचार नहीं करतीं, तो बेहतर होता। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा और बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा। यह बहुत गम्भीर और इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने दोनों तरफ के भाषणों को एक-एक घंटे तक सुना। दोनों माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। उनकी क्या बहस हुई, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। असली बात है कि वहां जनता या लोगों के साथ जो बीती, जो उनका दर्द है, उसके लिए हम अब भी जो कर सकते हैं, वह हमें करना चाहिए। चार्ज-डी-अफेयर्स गॉर्डन स्ट्रीब ने तो दगाबाजी कर दी। भोपाल के गैस पीड़ित लोगों के साथ चार्ज ने दगा किया है। चार ने तो दगाबाजी कर दी, अगर लोक सभा भी आज दगाबाजी करेगी, तो यह पांचवीं दगाबाज होगी। इसलिए हम सभी को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

महोदय, पहली दगाबाजी तो 3 दिसम्बर, 1984 की रात को हुई, जब भोपाल के अन्दर यूनियन कार्बाइड गैस के रिसाव के कारण 25 हजार लोगों का दम घुटा। फिर चाहे कोई कुछ कहे, सरकार चाहे 10 हजार कहे या 15 हजार, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दम घुटने से 25 हजार लोगों की भोपाल की सड़कों पर मौत हुई और उधर दृश्य क्या था, जब 25 हजार लोग तड़प-तड़प कर सड़क पर मर रहे थे, सड़कों पर लाशें बिछ गईं और अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। सबसे दुखद बात यह है कि वहां का मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी भाग गये। इससे और ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी भाग गये, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई अस्पताल भेजने वाला नहीं, इस पर बहस हो और इस पर इसीलिए हम संक्षेप में ही बहस करना चाहते हैं। यह दुनिया की जो सबसे बड़ी दुर्घटना थी, ये स्वीकार करते हैं?

शहर के बीच जिन्होंने कारखाना लगाने की अनुमति दी है, वह सबसे बड़ा अपराधी है। जिसकी राय से यह कारखाना बना, जिन वैज्ञानिकों से राय ली कि यह गैस का कारखाना भोपाल के बीच लगाया जाये, जिससे कभी भी कोई घटना हो सकती है, स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, दूसरे कौन हैं। एक तो ये हो गये, दागी कहिये, अपराधी कहिये, जिन्होंने शहर के अन्दर अनुमति दी और उसके बाद डी.एम. और सी.एम. भाग खड़े हो गये और बचाने वाला कोई नहीं, अस्पताल में ले जाने वाला कोई नहीं, इसलिए एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अपराधी हैं, चार सबसे बड़े दागी हैं।

दूसरे भोपाल की जनता की चार संस्थाओं ने दगाबाजी की है। सरकार भले ही 15 हजार, 8 हजार, 10 हजार बताये, लेकिन 25 हजार लोगों की मौतें हुईं, इसलिए ये भी उन दगाबाजों में से हैं, धोखेबाज़ हैं, जो इतनी बड़ी मौतों को छिपाया गया है। जहां तक कारखाना बनाने वाले लोग हैं, वारेन एंडरसन हैं, उनको गिरफ्तार करके हत्या का मुकदमा चलाने के बजाय सरकारी जहाज से दिल्ली पहुंचाने वाला बता दीजिए? सरकारी जहाज से पहुंचाने वाला कौन है, वही हम पूछ रहे हैं? प्रदेश सरकार ने भोपाल और देश की जनता के साथ दगाबाजी और सबसे बड़ी गद्दारी की है। इतने बड़े अपराधी, दोषी को सरकारी जहाज से भोपाल भिजवा दिया और भोपाल यहां से जहाज से लेकर रवाना हुआ, क्या इसको स्वीकार नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा कि अगर सही तथ्य लेकर आज लोक सभा ने भी कोई फैसला नहीं लिया तो पांचवीं दगाबाजी में हम लोग भी शामिल होंगे। यह गम्भीरता का सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि मैं संक्षेप में ही, 10 मिनट में ही अपनी बात करूंगा। एक-एक घंटे के भाषण, जनरल बात ये कर रहे हैं। यह दूसरी बात है कि जो दगाबाजी...(व्यवधान) आप हमसे मत बोलिये, हम तो आपको जानते हैं। ज्यादा किनारे किया तो ठीक कर देंगे, अगर इस तरह से दगाबाजी की। यह किसकी जिम्मेदारी है, मैं बार-बार कह रहा हूं, वरना आपके तो आने का कोई सवाल नहीं है। अगर आप अब भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, लेकिन आपने सबसे बड़ी गड़बड़ की, इसलिए यह नहीं हो पाया है। मैं बार-बार दुखी होता हूं, इनसे भी कहता हूं कि कोई बात सोचिए।

दूसरी बात भारत सरकार ने की थी, जिसमें अमेरिका की सरकार को आश्वासन दिया था कि एंडरसन का बाल बांका नहीं होगा, बताइये किसने कहा? उस समय की सरकार ने कहा। यहां की सरकार ने कहा, वहां के राष्ट्रपति को कहा कि इसका कोई बाल बांका नहीं होगा, आप चिन्ता मत करो। मैं इधर-उधर की बात नहीं करता हूं। ...(व्यवधान)

यह सब न चाहते हुए भी बोल रहे हैं। एंडरसन का बाल-बांका भी नहीं हुआ। जिसने उसको अमेरिका जाने दिया, उसके लिए भारत सरकार ने आज तक माफी नहीं मांगी। ...(व्यवधान)

चौथी दगाबाजी है - मुआवजे को लेकर भारत सरकार की ओर से केवल 714 करोड़ रुपए में यूनियन कार्बाइड से समझौता कर लिया गया। इतनी गंभीर घटना है, जिसमें पच्चीस हजार लोगों की जानें गयी हैं। इसमें उन जानों को छिपाया गया और सीएम-डीएम भाग गए। आप बताइए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, इन्होंने क्या देखा और मौके पर क्या किया? जो पच्चीस हजार लोग थे, ये गिनती कितनी भी करते रहें, आप भी भोपाल में रहे हैं, आप सब जानते हैं कि पच्चीस हजार लोगों की जानें गयी हैं। उस वक्त भी हम लोगों ने ऐलान किया था कि पच्चीस हजार लोगों की जानें गयी हैं। लाखों लोग

इसमें विकलांग हुए जो आज तक भी वैसे के वैसे हैं। आप इस चीज को देख लीजिए। ...(व्यवधान) विकलांग का मतलब अंधे, लूले-लंगड़े, एक हाथ, एक पैर या चारपाई पर पड़े हुए लोग हैं। ...(व्यवधान) आप इधर से शोर मचाए और वह उधर से शोर मचाए, लेकिन हम तो दस मिनट में अपनी बात खत्म कर रहे हैं। उनके लिए संसद क्या कर रही है? मैंने खूब कहा सोचा कि ये चार दगाबाज कह रहे हैं, लेकिन आप लोग भी पांचवे दगाबाज के रूप में शामिल न हों। मैं तो इसमें शामिल नहीं हूंगा, मैं यह कहना चाहता हूं। यह फैसला होना चाहिए कि वहां जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो परिवार बेकार हो गए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? कम से कम यह काम किया जाए। एक और बात, उनको सजा कितनी दी गयी - दो-दो साल की सजा।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भोपाल के केवल 56 लोग, 56 बार प्रभावित हुए। अभी इस बार बड़ी तादाद में आप लोग मध्य प्रदेश से हैं, आपकी सरकार वहां है, इसलिए वह इस बारे में सोचें। 56 बार में केवल 36 बार मुआवजा दिया गया, लेकिन 20 बार जो लोग मुआवजे में छोड़ दिए गए हैं, वे कौन हैं? वे मुसलमान हैं। आप याद करिए। आप जाकर देखिए। इसकी जांच करा लीजिए। दूसरे होम मिनिस्टर सदन में उपस्थित हैं। आप जांच कराइए कि 56 बार में 36 बार तो मुआवजा दिया, लेकिन 20 बार जो लोग छोड़े गए हैं, वे बीस के बीसों बार मुसलमान लोग हैं। उनके साथ यह ज्यादाती की जा रही है, क्या वे इसमें प्रभावित नहीं हुए? या तो सरकार कहे कि बीस बार उनको इसलिए नहीं दिया गया कि उनमें से कोई प्रभावित नहीं हुए। जितने 36 प्रभावित हुए हैं, उतने ही वे 20 भी प्रभावित हुए हैं। कुल 56 बार प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को छोड़ दिया गया। आज तक उनको एक पैसा नहीं दिया गया। बहस कहां से कहां पहुंच गयी? तुमने यह किया, मैंने यह किया, आपने यह किया। ...(व्यवधान) हम पूछ रहे हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं?

बिना पढ़े-लिखे लोगों को दलालों ने ठग लिया। जो पैसा बटा, उसमें भी दलाली हो गयी और बिना पढ़े-लिखे लोगों के नाम के आगे अंगूठा लगा दिया। जितना चाहा उनको दे दिया और बाकी अपनी जेबों में भर लिया। इसमें भी ठगी हुई है। क्या सरकार जांच कराएगी? ...(व्यवधान) लोगों की जो ठगी हुयी है, क्या उसकी जांच कराकर आप कार्रवाई करेंगे? हम आपसे यह जानना चाहते हैं। यहीं तक बहस में सीमित रहिए, लंबे-चौड़े भाषण नहीं करिए।

इसमें बहुत ठगी हुयी। लोगों को जो मुआवजा मिला, उसके बारे में कहना चाहता हूं। आप इस बात को नोट कर लीजिए, जो असली थे, उनमें से काफी लोग मुआवजे से वंचित रह गए। फर्जी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरा नुकसान हुआ, मेरा यह बर्बाद हो गया, मेरी संपत्ति चली गयी, इसमें उन फर्जी लोगों को मुआवजा दिया, जिनका एक रूपए का भी नुकसान नहीं हुआ।

एक और दगाबाजी भी इसमें शामिल है, दिल्ली से भोपाल तक की अदालतों ने क्या किया? आप बड़ी अदालत की बात करते थे। अदालतें भी दगाबाजी में शामिल हैं। ये अदालत का सहारा लेते हैं। लेकिन इंसानियत अलग है, अदालत अलग है।

सरकार इसलिए होती है कि जनता के दुख-दर्द में काम आए न कि जनता के साथ विश्वासघात करे और उसे दुखी करे। अदालतें बहुत देख चुके हैं। अदालत को क्या पता था। वह गवाह और सबूत के आधार पर खड़ी हुई है। इसमें गवाह और सबूत की बात थी। जमीन पर क्या हुआ, इसे सरकार जानती है। कैसे गैस रिसाव हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या इसी पर चर्चा होती रहेगी? उन्हें अब भी कुछ देना चाहते हैं या नहीं? अब भी उनके घावों पर मरहम लगाया जाहते हैं या नहीं, आज यह सवाल है। एक भी गोरा अपराधी आज तक सजा नहीं पा सका। भारतीय अपराधियों को दो-दो साल की सजा हुई। कम्पनी गोरे लोगों की है।...(व्यवधान) मैंने कह दिया कि सरकारी मुलाजिम बिठाए गए हैं, आप क्या कहेंगे। असली बात यह है कि आप एक-एक घंटे का भाषण दे रहे थे। एक घंटे उस तरफ से बोला गया और एक घंटे इस तरफ से बोला गया। सरकार आजादी के बाद से लगातार देश की जनता के साथ धोखाधड़ी और अन्याय कर रही है, एक ही दगाबाजी नहीं हुई है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, जनता के साथ लगातार दगाबाजी हुई है। लेकिन जनता से माफी मांगने और प्रायश्चित्त करने का आखिरी मौका आज है।...(व्यवधान) अगर आज भी माफी मांगते हैं तो उनके लिए काम कीजिए। आज जब जवाब दें तो जवाब नहीं बल्कि फ़ैसला कीजिए कि हम इतना मुआवजा देंगे।...(व्यवधान) सब मिलाकर 715 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। इतना जघन्य अपराध और ऐसा मजाक, संवेदनहीन एवं मानवताहीन मजाक आज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आज आखिरी मौका है।

केन्द्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक के बाद मुआवजा बांटने की घोषणा हुई। उस समय पीड़ितों की ओर से 5,000 करोड़ रुपये की मांग हुई। आज के मूल्यों के आधार पर 5,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, यह हमारी मांग है। श्री चिदम्बरम ने 21 जून को जो घोषणा की थी, वह 1300 करोड़ रुपये की थी। 1300 करोड़ रुपये की मांग और इतनी महत्वपूर्ण बहस से चले गए।...(व्यवधान) यहां केवल दो कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं।...(व्यवधान) यहां सीधे व्यक्ति बैठे रहते हैं और हम जानते हैं कि क्यों बैठे रहते हैं।...(व्यवधान) यह घोषणा हुई कि मृतकों को दस लाख रुपये, स्थायी अपंगों को पांच लाख रुपये, गंभीर

बीमारी वाले लोगों को दो लाख रुपये मिलेंगे। क्या अब भी मजाक करेंगे? अब ऐसा नहीं चलेगा। यदि करना है तो उन लोगों के लिए कुछ कीजिए। अब लोक सभा के सब सदस्य, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, मिलकर इंसानियत के आधार पर फैसला करें। इस पूरे घटनाक्रम में फिर से दलाल खड़े हो गए। दलालों ने पहले लूटा और फिर खड़े हो गए। हम आपको पक्की सूचना दे रहे हैं। जो घोषणा हुई है, उसके बाद दलालों की लाइन लग गई है, दलाल सावधान हो गए हैं। अब भी दस-दस लाख रुपये पीड़ितों को नहीं पहुंचेंगे। दस-दस लाख रुपये भी मजाक है। उस समय की महंगाई और आज की महंगाई जोड़ दीजिए। गृह मंत्री जी, कहां हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्या और मजाक करने जा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि लोक सभा भी पार्टी दगाबाजी में सिद्ध न हो। मैं बोल रहा हूं कि उसमें हम अकेले बच जाएंगे अगर दें, वरना नहीं दें।

आप सीधे मिलकर कोई रास्ता निकालिए। असली मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए गैस पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने के लिए अपराधी एंडरसन और उसके हिन्दुस्तानी मालिक डाऊ केमिकल्स पर मुकदमा चलेगा या नहीं? गृह मंत्री जी, आपको इस बारे में जवाब देना होगा। जायसवाल साहब, आप कैबिनेट मंत्री भले ही नहीं हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप यहां पर गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन आपकी भले ही बात न चले। ...(व्यवधान) सॉरी, अब तो आप कोयला मंत्री हो गये हैं। अब बेचारे के काले हाथ कर दिये। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, यहां पर होम मिनिस्टर ही नहीं, स्टेट होम मिनिस्टर भी नहीं बैठे हैं। त्रासदी यह है, नहीं ये तो दूसरे मिनिस्टर हैं। इन्हें आप जबरदस्ती घसीट रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अच्छा सॉरी।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर चर्चा है। खासकर ट्रेजिडी बेंचिस के लोग बहुत तेजी से बाहर चले गये हैं। ...(व्यवधान) लंच तो हमने भी थोड़ा बहुत किया है। ...(व्यवधान) जो शरीर हमारा है, वही शरीर उनका है। नारायणसामी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Sharad Yadav, it is the collective responsibility. Some hon. Ministers are present here. The Minister concerned will be coming. Please take your seat.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी रकम बांटने के लिए क्या केवल 66 कर्मचारी हैं? आप यह पता लगाइये कि 66 कर्मचारी किस स्तर के हैं। अब किसको बताएं।

सामी जी बेचारे तालमेल इधर से उधर करते रहते हैं। अब जाने कितना अधिकार है या नहीं। इसलिए मुआवजे का ठीक बंटवारा करना केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों की जिम्मेदारी है। अब वहां बीजेपी की सरकार है। आप भी सोचिए कि आपकी सरकार कितनी जिम्मेदारी निभा रही है। वह कितनी मांग कर रही है और कितनी मांग पर अड़ रही है। अगर मांग पूरी नहीं होगी, तो सरकार शामिल न हो और कहे कि आप सीधा बांटो। यह तरीका है, यदि इसे आप अपनायेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो दगाबाजों में आपकी सरकार आयेगी। हम लोग तो बच गये, लेकिन ऐसे ही बोलना जिससे आप भी बच जाओ। ...(व्यवधान) यह सच है क्योंकि आज ऐतिहासिक मामला है। आखिर 26 साल बाद इस पर बहस हो रही है और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपराधी एंडरसन और उसके हिन्दुस्तानी मालिक डाऊ केमिकल्स पर मुकदमा चलेगा या नहीं, इस बारे में आप बता दीजिए। उन्हें सजा होगी या बचाया जायेगा? अगर नहीं, तो लोकसभा की यह बहस बेमानी होगी और जनता तथा गैस पीड़ितों के साथ एक और दगाबाजी होगी।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, 2-3 दिसम्बर, 1984 की वह काली रात जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाये हैं, आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Rajan Sushant, as per parliamentary etiquettes you should not cross and stand before the hon. Member who is speaking. Please remember this.

डॉ. बलीराम : अमेरिकी कम्पनी यूनियन कार्बाइड की सहायक कम्पनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के भोपाल स्थित कीटनाशक उत्पादक कारखाने में 2-3 दिसम्बर, 1984 को घटना घटी। उस समय लोगों ने यह नहीं सोचा था कि हमारी सुबह नहीं होगी।

वहां जो गैस रिसाव हुआ, उससे लगभग 15000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पांच लाख से ज्यादा लोग आज भी उससे जूझ रहे हैं, अपाहिज हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है।

यह एक गंभीर विषय पर चर्चा है, लेकिन इस पर लोगों ने कितनी गंभीरता से चर्चा की यह केवल इस सदन ने ही नहीं, पूरे देश ने देखा है कि एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया गया है। सच्चाई यह है कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी का मालिक वारेन एंडरसन, जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की है, किस तरह से घटना के बाद चार्टर्ड प्लेन द्वारा उसे भोपाल से दिल्ली पहुंचाया गया और अमेरिका जाने का रास्ता साफ किया गया। निश्चित रूप से यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। उस समय वहां जो सरकार थी, निश्चित रूप से उसकी मिलीभगत रही। इतनी बड़ी त्रासदी हो, इतने बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हों, लाखों की तादाद में लोग घायल हों और ऐसे अपराधी को सरकार बचाने में लगी हो, यह बहुत ही खेद की बात है। देश के वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी ने हाल में एक बयान दिया कि वारेन एंडरसन को भगाया जाना जरूरी था, जबकि इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी एवं केन्द्रीय मंत्री वसंत साठे के बयानों के बाद अब अर्जुन सिंह के बयान से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोकहित में इन विरोधाभासी बयानों में सत्य और असत्य को सामने लाना जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें दोषी है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात सदन में रखी, वह भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती क्योंकि इतने दिनों में अगर कांग्रेस सत्ता में रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां 6 वर्ष तक हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने भी अपने कार्यकाल में इस तरह की कोई पहल नहीं की है। इसलिए आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह गंभीर मामला है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पीड़ित परिवारों को जो लाखों की तादाद में शारीरिक रूप से अपंग हो गए हैं, रोजी-रोटी कमाने लायक नहीं हैं, आखिर उनके परिजन कैसे जीवित रहें।

उनके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही हैं? दिल्ली में उपहार सिनेमा का हादसा हुआ, मरने वालों के आश्रितों को 15.-20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया गया। लेकिन जब भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उस समय केवल 25.25,000 रुपए ही मुआवजा दिया गया। वह मुआवजा भी किसने दिया, उस कम्पनी ने जिस कम्पनी को इन्होंने चुपचाप 713 लाख रुपए में बिकने दिया, हैंडओवर कर दिया था।

जब हमारे यहां कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर को जेल की सजा होती है। लेकिन उसका मुआवजा कम्पनी देती है, मालिक देता है। इस अमेरिकी कम्पनी को जिन लोगों ने भारत में आमंत्रित किया, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि सरकार अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलना चाहे तो उसके साथ कुछ शर्तें रखती हैं कि इन शर्तों को पूरा करने पर ही आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। जब भोपाल में यह कम्पनी खोली गई थी, तो उसके साथ भी सरकार ने कुछ इस तरह की शर्तें रखी होंगी कि अगर कोई दुष्परिणाम निकलेंगे या कोई हादसा होगा और लोग उसके शिकार होंगे, तो कम्पनी उसे मुआवजा देगी। अगर इस तरह की शर्तें नहीं रखी गई थीं तो निश्चित रूप से यह सरकार की गलती है और वह अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस केस में जो फैसला अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, लगभग 25-26 बरस बाद हुआ है। जो हमारे लोग मुकदमा लड़ने वाले थे, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया, ऐसा मैं मानता हूं। मुकदमा जब लड़ा जाता है, उसके 13 वर्षों बाद हम गवाह पेश करते हैं। इससे साबित होता है कि हम कितनी मुस्तैदी से इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। अभियोजन पक्ष की जो एजेंसी है, सीबीआई है, उसके वकील श्री सहाय ने अदालत के सामने तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि यूनियन कार्बाइड आफ इंडिया लि. के संयंत्र के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण यह हादसा हुआ है। सन् 1982 में एक कर्मचारी की जब मौत होती है, तो उसके उपरान्त अमेरीका से जांच करने एक टीम आती है। वह टीम यह बताती है कि इसके डिजाइन में कमियां हैं और इसे सुधारने की जरूरत है। जब इस तरह की जांच रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया, उसमें सुधार क्यों नहीं किया गया? इससे लगता है कि सरकार की निश्चित रूप से यह कमी है।

यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बाद जो फैसला आया, अभी जैसे मुख्य दंडाधिकारी श्री मोहन पी. तिवारी ने 23 साल बाद फैसला सुनाया। उस फैसले में उन्होंने सात लोगों को दोषी करार दिया है। एक-एक लाख रुपये से अधिक का उनके ऊपर जुर्माना और दो साल की सजा सुनाई गयी है। लेकिन सबसे विडम्बना की बात है कि उसके तुरंत बाद 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। आज जहां तक वारेन एंडरसन की बात है, कैसे वह



भागा, कौन उसके भागने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमारी सरकार इतने दिनों में उसका प्रत्यर्पण अब तक नहीं करा पाई है।

अभी हमारी प्रतिपक्ष की नेता कह रही थीं कि इंग्लैंड और अमरीका के जहाज जिनसे तेल के रिसाव के कारण प्रदूषण हुआ मैक्सिको की खाड़ी में, अमरीका ने उससे भारी भरकम रकम ली। लेकिन इतने बड़े हादसे में, जहां इतने गरीब लोग मरे, इतने बड़े पैमाने पर लोग मरे, जो घायल हुए उनका तो आंकड़ा ही नहीं है, जो उसके दुष्परिणाम से आज अपंग हो गये, उनका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। क्या यह सरकार अमरीकी सरकार से इसके लिए संघर्ष नहीं कर सकती है, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती है। निश्चित रूप से हमारी सरकार की यह कमजोरी है। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात को लम्बा न कहते हुए, आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आज भी जो पीड़ित परिवार है, जो लोग मर गये हैं, उनके अलावा जो लाखों की तादाद में अपंग हो गये हैं लंगड़े-लूले हो गये हैं, काम करने लायक नहीं हैं, ऐसे लोगों को कम से कम दस-दस लाख रुपये का मुआवजा देने की जरूरत है ताकि उनकी भी जिंदगी चल सके। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं तथा सदन से कहना चाहते हैं कि इसी सदन में तमाम ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जो विनाशकारी होते हैं, जैसे परमाणु-डील की बात आई थी, तमाम जगहों पर हादसे हुए, इंग्लैंड में भी एक हादसा हुआ था, लाखों लोग उसमें मरे थे। ऐसे जो निर्णय हैं, उन्हें हमें सोच-समझकर लेना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि हमें फिर से ऐसे हादसे का शिकार न होना पड़े।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, मैं यहीं से अपनी बात रखना चाहता हूँ और इसके लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ।

सभापति महोदय : ठीक है, बोलिये।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, प्रतिपक्ष की माननीय नेता ने और समाजवादी पार्टी के हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने सभी पक्षों को उद्घाटित किया है। सरकार की ओर से जवाब आयेगा लेकिन सरकारी पार्टी की ओर से जो बात रखी गयी है उसमें पता नहीं चल रहा था कि अमरीका का बचाव हो रहा है या कांग्रेस की ओर से कंपनी का बचाव हो रहा है या एंडरसन का बचाव हो रहा है या कहीं गलती हुई है तो उसका परिमार्जन न होकर के उससे मुक्त होने की बात हो रही है। वर्ष 1996-97 का उल्लेख करके कहा गया कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी।

यह बात सही है कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की समर्थी सरकार थी, श्री देवेगोड़ा और श्री इन्द्रकुमार गुजराल की सरकार थी। उससे पहले 1995 में कांग्रेस की सरकार थी। 1984 में 3 और 4 तारीख की रात में, जो अब तक औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी मानवीय त्रास्दी हुई थी, उसके बाद थाने में जो प्राथमिकी अंकित की गई और बाद में सीबीआई को यह मुकदमा हस्तांतरित किया गया, उसके बाद जितनी धाराएं लगाई गई थीं, उन पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि 1995 में एक अध्यादेश आया था कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, वे इस केस में पार्टी नहीं हो सकते हैं और इस केस में केंद्र सरकार पार्टी बनेगी। उस अध्यादेश द्वारा पीड़ित लोगों को अपनी बात अदालत में रखने से वंचित किया गया। यह अध्यादेश किस परिस्थिति में आया था, जिसे 1995 में कानून के रूप में इस सदन द्वारा परिवर्तित किया गया। जब वह अध्यादेश कानून में परिवर्तित हो गया, तो 1996 में मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया और कहा गया कि भारतीय दंड संहिता 304 (a) के तहत यह मुकदमा चलेगा। सरकार को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि 1995 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। 1996-97 में उसकी समर्थित सरकार थी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया। अभी जो निर्णय आया है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (a), 338, 337 और 336 के आलोक में आया है। यहां उत्तर प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल श्री विजय बहादुर सिंह बैठे हैं, वे हमें करेक्ट करेंगे कि कोई और सैक्शन था या नहीं था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन धाराओं के चलते निचली अदालतों से जो फैसला आया और 1995 में जिस अध्यादेश को परिवर्तित करके यहां कानून बनाया गया और 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि 304 (a) के तहत ही मुकदमा चलेगा, जिसमें अधिकतम दो वर्षों की सजा हो सकती है। अगर वाहन चलाते समय चालक की लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में अगर कोई मर जाता है, तो उसमें

अधिकतम सजा दो वर्ष की होती है। भोपाल में जो 15 हजार आदमी मरे, 15 हजार की संख्या रिकार्ड में अभिलिखित है और जो मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि 25 हजार संख्या है, जिनकी गणना सरकार के अभिलेख में नहीं की गई है और जिन्हें अभी तक मुआवजा देने की सूची में नहीं रखा गया है। इतने लोगों की मृत्यु हुई और ये काल के गाल में समा गए, इतनी बड़ी मानवीय त्रास्दी हुई और इन लोगों को मारने वालों की सजा केवल दो साल दी गई।

महोदय, जिस समय अदालत में निर्णय हो रहा था, उस समय हजारों की संख्या में गैस पीड़ितों के आश्रित लोग और जो विकलांग हो गए, वे बाहर एकत्रित थे। जब दो वर्ष की सजा दी गई और मामूली राशि का दंड सुनाया गया, तो बाहर लोगों ने शोर मचाया कि फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो।

किस को फांसी दो, एंडरसन को फांसी दो, वह कहाँ चला गया? 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में भारत सरकार की सीधी हिस्सेदारी थी। अमरीका से नहीं डरे, क्यों नहीं डरे क्योंकि वहाँ कोई कम्पनी नहीं थी। जो कम्पनी हमें एप्रोच करती। किकबैक्स नहीं मिलता। उस समय हमारी राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का भी सवाल था और उसी को हम लक्ष्य करके चल रहे थे। हमने अमरीका का मुकाबला किया और बांगला देश पूर्वी पाकिस्तान से मुक्त होकर बना। एंडरसन भागा नहीं, उसे भगाया गया। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ठीक ही कहा कि उसे रात में नहीं, छिपा के नहीं, टैक्सी में नहीं बल्कि सरकारी हवाई जहाज में दूल्हा की तरह भगाया गया। उसे 7 दिसम्बर को भगाया गया। सरकार बताये कि यह घटना जब 3-4 दिसम्बर की रात में घटी और 4 दिसम्बर, 1984 में स्थानीय थाना में जो कांड अंकित हुआ था, उसमें एंडरसन अभियुक्त था कि नहीं? अगर एंडरसन अभियुक्त था तो जिस किसी ने बिना अदालत की परमीशन के भगाया, चाहे उस समय का मुख्यमंत्री रहा हो, या कलैक्टर रहा हो, चाहे एस.पी. रहा हो, उस समय एंडरसन के खिलाफ थाना में जो कांड अंकित किया गया था, अगर किसी धारा के अंतर्गत वह अभियुक्त था तो अब तक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? सब को केस में रखा जाये। जो निर्णय हुआ है, अब कुछ लोग रो रहे हैं। कांग्रेस का जो जवाब आया, वह पुरुषार्थ का जवाब नहीं है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का जवाब नहीं है। वह राष्ट्रीय शर्म का जवाब है। कुछ तो शर्म करो, एंडरसन का बचाव करते हो, सीना तानकर कम्पनी का बचाव करते हो।

*(Interruptions) ...**


सभापति महोदय : ऑनरेबल मैम्बर ने पीछे बैठकर जो कहा है, वह रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

* Not recorded.

श्री मंगनी लाल मंडल : सभापति महोदय, सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की और अभी कहा गया और समाचार पत्रों में छपा है कि सरकार ने एक क्यूरेटिव पैटीशन उच्च न्यायालय में दाखिल की है। जब 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 304ए के तहत मुकदमा हो सकता है तो उसके बाद 1996 और 1997 में कांग्रेस की बैसाखी पर उस समय की सरकार चल रही थी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो ऑनरेबल मैम्बर बैठकर पीछे से बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

... (Interruptions) ... *

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, जो निर्णय हुआ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इनके लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें न्याय में विलम्ब हुआ। सरकार आपकी और रोते हैं आप। आपकी सरकार लगातार है। कहते हैं कि एनडीए की सरकार पांच साल रही थी। पांच साल का हिसाब कितने वर्षों में से लेंगे। एनडीए की सरकार ने एंडरसन की गिरफ्तारी के वॉरंट को तामी  करवाया था, यह श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बताया है। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर रोते हैं। यह घड़ियाली आंसू हैं। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी के ऊपर आंसू बहाकर समझते हैं कि जनता को ऐसा कहकर कोस लें कि यह ऐसा मामला है, जिसमें न्याय में विलम्ब हुआ और व्यावहारिक तौर पर न्याय नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय को दफना दिया गया है। यह किसने कहा? यह हमने नहीं कहा, हमारे नेता श्री शरद यादव जी ने कहा, प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने नहीं कहा, श्री मुलायम सिंह यादव ने नहीं कही, यह बात वीरप्पा मोइली जी ने कही है, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं। यह केवल उन्होंने ही नहीं कहा है, यह एटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने कहा है। उन्होंने कहा कि 304ए में तो अभियुक्तों को इससे ज्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है। यह निचली अदालत के वकील भी जानते हैं। लेकिन आप तो भारत सरकार के एटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने कहा है कि गैस कांड के आरोपियों पर अपराध नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1996 में जो फैसला हुआ था, वह कानून के हिसाब से गलत था। फैसले में काफी विरोधाभास है। लॉ मिनिस्टर कुछ और, उसी के समर्थन में एटॉर्नी जनरल कुछ कहते हैं। सरकार आपकी है, लेकिन एंडरसन का प्रत्यार्पण आप नहीं कर सकते हैं। आप एंडरसन को ले आइए। हम समझेंगे कि आपकी सरकार राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सम्मान और सार्वभौमिकता को संरक्षित करने वाली सरकार है। इसने एंडरसन को लाकर दिखा दिया। जब अदालत से फैसला आया तो अमरीका ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि एंडरसन के प्रत्यार्पण करने का कोई सवाल नहीं उठता है। एंडरसन का प्रत्यार्पण क्यों नहीं हुआ? सरकार के दो-तीन विभागों में लड़ाई

* Not recorded.

चल रही है। अभी आपने एक नियमन दिया। मैं उस नियमन का प्रतिकार नहीं करना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कलैक्टिव रिसपोन्सिबिलिटी सरकार की है। महामहिम राष्ट्रपति ने प्रत्येक मंत्री के विभाग निर्धारित किए हैं। यदि वह मंत्री जिनकी जवाबदेही तय है, सदन में आसन की परमीशन से नहीं रहेंगे,...(व्यवधान) आपसे परमीशन नहीं ली है और यहां से गायब हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी, बताकर गए हैं। उन्हें अपर हाउस में कुछ काम है, इसलिए बताकर गए हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, एंडरसन का प्रत्यर्पण क्यों नहीं हो सका? अमरीका ने कहा कि साक्ष्य नहीं है। इसलिए प्रत्यर्पण नहीं होगा। जब विदेश मंत्रालय को जवाबदेह ठहराया गया, यह अखबार में बात छपी है कि विदेश सचिव ने मंत्री समूह की बैठक में कहा कि विदेश मंत्रालय इसके लिए जवाबदेह नहीं है।

सरकार को इसके लिए साथ देना चाहिए था ताकि अमेरिका को हम संतुष्ट कर सकते और उसका प्रत्यर्पण होता। साक्ष्य देना किस का काम था, एनडीए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई या सीपीएम का काम था, साक्ष्य जुटाना सरकार का काम था। यह सरकार लगातार इतने सालों से हैं, सरकार ने साक्ष्य क्यों नहीं जुटाया? ...(व्यवधान) हमारी पार्टी के एक वक्ता श्री अर्जुन राय जी और हैं, उनका भी नाम है।



सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि नये सिरे से जो क्यूरेटिव पेटीशन दाखिल की है और जो भी राष्ट्रवाद नीति आपने बनाई है, उसका जो भी नारा हो, जितना भी सक्षम हो, एंडरसन को लाने की कार्यवाही नये सिरे से होनी चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके मुआवजे की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। जिन लोगों को दो साल की सजा मिली है, उन्हें फांसी की सजा देने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने हवाई-जहाज से एंडरसन को भगाया, जिनकी मिलीभगत रही या जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें भागीदार हैं, उन सब को कानून द्वारा सजा मिले, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पर सरकार से जवाब चाहूंगा।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, before I begin my speech, I just want to make a little request. My track record will speak for itself, the bell goes and I sit; I am one of those disciplined Members, who has never breached the bell. I breach you to give me a little more time today because this is an issue of such seminal importance and I have some observations and suggestions, which I think, the House might find enlightening. So, give me a little more time. The Biju Janta Dal has enough MPs, I think, in this House is to warrant a little more time.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, I am sorry. There are so many speakers to speak on this subject. So, please confine yourself to the time allotted to your party.

SHRI PINAKI MISRA : Mr. Chairman, in 26 years, since the night of 2nd and 3rd of December, 1984, I think this must be the 26th time that this august House is debating or discussing the Bhopal gas tragedy. It has gone on to become an annual ritual. Every year, this happens around December 2nd and 3rd because the Parliament is always in Winter Session during this period. Therefore, there is a ritualistic outpouring of sorrow; there is a ritualistic outpouring of anguish; there is a ritualistic outpouring of what has not been done. It is like a collective lament that has gone on in this House.

Sir, today we meet yet again to discuss this issue because of an immediate provocation, which is that a judgment has come after almost 25 years by which three people have been indicted and sentenced to two years, which everybody has found appalling; that for the death of 16,000 people, how can you have a two year sentence. That is the provocation for this House discussing this issue today.

Along with that, there is also an issue of the woeful compensation package, which I have heard, being discussed in the House. There is the toxicity aspect which continues to obtain in Bhopal, which continues to poison the air, the water and the soil there, and which continues to plague generation after generation.

Sir, there were stirring speeches by Shrimati Sushmaji and from the Congress Benches, by Shri Manish Tewari. I cannot match their stirring rhetoric. But I would confine myself to facts, which is what I am trained to follow. The Leader of the Opposition mentioned the United States of America; the Leader of the Opposition mentioned the 20 billion compensation that has been set apart at the instructions of the President of the United States, by the British Petroleum for the oil leak, which has taken place recently in America. I would like to inform the House that America is the only country in the world that has an income tax on global income. Everywhere else, there is tax on income in the country of business. They place a very high premium on their passport; they place a very high premium on the US citizenship; and which is why no matter where you may earn in the world, you have to pay income tax in America. No other country has this. The American Secretary of Treasury was asked: "Why is this so? This is a very incongruous practice and it amounts to double taxation of income."



15.00 hrs.

He said it is because we have placed a very, very heavy premium on our passport. Anywhere in the world if there is an American in trouble, a US citizen is in trouble—it could be the jungles of Colombia, it could be the Himalayas in Nepal, it could be the Tehran hostage crisis in the American Embassy—the American Department, the US Government will move every sinew, will make every effort to ensure that, that the US citizen is bailed out of his jeopardy. That is the high price that the Americans have placed on human life there.

What is the price we, as an Indian State, have placed on our citizens here? That is the seminal question that this House has to ask itself.

15.01 hrs

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

Mr. Chairman, I am reminded of the fact that one month before this horrible tragedy took place in Bhopal I look to the left for this and I do not wish to be partisan-- roughly 15,000 to 25,000 Indian citizens, Sikhs, were massacred on the streets of India. People say it was State sponsored. People say the State turned a blind eye. I am not here to pass judgement. That is a fact. Therefore, human life was very cheap on the streets of India during those three or four day in Oct-Nov., 1984.

Now I look to my right. In 2002, again thousands of people were massacred in Gujarat. People say it was an act of State carnage. Some people say it was an act of State omission. I do not wish to make any statement on this in terms of a value judgement. Once again we have found that human life was cheap. From 1984 to 2010, today, human life continues to be cheap in India.

All our laws, whether it is rail accident compensation, whether it is road accident compensation, look at the way these are measured. Can you measure these in terms of the movie Erin Brockovich, which, I think, most of us are guided by where billions of dollars were paid by the American companies in the event of any man made disaster that they were responsible for? That does not obtain in India because our law of Torts unfortunately, Mr. Chairman, is extremely weak

and that is the context I think in which the 4.70 million dollars, which was decided by the Supreme Court in 1989, was found to be perhaps, adequate for the compensation to be paid to those victims.

The tragedy is, the then Government of India did it. Within six months, there was another Government in power. The Congress was in Opposition. There was another Government where my friends from the right were supporting that Government. That Government did not lift a little finger to revisit that issue then. I come back to the fact that every political party of major hue has been in power in this country since 1984, since this unfortunate disaster took place.

Why are we in 2010, today, making a laughing stock of ourselves in the international comity of nations by trying to reopen a settlement arrived at in 1989? Do we think it is possible? It is legally not permissible. I am saying so on the floor of this House. It is not permissible to revisit an agreement which had been reached in 1989. It is not possible today to file a curative petition. The Government may have filed a curative petition. It will be laughed out of court. Internationally, we will be a laughing stock if after 14 years from 1996 to 2010, the Supreme Court today reviews its own judgement, which it passed in 1996. Mr. Chairman, we will be a laughing stock.


Now, Mr. Chairman, therefore, I say with great respect we have to today decide in this House henceforth whether we are going to place a larger premium on the life of Indian citizens in our country. The Indian State has to do something about it. This Parliament has to do something about it.

The second issue is toxicity. Now, I was really appalled, I was saddened by what Sushma Ji said today. Today, we pride ourselves on being a nuclear State. We want to sit at the nuclear high table, Mr. Chairman. We are nodding terms with the big five. The Leader of the Opposition here says that we are not able to take care of some toxic waste here which, by the highest possible account, is going to take about Rs.10,000 crore, about two billion dollars to clean up.

The Leader of the Opposition says that we must beg the Americans, because they have the incinerators and we do not have the incinerators in India, for this toxic waste to be shipped back there. Is this the India that we talk about, which has arrived on the international high table? I am appalled that the Leader of the Opposition had to make this suggestion today.

Again, I am appalled that successive Governments for the last 26 years have allowed this toxic waste to lie there. Eminent industrialists in this country have personally offered to clean it up. I know for a fact that Ratan Tata has made bold in public to say that Tatas would pay for it, please allow us to do it. At least, let some Government get up and say, you do it; you have the money; you have the philanthropy; and you please do it.

Why does some Government not get up and say that at least? Yet another GoM has been established now. This must be the 50th GoM that we know of in the last six years. Like the 49 before this, nothing will come out of this new GoM either unless there are some constructive suggestions that are placed on board.

Mr. Chairman, I will not take much time – you are looking at me. I know that I am not wasting the time of  this House. On the quantum of punishment, let me put it straightway that this is a laughing matter whether Shri Rajiv Gandhi knew it. Frankly, within a month of his mother's death Shri Rajiv Gandhi was too shocked at that point of time to be Machiavellian enough to send somebody away to any part of the world. Most of the Congress Party members in any case hate Shri Arjun Singh. So, all the blame has been put on him now.

All I wish to say in this regard is that I do not think extradition of Mr. Warren Anderson from day one was ever a serious option. Shrimati Sushma Swaraj was right in one thing that like Mr. Ottavio Quattrochi, Mr. Warren Anderson, both the extradition attempts were from day one never destined to succeed. Therefore, what is the point today in our lamenting and saying let us ask President Obama to send Mr. Warren Anderson back? Is this how the rule of law obtains? Is this how the rule of law is supposed to obtain? Is this how you are

supposed to ask Heads of States who are on goodwill missions that they send back a 85 year old man to face trial here? This is not the way things should be done now, if this GoM is to be a serious GoM.

There is no shortage of funds. Shrimati Sushma Swaraj is wrong when she asks whether money grows on trees. There is enough money here. We do not have to go back and cry before Dow chemicals that we do not have three billion, four billion, seven billion, ten billion dollars – whatever it will cost – in order to ensure that people who have suffered for generations have to be given rehabilitation. We do not need to beg before anybody. I think the time has come for India to stand proud, stand bold. Yes, mistakes have been made. But mistakes have been made across all political shades in this House. Let him cast the first stone who has not sinned.

Shri Manish Tewari is right that in 1998, 1999, 2000, 2001, repeatedly with my friends on the right, their Law Minister and the Attorney-General have opined exactly what the earlier Law Minister and the Attorney-General have opined. The law does not change because political parties change in power. The law remains the same. Therefore, you will find Attorney-Generals there, Attorney-Generals here, Law Ministers there, Law Ministers here have to abide by the law. They have all said the same thing. So, let us not make a laughing stock of ourselves. Let us shear the rhetoric off. I beseech the House that let there be no more rhetoric. Let us actually sit down and apply our minds and decide what can be done for those miserable people.

Mr. Chairman, with great respect I say this. I do not know whether the nation and all political parties have been inefficient, have been apathetic and whether there has been a lack of political leadership. I leave it for this House to judge, for the nation to judge.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, with pain and anguish I rise to articulate my views and the views of my Party, the Communist Party of India with regard to the gas tragedy in Bhopal.

A diabolic industrial disaster occurred on December 23, 1984. What was the actual figure of death and how many people have been affected by the disaster, is very difficult to say. It has not yet been ascertained. Different Government agencies, administrations are giving different figures. Some independent agency has already reviewed it. According to their opinion, more than 20,000 people died and not less than half a million people have been affected. What was the gravity of the disaster is known to everybody. It was a national shock.

Sir, I am not going into the details of all the incidents that had occurred at that time. But my point is that the GoM was constituted and it was the expectation of the people that the GoM would take some immediate and important decisions, and respond to the problems and address the problems in the prevailing situation. But I deplore the recommendations made by the GoM headed by hon. Home Minister, Shri P. Chidambaram.

What has been said with regard to compensation and rehabilitation of the Bhopal gas tragedy victims is miserable and it would not address the problem. What is said? What was the recommendation in this regard? According to the GoM recommendations, less than 10 per cent of the total victims' count of 5,72,241 would be eligible for compensation. Those who are eligible include 5,295 cases of death for Rs. 10 lakh compensation, 3,199 cases of permanent disability for Rs. 5 lakh compensation, 33,672 cases of temporarily injured for Rs. 3 lakh compensation and 42 cases of simple injuries for Rs. 1 lakh compensation. This does not even meet the immediate expectations of the victims or their families.


Not only that, when was the GoM constituted? The GoM was constituted immediately after the verdict was delivered by the Bhopal court. What has been

stated in the verdict has been mentioned by several previous speakers. But I must say that it was a travesty of justice and mockery of investigation and trial in case of that diabolic industrial disaster.

The GoM did not even raise the issue of how the CBI acted in such an incompetent manner and how the charges have been diluted. They have not even charged them under section 302 of IPC. Who is responsible for that? Is it not our expectation that the GoM will touch this point also? Nothing is said about how these charges have been diluted. They have deliberately skipped the issue of who allowed safe passage to Warren Anderson of Union Carbide Corporation. The whole nation is pondering over it. This is not a simple matter. This is a matter of national concern, but the GoM did not even touch upon it. They just skipped this issue deliberately. So, it is very regrettable and I am very sorry for that.

Finally, what was the recommendation of the GoM? They have recommended spending money from the Public Exchequer to address the issue of toxic contamination. The money of Public Exchequer is the money of the taxpayers. It is the money of the people as a whole. How can Public Exchequer be used for compensation?

It is not Anderson and it is not the culprits; but it is our exchequer that had to pay the compensation in this regard. This is a matter of dissatisfaction, and a matter of anguish.

Why did the Government of India wait for so long, that is, till the Bhopal judgement? Why did they wait for so long? It may be attributed to signal to the US investors and the USA  with whom the UPA-II is going to build a strategic relationship. This might be the main cause for the delay.

We have been discussing this matter in the backdrop of the Nuclear Liabilities Bill. So, I think that it would be very serious, and it will be very injurious and harmful to our country if we deal with this subject in this manner. Hence, my complaint / charge against this GoM.

What would be the solution to it? The solution to this problem cannot be made by one Party or the Government of the day or only by the Opposition. Therefore, my Party urges upon this Union Government to convene an all-Party meeting in this regard to solve / sort out / tackle this matter. This is a National issue, and this is not a very simple issue. All the people of our country are thinking over it as our prestige and dignity is related to it. More than 20,000 people have been killed, but the punishment awarded to them is nothing. It is a mockery. Therefore, seriousness is required in it. I think that the hon. Home Minister will address not only the anxiety of all the Members in this House, but will also convince the nation that he is very serious; he is bold enough; and he is willing to stand to the occasion and will not succumb to the pressure of the USA or is not to please the US investors.

With these words, I express my views.

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) : Hon'ble Chairman, sir, I thank you for allowing me to participate in the debate on an issue of seminal importance – the Bhopal Gas Tragedy of December, 1984. Sir, the year 1984 was a year full of cataclysmic events. It was a tragic year. Successive generations have been affected by the fallout of these tragedies.

Sir, in June 1984, the holiest shrine of Sikhs, the Golden Temple was attacked. It was a Himalayan blunder committed by the then Government. The Golden Temple is the Mecca of Sikhs. Operation Bluestar scarred the hearts and minds of the Sikhs forever. In November 1984, Smt. Indira Gandhi was assassinated. And then, thousands of innocent Sikhs were butchered in cold blood throughout India for several days. It was followed by the worst industrial accident in the history of the world – the leakage of the lethal Methyl Isocyanate gas from the Union Carbide Pesticide Plant in Bhopal in the night of December 2-3, 1984. Over 20,000 people lost their lives in this catastrophe and lakhs of people were injured due to the ill-effects of this toxic gas. Those who survived were condemned to a life of living-death. They were maimed and handicapped for life. Children born after this incident had congenital diseases. Hence, 1984 was a black year in the history of the country.

Sir, what is more tragic is the fact that the Government of the day failed to rise to the occasion. It miserably failed to provide any relief or succour to the gas-victims. Instead of coming to the aid of the hapless victims, the Government reached an out-of-court settlement with the Union Carbide company. The people of Bhopal had great hopes that the Government would provide justice to them and bring the perpetrators of this crime to book. They had reposed their faith in their elected representatives. But, the Government of the day dashed all their hopes to ground. Injustice was done to the hapless victims. A paltry sum was agreed upon by the Government as compensation for the gas-victims.

*** English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.**

Sir, lakhs of people had lodged criminal cases against the Union Carbide accusing the company of manslaughter and culpable homicide. But, with one stroke of the pen, the Government of the day snatched away their hopes of ever getting justice or bringing the guilty to book. Claims for compensation worth thousands of crores had been filed by the hapless victims of this gas-tragedy against the Union Carbide company. However the Government settled for a measly amount of 615 crores only as compensation to the gas-victims. This paltry sum was an insult to the sacred memory of gas-victims. 25 years have passed and much water has flown down the Ganges. But, even this paltry compensation has not reached the genuine victims. Those responsible are roaming scot-free. Those at the helm of affairs all these years have cheated the victims. The victims have been left in the lurch. The Government should have put a heavy premium on the lives of our citizens who had suffered in this horrible tragedy. Instead, there was a sell-out. Thus, the Government abdicated all its responsibility.

Sir, this was a tragedy of immense proportion. The Union Carbide Chief was responsible for the lack of safeguards at the Bhopal Plant of Union Carbide. Instead of putting him behind bars, Anderson was granted a safe passage out of the country. He was allowed to flee from the country. It was a treacherous act on the part of the Government.

Sir, after the assassination of Smt. Indira Gandhi, thousands of Punjabis and Sikhs were massacred throughout the country. It was a blot on the secular credentials of the country. Sikhs were butchered in cold blood. Tyres were put around their neck and they were burnt alive. Petrol was put in their mouth and they were set on fire. It was a barbaric genocide of Sikhs. However, the culprits have not yet been brought to book. 25 years have passed but the victims of anti-Sikh riots are still crying out for justice. In this august House too, members expressed their protest on this sensitive issue. However, the Government connived with the CBI and gave the guilty a clean chit. Those who were culprits

were granted 'Z' security and other facilities were lavished on them. These criminals are leading a life of comfort and affluence.

Sir, there was a time when India was considered a 'Golden Bird'. However, today the country finds itself in a sorry state, courtesy the Government. People, who are responsible for killings, are roaming scot-free. It is a travesty of justice. It is a mockery of the rule of law.

Sir, at the time of Operation Bluestar, a large number of Sikhs protested against the Government and went into self-exile out of disenchantment with the wrong policies of the then Government. The names of these Sikhs were put in a Black List. The Government refuses to scrap this Black List. These Sikhs cannot come back to their own country. These people have been dubbed anti-nationals. However, the fact is that they were merely protesting because their religious feelings had been hurt. The Government had brought tanks inside the Golden Temple. Naturally, the Sikhs were enraged. Sir, I urge upon the Government to scarp this Black List immediately and allow these Sikhs to come back to their own country with honour and dignity.

Sir, the Government should also provide a handsome amount as compensation to the victims of Bhopal Gas Tragedy. Anderson should be extradited and stringent punishment should be meted out to him for his acts of omission and commission.

Sir, I have another apprehension. The Government wants to set-up N-power plants in the name of development. However, it is a double-edged sword that cuts both ways. What will happen if there is a nuclear mishap in such a N-power plant? It can be catastrophic.


MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : The Government must take adequate safeguards if it intends to pursue its present policies. Otherwise, generations to come will suffer irreparable damage.

In the end, I urge upon the Government to bring to book the culprits of Bhopal Gas Tragedy. It is a festering wound that time has failed to heal. Also, those who were involved in the gruesome anti-Sikh riots of 1984 should be given exemplary punishment.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, this House in the past witnessed a number of debates on this issue. Today we are discussing the Bhopal Gas Tragedy on a different context. In the past, we had discussed on this at length when there was a settlement, when there was disaster in 1984 when after the elections, the Government came to power in the Eighth Lok Sabha. Today we are discussing when there was an outrage throughout the country when on 7th July, the Bhopal Court gave a judgment. It was the mockery of the judgment and lakhs and lakhs of gas victims are yet to get justice.

This was the biggest industrial accident which had ever happened in our country. The entire episode of how Bhopal gas accident was handled shows the connivance of successive Governments with American multinationals in deflating their culpability.

Culpability was established by a Committee that was constituted by the Government of India just after this disaster under the Chairmanship of the then Director-General of CSIR Mr. Varadarajan. This Committee went into the accident in-depth and established the culpability, giving reasons why that accident took place and what the defects were and whether the safety rules were properly observed or not.  We were surprised when in 1996 Supreme Court gave judgment that they changed the Section from 304 to 308 by diluting the culpability of the accident.


Union Carbide Corporation is a subsidiary company which was set up in Bhopal. Six months before the 2nd of December when this disaster took place, the Safety Audit Committee undertook a study of the safety aspect of the Bhopal Unit of the Union Carbide Corporation. That Committee also found out the defects in the unit and suggested some remedial measures. During the six months before this accident took place, there were a number of accidents and even workers died. But the company did not take any care to rectify the defects. It was not that it

happened suddenly. Why were safety measures not undertaken by the company? We were the safety norms violated?

The poisonous gas was emitted by one of the tanks which had more than 40 tonnes of MIC stored in it. Because of that poisonous gas, 2500 people in and around the UCC unit in Bhopal died. Those were slum areas. Poor people were living there nearer to the unit. More than five lakh people were exposed to the poisonous gas. Immediately 2500 people died and in subsequent years, the figure of dead crossed 22,000.

The Chief Executive Officer of the company Mr. Warren Anderson came to the country. Before he came here, an undertaking was given by the Government of India that Mr. Anderson would be given a safe passage.

He came; he was arrested. Immediately he was released. Not only released, he was brought to Delhi; he was accompanied by two officers of the State Government. He went back to New York. He is the main culprit. When he was arrested, why was he released? He had not even applied bail. He was sent to Delhi by Government aircraft; and then, to New York.

Congress Party was in power. Without the  knowledge of the Prime Minister of the country, how could a Chief Minister of a State take such a decision? Has it been done at the behest of the Prime Minister of India? Was there any agreement with the President of America that Mr. Anderson could come, and then, he would be given a safe passage? Why has this happened? During these 26 years, no attempt has been made to bring him back here to stand trial. We have Extradition Treaty agreement with the USA. But there has not been any attempt to extradite Mr. Anderson and to bring him back. He is the main person responsible for mass slaughter of the people that happened in 2nd December, 1984.

We have seen the statement of the Joint Director of the CBI. CBI undertook the investigation. But I have seen the statement of Joint Director, B.B. Lal to know as to what he has stated. He has stated that instructions came from Delhi, from the Central Government that CBI should not seriously try for

extradition of Mr. Warren Anderson. I would like to know from the Government this. Initially, the Government of India claimed three billion dollars as compensation. There was a settlement between the Government of India and UCC. That was an out of court settlement. By out of court settlement, the claim of three billion dollars, which was made by the Government of India, came down to 450 million dollars, that means, Rs.713 crore. That was finally settled with UCC. With this amount, the families of deceased received only Rs.12,000 to Rs.15,000 each.

Why did the Government of India during this period of 26 years not seriously try when the Supreme Court of India diluted the seriousness of the case and changed the section from 304 IPC to 304 (a) IPC? The Government of India did not seriously contest and challenge this and accepted the judgement of the Supreme Court. During this period, they had not seriously pursued the case. The family of the victims continued to suffer. Even during these days, those who were born, were born with blindness and other defects or diseases; they were found among the people of that area. You can find the difference in attitude.

The CBI wanted to visit their plant in USA. In West Virginia, they have a unit; the CBI wanted to visit that unit; but they were not permitted. They wanted to see the difference between their unit in West Virginia and the unit in Bhopal. But they were not allowed to visit. You can find the double standard being followed by this company.

Now, Dow Chemicals has purchased the UCC. The responsibility of cleaning that area and disposing or removing the poisonous waste materials which were dumped in Bhopal in the campus of UCC is the responsibility of the Dow Chemicals since it has now been taken over by them.

But we do not find that action. A Group of Ministers was constituted, but they took ten days to finalize the report. It made certain recommendations; it had enhanced the compensation amount; it had recommended that a further compensation of Rs.1500 crore be sanctioned by the Government of India. Why should the Government of India pay this money? This is people's money. Why

should UCC or the Dow Chemicals not be asked to pay more compensation? It is because the money which was originally claimed by the Government of India in 1986 was 3 billion dollars; and why was that amount reduced to just Rs.713 crore? The Government of India has decided to take necessary steps to seek extradition of accused no.1.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : When the Government of India considers accused no.1 as Warren Anderson, it has decided to start and try to seek extradition of accused no.1. We are developing strategic relations with the USA, in different spheres. Our Prime Minister has visited the USA. Many Ministers are holding meetings with their counterparts in the USA.

Has the Government of India till date taken up with the Government of United States of America the extradition of Warren Anderson? During these 26 years people are suffering from various ailments and diseases and they will continue to suffer. The ground water in the entire area within the five kms. radius in Bhopal has been contaminated. How can the area be developed? How can the people who have been exposed to poisonous gas be treated properly? No proper treatment has been given to them. There is a need to provide more funds....
(Interruptions) The UCC, now Dow Chemicals should also be prosecuted and should be forced to full cost for all remedial measures like, re-examination of categorisation of deaths and injuries while treating the current additional compensation offered as interim relief.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Next speaker is, Shri Joshi.

SHRI BASU DEB ACHARIA : We demand to set up a proper medical infrastructure for Bhopal victims and make available the required medicines; take up the issue of UCC's liabilities both criminal and civil and exhibiting Letter Regulatory which has not been done.

The entire Opposition demanded that Civil Nuclear Liability Bill, with the experience that we have with the UCC, a multinational company of the United

States of America, be enacted. USA is now putting pressure to enact a legislation in regard to Civil Nuclear Liability.

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

SHRI BASU DEB ACHARIA: The Bill is before the House.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The amount which is there in the Bill is much less than what has been paid.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Before I say 'nothing will go on record', please sit down.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am concluding, Sir.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

MR. CHAIRMAN : I have given you too much time. Shri Joshi, you may start.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Let me conclude, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, please, I have already called him.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Please allow me to conclude.

MR. CHAIRMAN: No. You should know that I have given you enough time.

* Not recorded.

श्री कैलाश जोशी (भोपाल): माननीय सभापति महोदय, मैं भोपाल गैस त्रासदी का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ और मेरे सामने ये सब घटनायें घटित हुई हैं।

सभापति महोदय, जिस जमीन पर यह कारखाना लगाया गया था. वह जमीन काली परेड के नाम से जानी जाती थी जिस पर नवाब के जमाने में सेना की परेड हुआ करती थी। बाद में जब मास्टर प्लान बना तो उस भूमि को खाली छोड़ दिया गया था। उस जमीन पर कोई भी कारखाना लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी क्योंकि वह बस्ती से लगा हुआ स्थान था। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने वहां कारखाना लगाने की अनुमति दी। सरकार को मालूम था कि उसमें एमआईसी सहित कई प्राणघातक रसायनों का प्रयोग किये जाने वाला है। वर्ष 1981 में एक बार ऐसी घटना घटी भी थी जब गैस का रिसाव हुआ और कुछ मजदूर मारे गये थे। उस समय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भविष्य में इससे भयंकर घटना घट सकती है, इसलिये ऐसी कोई प्रभावी व्यवस्था की जाये। उस समय यूनियन कार्बाइड की जो टीम उस घटना की जांच करने आयी थी।

उस टीम ने मिलीभगत से बाद में यह रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, यह साधारण घटना है और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी कार्यवाही यूनियन कार्बाइड ने नहीं की, न ही राज्य सरकार ने उस पर कोई दबाव डाला। इसके परिणामस्वरूप यह घटना घटी थी। जब यह घटना घटी, तो इसमें हजारों लोग और पशु मारे गए और पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे, वे रास्तों पर टपक पड़े। 5 तारीख को घटना के दो दिन बाद मैं स्वयं उस इलाके में गया था। जिन लोगों की आंखों में जलन हो रही थी, वे घरों से निकलकर भागने लगे तो उनकी सड़कों पर ही मृत्यु हो गई और दो दिनों तक उनके शव सड़कों पर पड़े रहे। इसी प्रकार से गाय, भैंसें, कुत्ते और बिल्लियों के शव भी दो-तीन दिनों तक वहां पड़े रहे, उसके बाद ही उनके शवों को हटाया गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के घटने का कारण यह था कि सरकार ने गलत जगह पर कारखाने को लगाने की अनुमति दी थी। जिस समय यह कार्यवाही चल रही थी, उस समय आपातकाल लागू था और हम लोग जेल में बंद थे, हमें पता भी नहीं चला कि कब अनुमति दी गई। जब हम बीस महीने के बाद जेल से बाहर आए, तब कारखाने के नींव रखी जा चुकी थी।

सभापति महोदय, इस घटना के बाद वहां के पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा गया। उन्होंने इसकी जांच शुरू की कि घटना क्यों घटी और इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? 6 तारीख से शहर की साफ-सफाई का काम शुरू हो गया। पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। किन्तु 6 दिसम्बर की रात को अचानक आदेश आ गया कि इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और वह इस काम को करेगी। इससे पुलिस की भुमिका नगण्य हो गई। पुलिस ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकी

क्योंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में कम्पनी के 8 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण बनाया और उन सभी को भी जमानत पर छोड़ दिया गया। हजारों लोग मारे गए थे। यह सीबीआई को मालूम था, किन्तु इसके बावजूद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। उन दिनों एंडरसन भी भोपाल में थे। यह पुलिस को मालूम था। लेकिन एंडरसन को जमानत पर छोड़ दिया गया। उस समय सीबीआई ने कुछ नहीं कहा। जब सीबीआई के अधिकारी से पूछा गया कि इन्हें क्यों छोड़ा गया है तो उन्होंने कहा कि हमने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही छोड़ा है। न पुलिस को बताया गया, न कोर्ट को बताया गया और सभी को बाहर से ही बात करके छोड़ दिया गया। एंडरसन को तो उसके गेस्ट हाउस में ही जमानत देकर छोड़ दिया गया।

महोदय, वारण्ट जारी होने के बावजूद भी वारण्ट को तामील नहीं किया गया। अभी भी वहां की पुलिस वारण्ट तामील होने का रास्ता देख रही है। उसके खिलाफ अपराध दर्ज हैं। उसको कोर्ट में पेश किया जाना है। जब यह घटना घटी उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने एंडरसन और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश पुलिस यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में एंडरसन को गिरफ्तार करने पहुंच गई। अरैस्ट करने की कार्रवाई चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री का दूसरा निर्देश आ गया कि कोई कार्यवाही नहीं की जाए, उसे छोड़ दिया जाए और अधिकारी शासकीय विमान से उसे दिल्ली पहुंचा दें। इसके बाद वहां के कलेक्टर और एसपी उसे शासकीय कार से एयरपोर्ट छोड़ने आये और उसे शासकीय विमान से दिल्ली पहुंचा दिया गया।

महोदय, मुझे जानकारी मिली है और यह तथ्य पूर्ण है कि ..* जब हमने उसका विरोध किया...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : आप कृपा करके नाराज मत होइए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take your seats. Please do not make allegations.

... (Interruptions)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): आप बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, ये सबूत मांग रहे हैं।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए, आपको सबूत चाहिए। ...(व्यवधान) आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं सबूत लेकर आपके पास आ जाऊंगा।...(व्यवधान) मेरे पास सबूत हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have asked him to stop making allegations.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down and do not disturb the proceedings.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not accuse somebody.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have already asked him not to make allegations. Please take your seats.

...

(Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल : इस प्रकार से किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते।...(व्यवधान) क्या आप संसदीय परम्पराओं को जानते हैं? ...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। ...(व्यवधान) मेरे पास इन सब बातों का प्रमाण है और अभी मैं बता सकता हूँ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair.

... (Interruptions)

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि 1985 के चुनाव के लिए ... (व्यवधान) *

श्री जगदम्बिका पाल : ये इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने एस.पी. को फोन किया।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.


(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if there is anything objectionable, then I will see to it that it is deleted from the records.

... (Interruptions)

श्री कैलाश जोशी : आप पूछने वाले कौन होते हैं, सरकार हमसे पूछेगी तो हम उसका जवाब देंगे। आप ऐसे ही बीच में बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)

16.00 hrs.

सभापति जी, उस संस्था के जो आज अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस घटना के घटने के बाद भी सार्वजनिक रूप से बोला है कि हमें यूनियन कार्डाइड से चन्दा  मिला था। अब आपको किस बात का सुबूत चाहिए ? ... (व्यवधान) उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। ... (व्यवधान)


MR. CHAIRMAN : Please address the Chair and conclude.

... (Interruptions)

श्री कैलाश जोशी : सभापति जी, मैं तो कन्क्लूड करना चाहता हूँ, लेकिन वे मुझे बोलने तो दें। ... (व्यवधान)
सभापति जी, मेरा यह आरोप भी है कि यूनियन कार्डाइड से ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

 श्री कैलाश जोशी : सभापति जी, मेरा यह आरोप भी है कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने यूनियन कार्डाइड से चुनाव के लिए पैसा लिया है। ... (व्यवधान) और इस कारण उसे छोड़ा गया है। इसके प्रमाण हैं। ... (व्यवधान) सी.बी.आई. के रिटायर्ड अध्यक्ष ने भी बोला है कि यह सच है और किस व्यक्ति के धू पैसा आया है, यह सबको मालूम है। ... (व्यवधान)

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: I have given you plenty of time. I cannot give you any more time to speak. Shri Verma, please continue now.

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

* Not recorded.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): माननीय सभापति जी, इस सदन में 25 साल के बाद भोपाल गैस ट्रेजडी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इतनी भीषण त्रासदी पर ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. There is a certain amount of time allotted to each Party. Your Party's time is over.

*(Interruptions) ...**

श्री सज्जन वर्मा : सभापति जी, आज सदन में पहली बार, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं, तब यह लगा कि नेता प्रतिपक्ष के पास अच्छे शब्दों का पिटारा नहीं है, यानी अच्छी डिक्शनरी नहीं है।

माननीय सभापति जी, 25 साल के बाद जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्हें मदद मिलनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इस बात से इस सदन का कोई मैम्बर इंकार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में एक बार भी यह नहीं कहा कि गैस ट्रेजडी में जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन्हें ये सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ यह कहा कि यह हुआ, वह हुआ, इधर की सड़क को उधर मोड़ा और उधर की सड़क को इधर मोड़ा, इस घटना को उस घटना से ले जाकर जोड़ा, क्योंकि इस सदन में श्रीमती सुषमा स्वराज से बड़ा शब्दों का कोई और जादूगर नहीं है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Sajjan Verma is saying.

*(Interruptions) ...**

श्री सज्जन वर्मा : सभापति महोदय, उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी को 1984 के दंगों से जोड़ा, सोहराबुद्दीन के केस से जोड़ा, उन्होंने इसे मोहम्मद अजमल कसाव के साथ जोड़ा। उनसे कोई व्यक्ति दिल्ली में खड़ा होकर पूछे कि माननीय सुषमा जी, बनारस जाना है, तो कैसे जाएं ? सुषमा जी कहेंगी कि देहरादून होकर जाना। शब्दों की ऐसी जादूगरी उनके अलावा इस सदन में और कोई नहीं कर सकता। माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ...(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करता हूं कि बहुत सारी बातें सुषमा जी ने कठोर शब्दों में अपनी बुलन्द आवाज में कहीं, उस वकील की तरह, जो एक आयातित वकील होता है, जो वकील अपने मुवक्किल की, अपने क्लाइंट की अच्छी-अच्छी बातें तो मजिस्ट्रेट के सामने रखता है, लेकिन कमजोर बातें अपने मुवक्किल की, अपने क्लाइंट की सामने नहीं लाता। सुषमा जी, 5.5 लाख लोगों की गैस ट्रेजडी में आर्थिक सहायता



* Not recorded.

मिली। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस केस की पैरवी सुषमा जी कर रही थीं, वह इतना कमजोर केस था कि उसकी हवा अरुण जेटली साहब ने निकाल दी। इतने कमजोर केस की पैरवी सुषमा जी कर रही थीं कि

16.06 hrs.

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

जब अरुण जेटली जी ने लॉ मिनिस्टर होते हुए अपनी फाइल में यह लिखा: “Warren Anderson is not responsible for Union Carbide gas leakage and Bhopal gas tragedy.” जब उनकी पार्टी का व्यक्ति एक मंत्री रहते हुए यह बात कर रहा है, तब मैं समझता हूं कि सुषमा जी को इस सदन में देशप्रेम की बातों का भाषण नहीं देना चाहिए।

आपको आश्चर्य होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग इफैक्टिड हुए हैं, मैं उनकी तरफदारी करता हूं, मेरी सरकार उनकी तरफदारी करती है और सुविधाएं मिलें, उसकी तरफदारी पूरा सदन करता है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय यह घटना हुई, 2-3 दिसम्बर, 1984 की दरम्यानी रात को, उस समय भोपाल की जनसंख्या 8.25 लाख थी और जब गैस ट्रेजेडी के बाद दावे आये तो 10.25 लाख दावे आये। यह आश्चर्य का विषय है कि यह सुषमा जी नहीं देख पाईं कि जहां 8.25 लाख की जनसंख्या है, वहां 10.25 लाख दावे प्रस्तुत किये गये। इतने फर्जी दावे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रस्तुत कराये, मैं तो यह कहूंगा।

बार-बार सुषमा जी ने कांग्रेस की अस्मिता पर प्रश्नचिन्ह लगाया, कांग्रेस की सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगाया। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि सन् 1984 में जब यह घटना हुई, उस समय के चन्द दिनों के बाद लोक सभा के चुनाव थे और अविभाजित मध्य प्रदेश में लोक सभा की 40 सीटें थीं। उनमें से 39 सीटों के चुनाव हुए और 39 पर हमारी पार्टी के लोग जीते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि थोड़े दिनों बाद भोपाल संसदीय सीट का चुनाव, जो इस ट्रेजेडी की वजह से रोक दिया गया था, जब चन्द दिनों के बाद भोपाल संसदीय सीट का चुनाव हुआ तो लाखों वोट से कांग्रेस का नुमाइन्दा इस घटना के बाद भी जीतकर आया, मैं यह सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। जब सुषमा जी कांग्रेस की अस्मिता पर प्रश्न-चिन्ह लगा रही थीं, तब शायद उनको इस बात का ध्यान नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 1984 की इस घटना के बाद मार्च, 1985 में मध्य प्रदेश विधान सभा के चुनाव थे और सम्पूर्ण मैजोरिटी के साथ कांग्रेस ने फिर भोपाल में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, इसलिए कांग्रेस की सरकार को कठघरे में खड़ा करना...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको टाइम दिया जाये। ये गवाह हैं, जिन्होंने सारी बातें देखी हैं, इसलिए आप उनको बुलवाइये।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, आप उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री सज्जन वर्मा : 6.5 साल से मध्य प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ..(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सज्जन वर्मा : मध्य प्रदेश के अंदर साढ़े छः साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया, जिससे गैस पीड़ितों और उनके परिवार वालों को कोई सहायता मिल सके। यहां तक इस सरकार ने उल्टे यह काम कि जब गैस पीड़ित लोग, ...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब गैस पीड़ित परिवार भोपाल की सड़कों पर न्याय मांगने के लिए निकलते थे, तब भाजपा की शिवराज सिंह सरकार उन पर लाठी और डंडे बरसाती थी। इस तरह की सरकार और पार्टी के लोग इस सदन में बात करने के काबिल नहीं हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष को आह्वान करता हूँ कि मनीष तिवारी जी ने कांग्रेस की तरफ से जो तथ्य रखे, उनमें से एक भी तथ्य आप नहीं काट पाएंगे। एक भी तथ्यात्मक बात आपके पास नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं स्टेज लगा दिया गया हो और सुषमा स्वराज जी उस पर राजनीतिक भाषण दे रही हों। उन पीड़ितों के आंखों के आंसू पोंछने के काम के लिए एक भी शब्द नहीं था जिससे गैस पीड़ितों के आंसू पोछे जाएं और उन्हें सहूलियत दी जाए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस सदन में उसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, जो खुद न्याय करता हो, जो खुद न्याय की परिभाषा जानता हो। आज कैलाश जोशी जी यहां उपस्थित हैं। यह उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि मैं भोपाल का वासी हूँ, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। आप हमारे देवास जिले के रहने वाले हैं। जिस तरह से सुषमा स्वराज जी आयातित होकर भोपाल के पास आयी हैं, उसी तरह से आप भोपाल आयातित होकर गए, इसलिए उस समय का दर्द आपकी जानकारी में नहीं है कि गैस पीड़ित परिवारों ने क्या और कैसे भोगा है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब-जब दिल्ली में गैस पीड़ित लोग भोपाल से चलकर आए, तब उस समय पिछली यूपीए गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के मात्र चार सांसद ही थे ...(व्यवधान) जबकि बीजेपी के 20-22 सांसद थे, जब भोपाल से गैस ट्रेजडी से पीड़ित लोग यहां आते थे, दिल्ली की सड़कों पर लावारिस घूमते

थे । तब भाजपा के सांसदों में से किसी एक ने भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दी कि आइए आप चाय या पानी पीजिए। आज आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सज्जन वर्मा : ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और थोथी बातें कर रहे हैं। इनके पास तथ्यात्मक कुछ भी नहीं है। आज मनीष तिवारी जी ने जो जवाब दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद किसी भी विषय पर सुषमा स्वराज जी ओपनिंग करना भूल जाएंगी। ...(व्यवधान) किसी भी विषय पर सुषमा स्वराज जी ओपनिंग नहीं करेंगी। पिछली तीन बार से वह देख चुकी हैं कि कितना गलत बयानी करती है, अतथ्यात्मक बात करती हैं। हमारे कांग्रेस के लोग जो भी जवाब दें, मंत्री जी तो बाद में जवाब दें...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री सज्जन वर्मा : लेकिन मनीष तिवारी जी की बातों का जवाब एक भी सदस्य नहीं दे पाएगा। माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस सदन में ...(व्यवधान) मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आपस में चर्चा नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री सज्जन वर्मा : मैं बहुत समझदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आप जैसे नहीं ...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं न्यायपूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से गैस पीड़ितों को और सुविधाएं मिलनी चाहिए, यदि हमारी सरकार उनको और अतिरिक्त सुविधाएं मुआवजे के रूप में देती है, तो हम उनको धन्यवाद देंगे। जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी तरफ से माननीय कैलाश जोशी जी बोल रहे थे। वह भोपाल से ही सांसद हैं। सालोंसाल से भोपाल में निवास भी है और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि एक प्रकार से एबरप्टली उनका भाषण बीच में काट दिया गया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : प्लीज आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदया, मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि उनके भाषण के बीच में बार-बार टोका-टोकी की गयी, इसलिए केवल उनका भाषण पूरा करने के लिए उनको दो मिनट का समय दिया जाए, ऐसा हम आपसे नम्र निवेदन करेंगे। वह बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, इसलिए मेरा आपसे इतना निवेदन है कि कृपया आप उनको अपना भाषण पूरा करने के लिए उनको थोड़ा समय दीजिए।

सभापति महोदया : मैं वाइंड-अप करने के लिए दो मिनट का समय देती हूँ, लेकिन जो चेयर की रूलिंग थी कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम हटा दिए जाएं और इस तरह दुबारा नाम नहीं लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : एज एन एक्स्पैशनल केस केवल वाइंड-अप करने के लिए दो मिनट का समय है। मैं फिर रिपीट करती हूँ कि चेयर की जो रूलिंग दी जा चुकी है कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उन पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : माननीय सदस्यों ने कई लोगों के नाम लिए हैं, तब किसी ने नहीं कहा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप वाइंड-अप कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अगर बहस वाइंड-अप करेंगे तो हमारे दल के सदस्य कब बोलेंगे।

सभापति महोदया : मैं जोशी जी की बहस को वाइंड-अप करने के लिए कह रही हूँ। जोशी जी, मैं आपको एज ए स्पेशल केस इजाजत देती हूँ।

...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: It should not become a precedent....

(Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : आपके आने से इंसाफ मिलता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप दो मिनट सुन लीजिए और सदन में पहले जो रूलिंग आ चुकी है, उसे सब सदस्य याद रखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : हम मांग करते हैं कि एंडरसन का प्रत्यार्पण कराने के लिए केन्द्र सरकार तत्काल कार्यवाही करे, क्योंकि उन पर आज भी भोपाल पुलिस का वारंट जारी है। वारंट होने के बाद भी वे आज तक अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसलिए उनका प्रत्यर्पण करवाकर जेल में भेजने की व्यवस्था की जाए जिससे उन पर मुकदमा चल सके।...(व्यवधान) आप फिर बीच-बीच में बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : इस बीच एक घटना और घटी जिसके बारे में माननीय सदस्य बोले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला आया जिसमें धारा 304 के मामले को धारा 304 (ए) में बदल दिया गया। उस समय जो जस्टिस थे, उन्होंने यह निर्णय लिया और निर्णय लेने के कारण भोपाल में जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, वहां के न्यायाधीश को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदली हुई धारा में ही मुकदमा चलाना पड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि सबको दो-दो वर्ष की सजा मिली, इससे ज्यादा नहीं मिली। जिन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली, उन्हें केवल दो-दो वर्ष की सजा मिली और वे अभी भी अपील में जा रहे हैं, जेल से बाहर हैं। यह स्थिति हुई। जस्टिस महोदय को इसका यह इनाम दिया गया कि भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए जो अस्पताल खोला गया, उन्हें उस अस्पताल की संचालन समिति का जीवनभर के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। वे आज भी उस पर बैठे हुए हैं।

हमारी दूसरी मांग है कि उस समिति को तत्काल भंग करके नई समिति का गठन किया जाए जिसमें भोपाल के नागरिक, भोपाल के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए।...(व्यवधान)

मैं गैस त्रासदी के पीड़ितों के बारे में कहना चाहता हूं। पीड़ितों की संख्या सही नहीं बताई गई है। लोग इससे कहीं अधिक संख्या में मरे हैं जिनके शवों को बाहर जाकर नदी में बहा दिया गया है। यह वहां के लोग आज भी कहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वहां से पीड़ितों की जो संख्या बताई जाती है, उसे विश्वसनीय माना जाए और यहां की संख्या को ठीक नहीं माना जाए। यही स्थिति बीमार लोगों की भी है।

तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि भोपाल में उस समय कोई 56 वार्ड थे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जोशी जी, आपके दो मिनट हो चुके हैं। मैं नाम लेने के लिए बाध्य हूं।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : वे व्यवधान डाल रहे हैं, आप उन्हें रोकिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक सैकिंड में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : मैं कहना चाहता हूं कि पीड़ितों के बारे में संख्या ठीक से निर्धारित की जाए।

जो मुआवजा अभी दिया गया है, वह अत्यंत कम है। इसलिए कम से कम मृतकों को दस लाख रुपये, गंभीर बीमारों को पांच लाख रुपये और अन्य को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये, यह हम लोग मांग करते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, सीबीआई की चर्चा यहां पर आयी है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जोशी साहब, कृपया करके अब आप बैठ जाइये।



...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कल्याण जी, अब आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, सीबीआई की चर्चा यहां पर आयी है और सीबीआई के बारे में सभी माननीय सदस्य बोले हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जोशी साहब, अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, मैं अपना वाक्य पूरा करके समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

सीबीआई हमारे देश की विश्वसनीय जांच संस्था रही थी, किन्तु दुर्भाग्य से कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे हैं कि सीबीआई पर से विश्वास उठने लगा है। सदन में भी अनेक सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिये।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : मैं अपनी बात कहता हूं कि हमारा यह भी अनुरोध है कि सीबीआई के मामले में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाये, जो इस बात की जांच करें कि सीबीआई का कार्य निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ किस प्रकार हो...(व्यवधान) ऐसी व्यवस्था की जाये।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam Chairman, I will not take much time of the House, as has been taken by the hon. Leader of the Opposition. I will take only three or four minutes. I do not know whether the hon. Leader of the Opposition has really done her home work or not and she should really ask questions to a member of her own party who is now a Member of the Rajya Sabha and also the present Leader of the Opposition there.

Madam, I do not know whether you have the power to call for the official files here. But if the file in respect of this matter is called for, the entire nation will see as to what has been done when her party member was the Law Minister in the year 2001. It is really shocking, simply shocking. In 2001, the then Attorney-General of India Shri Soli Sorabjee sent his legal opinion to the Government and the then Law Minister noted his opinion on the file as follows:

“The evidence so far collected does not appear to be sufficient at this time to meet the standards applicable in the US.”

Now, everybody knows who was the Law Minister in 2001. It was none other than Shri Arun Jaitley and it is he, who recorded his opinion like this in the file. You can bring the record and the entire country will be able to see that. The then Law Minister recorded his opinion in the note sheet on the basis of the opinion given by the then Attorney-General Shri Soli Sorabjee and he said:

“Our extradition case appears to be weak.”

You can call for the records and see that. This opinion was given by the then Attorney-General in July, 1998 in response to a query from the Legal and Treaties Division of the Ministry of External Affairs. On 25th September, 2001, the note was given by the then Law Minister. He was not only the Law Minister of the country at that time, but he is a senior advocate of the country with experience of practicing in the Supreme Court for long years. I have great respect for him for his abilities in the legal field. The person who commands a special respect in the legal

field in our country, this gentleman, when he was the Law Minister, wrote in his note:

“It is not the case that Mr. Anderson committed any act that led to the direct result of the leakage of gas and the consequent loss of lives and injuries.” ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : यह कोटेशन है, एलीगेशन नहीं है।

SHRI KALYAN BANERJEE : Thereafter he went on writing:

“There is no evidence that Mr. Anderson had knowledge of design defects and violation of safety requirement and yet he failed to take proper remedial measures.”

He also added there:



“There was no evidence to show that the parent company exercised control over the day to day operations and running of the Bhopal Plant.”

It has also been written there and if I do not quote that I will not be stating the truth. So, I quote:

“It will be a matter of policy to go ahead with the extradition request despite the shortcomings.”

This is the position. The then Law Minister has done it. Why the allegations are there? Why in 1996 Chief Justice Ahmadi reduced the crime, transformed the charges under section 304? Why did the BJP leaders did not say anything at that point of time? Why nothing was said? Why did they not come out? Why that was not protested? Why did they not say that the Supreme Court has no power to do it? Why did they not file any application? Why did they not file the curative petition?

Today all crocodile tears are coming. In Bengali it is said, “*kumirer kanna*”. Now, this is nothing. It is simply for making the politics. If this is done, if this is wasted, if it is lost, if the victims have suffered, they have suffered

because of the opinion of the then Law Minister, who has spoiled the entire case. It is a fact. It has to be accepted.

Today, the entire nation wants to know what the legislators were doing, what the parliamentarians were doing. Why would under section 304(A) two years imprisonment be there? Is it the responsibility of the court? Or this is our responsibility? Why have we not done it? Why have we not amended section 304(A)? Why have we not said in 1996 when Justice Ahmadi said, 'reduce the quantum, reduce the gravity of the charges transforming to Section 304(A)'? Today they are asking what has been done.

I must appreciate the hon. Prime Minister. The moment everyone has said, the hon. Prime Minister knows about that. No law has given him any power. Even then he has constituted a committee. This committee is presided over by our hon. Home Minister. He is trying to render the justice, trying to give justice to the persons who have seriously suffered. Not a single man has gone to espouse their case. No matter when years after years, decades after decades have gone by, how many BJP leaders have gone to the court and said they are supporting the victims' case. How many BJP leaders and BJP lawyers went to the court and fought for the victims? Nobody has gone, Madam. The victims have suffered. Victims have got their relief which has been given by the Supreme Court. It was not decided by the Central Government at all.

Today, what they are saying is for the purpose of doing politics. Rather, I would request the Opposition leaders to go back home, call that leader who is crying for the nation and ask him why this opinion was given by him. It is because of him that today the entire country has suffered.

Madam, I give my highest regards to you and thank you for giving me this chance.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on this subject. The Bhopal Gas tragedy really was a sad incident. Next to Hiroshima, Bhopal Gas tragedy is the biggest man inflicted disaster that shook the entire country. Thousands of people have lost their lives and lakhs and lakhs of people were either incapacitated or suffered from incurable ailments.

The company had thrown all ethos and morality to winds and behaved indifferently to the consequences of tragedy. The recent information reveals that Dow Chemical Company, an American firm, which owns the said Union Carbide Corporation, is now trying to seek the support of the Government of India for its firm's business despite continuing public opposition over its unwillingness to accept responsibility for Bhopal. The Government must be very careful in dealing with this issue.

Legal battle fought over more than two decades has not brought any relief to the victims and the affected people. Still the people are suffering from incurable diseases. Social activists and others, who took up the cause of the victims, have been driven from pillar to post. Those who perpetrated the crime have escaped with minor punishment. To whom we have to blame, to the heartless corporates or to the ineffective legal system? The sufferers have no salvation. Had we taken up the issue in a more effective manner, and even I would suggest with the authorities of the US, we could have got more relief which could have benefited the affected people. Now the Government wants to extradite the chief of the company for launching prosecution. I think this is not only a belated move but also an unproductive one. I think, no useful purpose will be served. There is something fishy also in this tragic episode. I do not want to go into details of the issue as to who has done it and on whose behest. Let bygone be bygone.

Constructive efforts must be made to rehabilitate the affected families. If we fail to perform duty, the future generation will blame us as insensitive to the

tragedy. The relief package suggested by the GoM is not adequate and it will not fully meet the needs of the people. Let us be generous and look at the pathetic plight of these helpless people.

I would rather request the hon. Home Minister to have a re-look at the issue and come forward to sanction adequate amount for their rehabilitation and recovery of their health. The persons who were responsible for this sad tragedy should be made to bear the compensation.

While we are discussing this matter, one person has to be remembered and honoured. That person is Zahir Ali Khan, a former MLA of Madhya Pradesh – he belongs to CPI – who opposed it even at the time of launching the Union Carbide company. Even before the tragedy occurred he predicted as to what is going to happen. Even after passing of so many years, still the residue of the poisonous gas is harming the people. The Government should clean the site from possible hazards.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदया, भोपाल गैस त्रासदी पर हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण यहां जो बताया गया, वह यह है कि गैस लीकेज के कारण यह दुर्घटना हुई। उसके कारणों की चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने उसमें टेक्नीकल डिफेक्ट की बात कही, उसका मेनटेनेंस भी प्रॉपर टाइम में नहीं होता था। इस बात को कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा है इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह कम्पनी का टोटल फेल्योर था। दिसम्बर दो और तीन तारीख के बीच में यह दुर्घटना हुई, लेकिन सीबीआई ने इस मामले को तीन दिन के बाद टेकअप किया और तीन साल बाद इसकी चार्जशीट फाइल की गई।

अभी मनीष जी यहां नहीं है लेकिन टीवी तो देख रहे होंगे। जब सीबीआई ने चार्ज-शीट फाइल की थी, उसमें वारेन एंडरसन का नाम और लोगों के साथ था। यह तो यूएस की पैरेंट कंपनी है, इंडियन कंपनी तो उसकी सबसिडी कंपनी है। यूजीसी पैरेंट कंपनी को उसमें लिया गया है और उसके साथ हांगकांग में इसकी एसोसिएट कंपनी थी, उसको भी लिया है, एंडरसन और युनियन कार्बाइड को भी लिया है। इतना करने के बाद एंडरसन को नॉन-बेलेबल वारंट इश्यू किया था। लेकिन उस आदमी के लिए गवर्नमेंट एक ट्रक लेकर भोपाल जाती है और उसे दिल्ली लाकर पूरी मर्यादा के साथ अमरीका भेजा जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप दोनों तरफ के सदस्य कृपा बैठ जाएं। आप चेयर को एड्रेस करें।

...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : पहले भी प्रोटैक्ट किया अमरीका वाले को, अभी भी प्रोटैक्ट कर रहे हो।...(व्यवधान) मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। शोएब मलिक पाकिस्तान से यहां आकर सानिया से शादी करता है तो उसका पासपोर्ट सीज कर दिया जाता है और इतना बड़ा कांड हुआ, 20 हजार लोगों अपंग हुए या मारे गये और पांच लाख लोगों पर उस गैस का असर हुआ, उसका पासपोर्ट तो सीज नहीं किया गया।...(व्यवधान) अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि वहां भोपाल में इतने लोग हैं भी नहीं। अभी भी ये लोग अमरीका वालों का सपोर्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिए। यह बहुत ही सीरियस इश्यू है, सदस्य इसे मजाक में न लें।

श्री नामा नागेश्वर राव : यूनियन गवर्नमेंट ने 3.3 बिलियन का फाइन किया है यानी 14 परसेंट जो यूनियन गवर्नमेंट बोली कि इतना नुकसान हुआ है। आखिर में 470 मिलियन, इसका मतलब यह है कि 14

परसेंट इन लोगों से इकट्ठा किया है। ... (व्यवधान) मैडम, इन लोगों की वजह से उन लोगों को प्रोटैक्शन मिला है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अमरीका में एक छोटा इश्यू हुआ है बीपी का। तुरंत व्हाइट हाउस में उसके सीईओ को बुलाकर 20 बिलियन यानी 90,000 डिपोजिट करवा दिया है जबकि केवल 13 आदमियों की मृत्यु उसमें हुई थी। यहां इतने आदमियों की मौत होने के बाद उसके सीईओ को राज-मर्यादा से, यहां से स्पेशल फ्लाइट से बाहर भेज दिया जाता है। भारत के लोगों के स्वाभिमान को इन लोगों ने अमरीका के लोगों के पैरों के नीचे रखा है। ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, इन्होंने देश को बेच दिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप गलत लोगों को स्पोर्ट मत करो और विकटिम्स को जल्दी कम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। एंडरसन को यहां ला कर जेल में डालना चाहिए।



डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, हाल में जो समाचार देश भर में फैला कि 10, 20 या 25 हजार लोग मरे थे और पांच लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस कांड में सजा सिर्फ दो साल की हुई और दोषियों को केवल एक-एक लाख रुपया जुर्माना हुआ। "जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड।" पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। इस फैसले और इस दुर्घटना के बाद देश की सारी व्यवस्थाएं कटघरे में हैं। न्यायिक व्यवस्था, शासन, प्रशासन कटघरे में है और यह साबित करता है कि गरीब और पीड़ित व्यक्तियों के लिए यहां व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कानून मंत्री ने कहा कि न्याय नहीं मिला, न्याय मर गया और न्याय का व्यवहार नहीं हुआ। श्री बालकृष्णन चीफ जस्टिस ने कहा कि दोष के मुताबिक पर्याप्त सजा नहीं मिली। बहुत विस्तार में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस कांड का असली कसूरवार कौन है? इसमें सात चूक हुई हैं और आपराधिक लापरवाही हुई है। जब मैं इस बारे में देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कम कसूरवार है। चाहे अफसर हो चाहे सरकार हो, कोई भी कम कसूरवार नहीं है। सुश्री सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं। विभिन्न कोर्ट के फैसलों को पढ़ रही थीं और इस केस शोहराबुद्दीन के केस से जोड़ रही थीं। हम सुनकर आश्चर्यचकित थे कि क्या लोजिक है। इनका भी देश और राज्यों में प्रशासन रहा है। उस समय ये कहाँ थे और 25 सालों में क्यों नहीं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, आफिसर हो या शासन हो, कोई भी कम कसूरवार नहीं है। गरीब आदमी के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई नहीं है, इस फैसले से यही पता चलता है। चूक नम्बर एक यह है कि 25 साल बाद फैसला हुआ है। अरुण जेटली जी का नोट पढ़ कर सुना रहे हैं, वे कानून मंत्री थे, तब क्यों नहीं तेजी से कार्यवाही की गई। कुछ मामलों में ये दोनों एक जैसे ही हैं। 25 साल बाद फैसला आया है। 25 हजार लोग मरे हैं और 5 लाख लोग घायल हुए और प्रभावित हैं। इससे ज्यादा बर्बादी हिरोशिमा-नागासाकी के बारे में मैं सुनता था, उसके बाद यही घटना लगती है। ये घटना मानवता के खिलाफ घटी है, लेकिन सजा बिल्कुल नगण्य है। कम मुआवजा दिया गया है। उपहार सिनेमा में जो लोग मरे थे, उन्हें 15-20 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। भोपाल गैस पीड़ितों को केवल दो हजार, तीन हजार की बात हम सुनते हैं, हिसाब जोड़ा जाता है कि इतने लोग मरे और मुआवजा दिया गया।

कैसे मुआवजा दिया? अभी नारायण जी ने जो उदाहरण दिया, जो बी.पी.कंपनी ब्रिटेन वाली है और अभी ओबामा साहब जो अमरीका के प्रेसीडेंट हैं और जो मैक्सिको के गर्भ में तेल का रिसाव हुआ, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 90000 करोड़ से ज्यादा ही हो जाएगा, करीब एक लाख है, उन्होंने उस कंपनी से जमा कराया। इसलिए उसी अमरीकी प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि जहां 25 अरब हुआ, उसमें 12-



13 या 15 आदमी मरे होंगे या पर्यावरण दूषित हुआ तो उनको लाख करोड़ मुआवजा चाहिए और यहां 700 करोड़ रुपये में मामला रफादफा करा दिया। इतना भारी अन्याय गरीबों के साथ हुआ। मुआवजे के मामले में एंडरसन को भगा दिया गया और क्या कांग्रेस के अंदर कहासुनी नहीं हुई? मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन यह सही है कि एंडरसन को भगाने का काम यहां हुआ। उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद करना चाहिए था लेकिन उसको यहां से भगा दिया गया। कहते हैं कि हमने नहीं किया। मुख्य मंत्री ने नहीं किया, प्रधान मंत्री ने नहीं किया तो क्या हमने उसको यहां से भगा दिया? इसलिए यह बहुत गंभीर सवाल है और इस पर 25 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 वर्षों से कहते-कहते एंडरसन का वारंट जारी हुआ।

16.46 hrs.

(Dr. M.Thambidurai in the Chair)

हमारा गरीब आदमी यदि कोई सहारन दफा में पड़ता तो उसकी गर्दन में गमछा लगाया जाता। लेकिन चूंकि यह बड़े आदमी ने अपराध किया इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका प्रत्यर्पण क्यों नहीं होता? अमरीका और भारत की संधि कहां चली गई? ज़हरीली गैस के कारखाने के नियमों को ताक पर रख दिया गया। ज़हरीली गैस के बारे में भाषण दिये जा रहे हैं कि इस कारखाने की स्थापना हुई। इस कारखाने की स्थापना पास वाली जमीन में नहीं होनी चाहिए थी। शुरु में ही चूक हुई। पहले से खतरे की जानकारी हो गई थी और उसके बाद भी एहतियाती कार्रवाई नहीं की गई। अगर एहतियाती कार्रवाई की गई होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। आपराधिक लापरवाही की गई है और इस तरह से यह अक्षम्य अपराध किया गया है। लेकिन उसके बावजूद मुआवजे के भी उपाय नहीं किये गये। दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई।

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please wind up.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): न्यूक्लियर लॉयबिलिटी वाला कानून आने वाला है। मैं भारत सरकार को और सदन को इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं। कहते हैं कि उसमें जो एटमिक यंत्र होगा, उसमें अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो 500 करोड़ रुपये का जुर्माना उसमें हैं, ऐसा सुनते हैं।


MR. CHAIRMAN: Please wind up. When the Bill comes, you can discuss it. Now, here it is restricted.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कितना भारी अपराध देश के साथ फिर होने वाला है।...*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Please wind up. The Minister has to reply now. He is going to reply at five o' clock.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए हमें अब बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वहां 5 आदमी मर गये तो एक लाख करोड़ रुपया और यहां पर न्यूक्लियर से आदमी मर जाएगा तो 500 करोड़ रुपया ही मुआवजे में देने

का प्रावधान है। ऐसा प्रस्ताव सदन में आया है। पीड़ित में कोई छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्नीकल ऑब्जेक्शन लगाकर उसमें जो पीड़ित मर गया या पीड़ित हुआ, उसको मुआवजा नहीं मिले, यह अपराध नहीं होना चाहिए। देश में इतने दिन अपराध हुआ लेकिन इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो मरे हैं, उनको मुआवजे की पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए। कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए। फिर कहते हैं कि क्योरेटिव पैटीशन बनने जा रहा है। क्योरेटिव पैटीशन से खतरा है, ऐसा जानकार लोग बताते हैं कि क्योरेटिव पैटीशन से फिर अगले 25 साल ट्रायल में चले जाएंगे।

फिर क्या होगा। इसीलिए सावधान और सजग होकर कसूरवार कोई छूटे नहीं। एंडरसन की टांग में रस्सा बांधकर यहां बुलाया जाए और जेल में बंद किया जाए। हमारी प्रत्यर्पण संधि का क्या हुआ? इसके अलावा जो दुर्घटना का स्थान है, जहां पानी दूषित हो गया, पीने का पानी भी दूषित हो गया है। उस सभी चीजों का सुधार होना चाहिए। अभी सुनते हैं कि वहां कचरा पड़ा हुआ है, यह अभी तक क्यों नहीं हटाया गया है, इसके हटाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? इसके लिए कसूरवार  गौन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा भूतकाल बर्बाद हुआ, हमारा वर्तमान बर्बाद हो रहा है और देश के लोगों के भविष्य पर भी बर्बादी का खतरा आने वाला है। इसलिए इस मिलीभगत का हम भंडाफोड़ करना चाहते हैं, ताकि मिलीभगत नहीं चले और आमजन पीड़ित न हों, लोग बेमौत न मारे जाएं। वहां के बचे हुए लोगों को पर्याप्त मुआवजा मिले और जो कसूरवार है, उसे किसी हालत में नहीं छोड़ा जाए, उसे पर्याप्त दंड दिया जाए। ...(व्यवधान) एंडरसन की टांग में रस्सा बांधकर उसे यहां लाया जाए और उसे जेल में डाला जाए और ऐसा उपाय करो कि हमारा मुआवजा एक लाख करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ताकि जो भोपाल और मध्य प्रदेश के पीड़ित परिवार हैं, उनका पुनर्वास हो सके, उन्हें पूरा मुआवजा मिल सके। वहां जो भोपाल गैस कांड से पीड़ित परिवारों के संगठन काम में लगे हुए हैं, सरकार को उन्हें कांफीडेंस में लेना चाहिए। ...(व्यवधान) हमारे से जो चूक हुई है और देश का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। अन्यथा हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए सड़क से संसद तक लड़ाई होगी।

अंत में मैं दो पंक्ति बोलकर समाप्त करता हूं -

“देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है,
किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है।”

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, we are aware that the Bhopal gas tragedy is the worst industrial disaster of the world which can only be compared to Hiroshima incident. More than 20,000 people have died in Bhopal and about 5 lacs people are still suffering from the ill effects of the gas leak; they have become incapacitated. But I am on a separate point. I wonder whether on that fateful night, there was any administration functioning in Bhopal or not. As I have come to know and have gathered information, it seems that before the gas leaked, the administration was informed about an impending danger, 1½ or 2 hours in advance. But unfortunately, the Government did nothing. If it could take timely action, then the massive tragedy could have been averted, many innocent lives could have been saved and the disaster could have been stopped from taking place.

Therefore I would urge upon the Central Government to keenly look into this aspect. Secondly sir, the judicial system of our country is in shambles. Justice is always delayed here which gradually results in denial of justice. What did we see in this case? After long 26 years, a verdict was announced by the court which sentenced the accused to jail for only 2 years. The punishment was so lenient that the judiciary became a laughing stock. People from across the country were agitated because immediately the culprits were out on bail. If this is the image of our judicial system, then how can the ordinary people keep faith in it? How can they rely on the dispensation of justice? We say that the tenets of individual liberty is the hallmark of our society. But the reality seems to be something else. Our judicial system no longer upholds and safeguards the democratic norms; It no longer delivers timely justice based on morality and righteousness. It has really become mockery of law and justice.

Thirdly Sir, we should also know that the developed nations are very conscious about their health. They do not allow harmful, poisonous chemicals to be manufactured in their factories. But shift these hazardous manufacturing units

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

to the third world countries. This practice must be stopped. India has signed the nuclear pact with USA. If that treaty is materialises then such accidents can take place in future also. A threat of another industrial disaster thus looms large if the Civil Nuclear Liability Bill is passed in the Parliament. In case any accident happens, the entire fiscal responsibility will have to be borne by the Government of India whereas the suppliers of the nuclear reactors will go scot-free. As we know that the Bhopal gas victims or survivors have received a paltry sum of Rs.12,000 as compensation which should have been much higher for a disaster of such magnitude. The whole nation is furious. People are demanding true justice. The Government must look into the aspect of relief and rehabilitation of the victims seriously. Moreover, the culprits should be severely punished and the cases must be reopened.

With these words I wind up my speech and thank you for allowing me to participate in this discussion.

MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to speak on the subject, if they are having written speeches, they can be laid on the Table of the House.

Shri Narahari Mahato to speak now.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you Mr. Chairman, Sir. I am grateful to you for having given me a chance to participate in the discussion on Bhopal gas tragedy. It was a sad incident in the history of our nation. The Bhopal gas tragedy occurred nearly 26 years ago. It is still a sad memory to us. The tragedy has led to death of many people. When the tragedy occurred in the city of Bhopal, the State Government of Madhya Pradesh must be acknowledged as to whether they were serious in providing relief measures or not. No sensible action was taken to stop the emission or to stop the tragedy.

My humble request to you is this. More than 20,000 people died in this tragedy. Thousands of people have been affected. They are unable to earn their livelihood and live their life with honour. In this incident, the environment was badly affected. The environmental protection measures have not been taken and the pollution has been increasing and the people are unable to live in that place. The flora and fauna are affected and the water, land, trees, plants etc. have all been affected.

Those who were responsible for this tragedy have not been punished. My humble submission to you is this. Such a sad incident which has caused death of lots of people and caused thousands of people to live in misery for years has to be seriously looked into. This matter should be looked into seriously. We should take all possible action to give help to the poor people who are living in a very starving position.

I do not want to take much time of the House. My last and final submission to you is this. This tragedy has taken the lives of thousands of people and thousands of people are in difficult positions. They should be involved in the compensation and they should be provided all help and assistance.

With these words, I conclude.

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** मैं उन लोगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो 3 दिसम्बर 1984 कि रात मध्यप्रदेश कि राजधानी भोपाल में, प्रतिदिन दिनचर्या कि तरह काम में थके हारे गरीब लोग अपने परिवार बच्चों के साथ चैन कि नींद में सो रहे थे और उनके आस पास काफी झुग्गी, झोपड़ियां बसी हुई थी। और अचानक उसी रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव होने के कारण घंटों के भीतर वह चैन की नींद, मौत की नींद में सोते गए वह जहरीली गैस..... और वह घटना का असर उसी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर वर्षों तक चलता रहा, और इस तरह से 15000 से अधिक लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक लोग घायल के रूप में शिकार हो चुके हैं, और अभी भी इसका कहर जारी है।

महोदया यदि इस घटना को गहराई से देखा जाए तो एक आम आदमी का दिल भी दहल जाता है। इस तरह से यह घटना सिर्फ भोपाल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास कि सबसे बड़ी दुर्घटना है।

यहां सबसे असंतोष की बात यह है कि उस समय देश में केन्द्र और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन बचकर निकल जाने में सफल रहा। जबकि यदि एक आदमी का मर्डर होता है तो हमारे देश के सी.बी.आई. उसके जड़ तक पहुँचकर अल्प समय में ढूँढ निकालते हैं। लेकिन इस एंडरसन के भाग निकलने से यह लगभग पूरी तरह सत्यापित हो गया है केन्द्र के कांग्रेसी सरकार और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने खुशी खुशी और जान बूझकर यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वारेन एंडरसन की सुरक्षित निकासी को सुनिश्चित करने के लिए इस तथ्य के बावजूद षडयंत्र किया कि वह भोपाल गैस लीक कांड में जो हजारों लोगों के कत्लेआम का एक प्रमुख अभियुक्त था। सचमुच ही यह एक क्रूर मजाक है। और कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार ने एंडरसन के सुरक्षित निकासी के घोर अक्षम्य देशद्रोही और अमानवीय कृत को अंजाम दिया है।

यह दिल दहला देने वाली बात यह है कि यह घटना 3 दिसंबर 1984 को घटी और इस मामले के 5 दिसम्बर 1984 को सी.बी.आई. को सौंप दिया गया और एक लंबे समय 13 साल बाद 29 अक्टूबर 1997 को पहला गवाह पेश हुआ।

मैं यहां सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ? और आखिरकार अंत में 25 साल बाद उन आठ आरोपियों को केवल एक छोटी सी रकम के साथ दो-दो साल की सजा यह कैसा न्याय है? महोदया यह न्याय नहीं बल्कि पीड़ितों के साथ

* Speech was laid on the Table.

एक घोर अन्याय हुआ है। और इस अन्याय से हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्षुब्ध है और हमारा यह सामूहिक प्रयास रहेगा कि पीड़ितों को उचित मुवावजे के साथ पूरा न्याय मिलना चाहिए। और भारत सरकार और सी.बी.आई. को तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाए ताकि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को उचित दंड मिले और वारेन एंडरसन को कड़ी से कड़ी सजा एवं भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाय।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** 2-3 दिसम्बर, 1984 को हुई भयावह दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे गए थे। पशुओं के मारे जाने की संख्या लगभग एक लाख आंकलन किया है। प्रायः 5 लाख लोग जहरीली गैस के कारण अंधे हुए या भयंकर जानलेवा बीमारियों के शिकार हुए। 1984 से चल रहे मुकदमे का 2010 में फैसला आया, लेकिन यह न्यायिक त्रासदी भोपाल गैस जैसी ही भयंकर है। इन 26 वर्षों में जहरीली गैस प्रभावित जनता ने कैसी जिन्दगी जी और किस तरह प्रभावित परिवार के अनाथ बच्चे बड़े हुए, यह मानवीय इतिहास की एक लोमहर्षक कथा है। एक आंकलन के मुताबिक 20 हजार लोगों की मृत्यु हुई, 1 लाख से ज्यादा लोग अपाहिज हुए, 5 लाख लोग अंधे हुए या जानलेवा बीमारियों के शिकार हुए।

1987 में सी.बी.आई. ने चार्जशीट दाखिल की। 10 दोषियों की 10 साल की कैद की आवाज उठायी। 13 सितम्बर, 1996 के उच्चतम न्यायालय के एक खंडपीठ ने धारा 304-दो के तहत लिए गए आरोपों के गठन को खत्म कर धारा 304-ए के तहत आरोप गठन करने के निर्देश दिये गये। 8.12.1984 को वॉरन एंडरसन को रिहा किया गया। 1984 के मुकदमे का निर्णय 2010 में आया।

गैस त्रासदी के कानूनी पेंच के लिए दैनिक जागरण, 18.06.2010 पृष्ठ सं. 8 पर दिये गये समाचार पढ़ें।

2010 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल गैस त्रासदी मामले पर विचार के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) की सिफारिशों पर मोहर लगा दी।

जी.ओ.एम. की सिफारिशें

गैस पीड़ितों को 1392 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा पैकेज, तत्कालीन सी.ई.ओ. वॉरन एंडरसन के प्रत्यार्पण की कोशिश, मृतक के परिजनों को 10 लाख स्थायी विकलांगों को 5 लाख, कैंसर व गुर्दे की बीमारियों से ग्रस्त प्रभावितों को 2 लाख, जख्मी हुए लोगों को 1 लाख मुआवजा दिया जाएगा। पैकेज में 300 करोड़ रुपये पर्यावरण, 272 करोड़ चिकित्सा व सामाजिक क्षेत्र के लिए निर्धारित है।

दिसम्बर, 2011 तक नियत समय सीमा में सभी काम पूरे करने के लिए कैबिनेट ने केन्द्रीय समिति (ओवर साइट कमेटी) गठित करने का फैसला किया है। इस समिति की निगरानी में पीड़ितों को राहत राशि का वितरण किया जाएगा। इसके साथ पूर्व चेयरमैन वॉरन एंडरसन के प्रत्यार्पण और इस हादसे में सुप्रीम कोर्ट के 1996 के पुराने आदेश के खिलाफ सुधार याचिका दायर करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 1996 में इस मामले में मुकदमों की धारा कमजोर करने वाले फैसले को चुनौती दी जाएगी।

* Speech was laid on the Table.

*SHRI B. MAHTAB (CUTTAK): I would like to express my views in the matter that is tragic and beyond all comprehension. It is said history repeats itself who or where the people have a tendency to forget it. Once Bhopal Gas Explosion was a tragedy and then it has become a farce. And this is amply demonstrated here. There is no better illustration than the gas leak in Bhopal in December, 1984 and miscarriage of justice in June, 2010. The path to the criminal trial and conviction of some people on June 7, for 'rash and negligent' conduct that resulted in the death of over 20 thousand people and injury and harm to over 5 lakh people is full of curious twists and unexplained turns. The delusion of charges in 1996 from culpable homicide to rashness and negligence is a question which needs to be answered. But the history of this leniency travels further back in time to 1989 when all criminal cases in process and that may arise in future, in relation to the Bhopal Gas Disaster were quashed by the Supreme Court when Union Carbide Corporation paid 470 million US dollars. In February, 1989, the Court said this would "enable the effectuation of the settlement". But in December, 1989, another bench the effectuation of the settlement." But in December, 1989, another bench of the Court found that the Claims Act, under which the Government had taken over the litigation had nothing to do with the criminal cases and that part of the settlement derive from the Act but was beyond it. And in 1991, the Court, unable to sustain the quashing of criminal cases, backtracked and the criminal cases were revived. This was before the dilution of the charges in 1996. The quashing of criminal cases continues to be shrouded in a mystery.

It is very clear that criminal liability was not negotiated under the Claims Act. The Government says it had nothing to do with the quashing of the criminal proceedings. The Supreme Court claims to have the power to go beyond law but says it had not been given grounds for doing so at that stage. It does not say why, then it did what it did. It appears, the Supreme Court had quashed the criminal proceedings for no stable reason.

* Speech was laid on the Table.

The world's worst industrial disaster occurred on the night of 2 and 3 December 1984, when a tank full of deadly methyl isocyanate (MIC) gas exploded in Carbide's to two years' imprisonment. The case, it seems have been treated as a traffic accident.

What happened between December 1984 and June 2010 is now history. Warren Anderson, the Chief of Union Carbide, thought put on bail, escaped to the USA, ever to come back to face trail and thereby hangs the tail. Straight jacketed by the Supreme Court order, the Magistrate, after a trial that continued for 18 years, convicted the accused under Section 304-A of the IPC with some Minor offences and sentenced them to undergo rigorous imprisonment for two years each with a fine. This is the penalty for causing the death of over 20 thousand and incapacitating more than 5 lakh people.

Today, there has been outrage throughout the country which has compelled jurists and academics to find ways and means to undo the injustice that is inflicted on the victims of Bhopal Gas tragedy. The Attorney General has advised the government to file a curative petition in the Supreme Court under Article 32 read with Article 142 of the constitution. Former Chief Justice of India, JS Verma, has also made a similar suggestion. But there are legal obstacle to it and it needs to be overcome.

Other than the legal aspect, ultimately it is the relief in the curative petition which is a matter of the court's discretion. In trying to "undiluted" the charge and restore the charge under Section 304 Part II of IPC, the Supreme Court shall find the equity of the need for fair trial of the accused pitted against the cry of justice for the victims of 1984. No doubt the offence is grave and horrendous, but the accused have also faced protracted trial spread over 18 years. Mr. Keshab Mahendra, one of the convict, is reported to be 85 and Warren Anderson, the fugitive, is already go and rumoured to be suffering from Alzheimer disease. The crucial question is whether the Government will be able to get him extradicted.

The Bhopal Gas disaster has been a tragedy compounding a tragedy and has blurred the question of which one is greater, the original which cost 20 thousand lives and 5 lakh injured or the travesty of justice which was reduced the World's worst industrial disaster into a force. There are 5 lakh 60 thousand claims for disabilities pending before the courts, none of them addressed so far. It seems, the blunders of Bhopal gas tragedy never seem to end, nor does the nightmare. I demand the Government should come out with clear package for the benefit of the affected people. At least in doing so, one can do justice belatedly though.

MR. CHAIRMAN : Now, Dr. Tarun Mondal may speak. You may very briefly tell the points you want to raise and finish in two minutes.

17.00 hrs.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, before I start my speech, I would like to submit that I had given a notice to hon. Speaker on 25th June 2010 to hold a full-fledged Session on this issue, but you are giving me only two minutes. Sir, I plead your protection to allow me to raise at least four or five points.

MR. CHAIRMAN: Okay. You tell the points.

DR. TARUN MANDAL : First, the way the discussion was continuing in this House, it seems to me, a new Member, as if it was not a discussion on Bhopal gas tragedy but I was viewing some Hollywood or Bollywood comedy movie!

Sir, there is a saying that if you kill one person, you are a murderer or a killer, but if you kill thousands and lakhs, you are a hero. Warren Anderson, killing more than 25,000 people and injuring at least half a million people in and around Bhopal, has not only become a national hero but is an international hero now. I would like to say that not only the CEO of Union Carbide, Shri Warren Anderson is responsible, but the then Prime Minister was also equally, morally and ethically responsible for whatever tragedy happened in Bhopal and its aftermath. After the statement of the then Chief Minister of the Madhya Pradesh, Shri Arjun Singh, it has become clear that responsibility goes more to the then Prime Minister.

Sir, already the statement of Gordon Streeb, who was the Deputy Chief of Mission of the US Embassy in New Delhi, has come before the House and also the matter of then CBI officer in-charge, Shri Lall has been placed in the House, which tell how the investigation was influenced not to extradite Warren Anderson to India.

I also want to say that at the same time, the Opposition, the so-called BJP and CPI(M) and other opposition parties, were also equally responsible in the

sense that they do not have any propriety. The Opposition Parties like the BJP and CPI(M) should not have complained on this issue. After the Government of Rajiv Gandhi, V.P. Singh led Government was supported by BJP and CPI(M) and the United Front Government was supported by the Congress and the CPI(M). Thereafter, the BJP led NDA Government. The UPA-I Government enjoyed the support and cooperation of the CPI(M) also. These Governments progressively did not do anything in regard to this case.

Sir, I want to say that the formation of the Group of Ministers after the court verdict to increase only the compensation part was simply to hoodwink the people of our nation and to save the real culprits from punishment. After the Bhopal tragedy, a group of 60 members from NATO came there and one of them was Warren Anderson also. What they experimented and what they recommended was never revealed. That should be revealed.

Finally, I want to tell you that a lot of warnings were given by the intellectuals, environmentalists and citizens of Bhopal against the installation of that plant for production of dangerous pesticides by the Union Carbide in Bhopal, but they were never paid heed to. I want to submit that the Government must, first of all, give proper compensation to the victims and their kith and kin, which matches the international standard.

Secondly, the area of Bhopal should be immediately cleaned, and we should make it environment-friendly. Thirdly, all the culprits inside India and outside should be brought to book and punished accordingly.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shrimati Yashodhara Raje Scindia. Madam, please be very brief.



***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** भोपाल गैस त्रासदी के समय और उसके पश्चात् घटी घटनाओं के कारण नोटिस 193 के चर्चा में निम्नांकित सुझाव ले कर रहा हूँ -

- 1) न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं जनता की अपेक्षा के अनुरूप बनाने के लिए जूडिसियल सिस्टम में शीघ्र सुधार करना चाहिये । मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरणों का वर्गीकरण कर स्पेशल न्यायालय स्थापित करने चाहिये ।
- 2) प्रकरण से जुड़े हुए सभी अधिकारी (राज्य सरकार एवं भारत सरकार) तथा मुख्य मंत्री एवं मंत्री तथा प्रधानमंत्री व मंत्री सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ।
- 3) यदि न्यायिक संस्थाओं की लापरवाही भी प्रतीत होती है उनको भी संसद द्वारा जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए ।
- 4) भारत द्वारा प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार एंडरसन का प्रत्यर्पण शीघ्र किया जाना चाहिये एवं पीड़ितों को हर तरह का मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

* Speech was laid on the Table.

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** भोपाल में घटी विश्व की सबसे भीषणतम गैस त्रासदी के समय में भोपाल में ही था । और इस कारण में इसके कई घटनाक्रमों का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ ।

इस घटना में हजारों व्यक्ति मारे गये, हजारों पशु काल को कवलित हुये तथा हजारों मरे हुये पक्षियों का उस क्षेत्र में ढेर लग गया ।

यह भूमि काली परेड के नाम से थी । जिसपर नबाबी काल में सेना की परेड होती थी ।

मास्टर प्लान में यह भूमि खुली भूमि के नाम से छोड़ी गई थी ।

बाद में 1975 में इसे यूनियन कार्बायन को दिया गया जब देश में आपातकाल लगा हुआ था ।

यह भूमि उस समय भी आबादी के निकट थी जो अब तो आबादी के बीच आ गई है ।

वहां कारखाना क्यों लगाने दिया गया ।

सन 1981 में भी थोड़ी मात्रा में गैस रिसने की घटना घटी थी । जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी उसे नजरअंदाज क्यों किया गया । इस घटना की जांच का काम मध्यप्रदेश के प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा आरंभ कर दिया गया था । किन्तु दिनांक 6 दिसंबर को जांच का काम सी.बी.आई. को सौंप दिया गया जिससे पुलिस की भूमिका कम हो गई ।

इस बीच सी.बी.आई. द्वारा एण्डरसन मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रकरण में कंपनी के 8 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण बना दिया गया था उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया ।

कम्पनी के अध्यक्ष श्री एण्डरसन उन दिनों भोपाल में ही थे उन्हें भी न्यायालय में प्रस्तुत किये बिना मुचलका पर छोड़ दिया गया मुचलके पर छोड़ा जाना गैरकानूनी था लेकिन सी.बी.आई ने चार्जशीट में लिखा कि सभी औपचारिकताये पूरी कर ली गई है ।

अब केन्द्र सरकार सुधार याचिका ला रही है ।

एण्डरसन पर वारन्ट तामील क्यों नहीं किया जा सका जबकि अदालत ने गैरजमानती वारन्ट जारी किया था ।

सी.बी.आई देश की एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्था के रूप में जानी जाती है । किन्तु अब उस पर अनेक प्रकार के आरोप लगने लगे हैं । इसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि सी.बी.आई. की कार्य प्रणाली, अधिकार क्षेत्र तथा पारदर्शिता पूर्ण कार्य की दृष्टि से पुनः विचार किया जाये । इसके लिये

संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए । जिसके प्रतिवेदन के आधार पर शासन आगामी कार्यवाही करे । एण्डरसन की जमानत लेकर उसे शासकी विमान से दिल्ली भेजने की चर्चा उठने पर एक पक्ष ने इसे राज्य सरकार की कार्यवाही एवं दूसरे पक्ष ने केन्द्र सरकार की कार्यवाही बताया ।

यह भी चर्चा चली कि तत्कालीन मुख्यमंत्री यह उत्तर दे कि उसको छोड़ने का जिम्मेदार कौन है

यह भी कहा गया कि उनके द्वारा संचालित एक संस्था ने यूका से चन्दा लिया है ।

पहले तो इसे अस्वीकार किया गया किन्तु बाद में संस्था के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हां चन्दा दिया गया है ।

मध्यप्रदेश को मिला ।

1. घटना घटने के तत्काल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि एंडरसन को तत्काल गिरफ्तार किया जाए । उसे यू.के. के गेस्ट हाउस में लाया जाए ।

2. किन्तु बाद में उसी दिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उसे छोड़ दिया जाए। इस आधार पर तत्कालीन कलक्टर और एस.पी. उसे एयरपोर्ट लाये और शासकीय विमान से उसे दिल्ली रवाना कर दिया गया । ने थाने पर ले गये और कोर्ट में पेश किया ।

3. यह संभव नहीं है कि इस घटना के अपराधी को मुक्त करने की हिम्मत मुख्यमंत्री कर सके इसमें केन्द्र की सहमती बिना यह हो सके ।

4. उन दिनों तत्कालीन प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश के ही दौरे पर थे यह बताया जाता है कि उनके निर्देश पर ही मुख्यमंत्री ने यह कार्य किया इसकी पुष्टि तत्कालीन विदेश सचिव ने की ।

इस कार्य के लिये अमेरिका ने भारत पर भारी दबाव डाला था । मार्च 1985 में चुनाव होने वाले थे । उसके लिये यूनियन कार्बाइन से कांग्रेस को काफी बड़ी राशि का चन्दा मिला ।

अब तो सी.बी.आई. के पूर्व अधिकारी ने यह रहस्योद्घाटन कर दिया है कि किस तरह तत्कालीन केन्द्र सरकार ने एण्डरसन को बचाने की कोशिश की थी ।

1. एण्डरसन को सुरक्षित रूप से पहुंचा देने के कार्य का जिम्मेदार कौन है इसका खुलासा किया जाये। जिससे भोपाल के गैस पीड़ितों तथा जनता को पता लग सके कि उसके विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद भी उसे कैसे जाने दिया गया । इस बीच उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया जिसके तहत मामले को धारा 304 के बजाए 304ए में बदल दिया गया जिसमें दोष सिद्ध होने पर अधिकतम दण्ड दो वर्ष का है । जिन न्यायाधीश धारा बदलने का निर्णय लिया था बाद में उनकी अध्यक्षता में ही गैस पीड़ितों के लिये खोले गये अस्पताल की संचालन समिति का आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया ।

इस अस्पताल में गैस पीड़ितों की बजाये फीस लेकर अन्य लोगों के इलाज किये जाते हैं ।

अब केन्द्र सरकार इस विषय पर सुधार याचिका लगा रही है । इस घटना में मरने वाले व्यक्तियों की भी निश्चित संख्या सामने नहीं आई है । जानकार लोगों का आरोप है कि मृतकों की संख्या अधिक है जिनके शवों को प्रशासन द्वारा पानी में बहा दिया गया ।

इसी प्रकार पीड़ितों की संख्या का भी सही आंकड़ा सामने नहीं आया है जिन पीड़ितों को मुआवजा मिला है उनके अतिरिक्त अनेक पीड़ित ऐसे हैं जो मुआवजे से वंचित रहे हैं ।

नगर के 56 वार्डों में से केवल 26 वार्डों को ही गैस पीड़ित घोषित किया गया है ।

शेष 20 वार्डों में भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो गैस पीड़ित हुये थे लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। जिन मृतकों को मुआवजा दिया गया उन्हें भी मात्र 50-50 हजार रुपये दिये गये ।

सभी गैस पीड़ितों को 20 वार्डों सहित मुआवजे में मृतकों को न्यूनतम 10 लाख रुपये , गंभीर रूप से घायल को 5 लाख रुपये तथा सामान्य रूप से घायल को 1 लाख रुपया दिया जाए

1. एण्डरसन को सुरक्षित रूप से पहुंचा देने के कार्य का जिम्मेदार कौन है इसका खुलासा किया जाये । जिससे भोपाल के गैस पीड़ितों के गैस पीड़ितों तथा जनता को न्याय मिल सके ।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। संसद में हर साल जब भोपाल गैस त्रासदी की एनिवर्सरी आती है तो हम लोग यहां दिन भर बहस करते हैं। शायद जिन लोगों ने आज हंसते हुए लोगों के ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने शायद लोक सभा टी.वी. देखा नहीं है। अगर वे लोक सभा टी.वी. देखते तो जिस तरह से जनता हमारी तरफ देखती है कि कैसे हम कार्यवाही करते हैं और कैसे हम इस अगस्त हाउस में बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे गंभीर और मानवीय विषय पर हम लोग इस तरह से एक-दूसरे को इंटरप्ट करते या एक-दूसरे के ऊपर हंसी-मज़ाक करते।

सभापति महोदय, आज हमारे सामने कई ऐसे तथ्य आए हैं, परन्तु मैं सबसे पहले संसद के सभी महानुभावों को यह कहना चाहती हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से तथ्यों के साथ भूमिका बनाई, अगर मैं भूमिका के शब्द यूज़ करूं तो अपनी नेता प्रतिपक्ष पर अन्याय कर रही हूं। हमारे सामने कई चीजें आती हैं, जिन्हें हम पोलिटिक्स से ऊपर हट कर, इसके ऊपर बहस करके, मिल कर कुछ निचोड़ निकाल कर इस निष्कर्ष पर आएंगे। हमारे भोपाल के विक्टिम्स को मानवीय आधार पर जो अन्याय मिला है, उन्हें कम से कम 25-26 साल के बाद न्याय मिलना चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई है। उन दिनों में जिस तरह से फैक्ट्रियां शहर के अंदर लगती थीं, वह आज की तारीख में मैंने देखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इन सब इंडस्ट्रीस को बाहर निकाला है। मुझे नहीं लगता कि 26 साल पहले इन लोगों को शहर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति मिलती, जिसके पास ऐसे पॉयजनैस गैस की फैक्ट्री है, जो पूरे शहरवासियों को प्रभावित कर सकती थी। जो हुआ, सो हुआ। कई ऐसी मिस्टैक्स हुईं, मैं उनमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम 26 साल से इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। दुनिया जितनी प्रोग्रेस कर रही है, हम सब मान सकते हैं कि यह पूरे भारत में सबसे बड़ी मैन मेड ट्रेज़डी थी, हम इसे एवाइड कर सकते थे। न्यू ओरलियंस, अमेरिका में हरिकेन कैटरिना आई, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ मदद नहीं की। मैं इसलिए इस बारे में बता सकती हूं, क्योंकि मैं न्यू ओरलियंस में रहती थी। मैं वहां देख रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे वहीं रहते हैं। वहां सौ-सौ दिन के बाद अभी तक राहत नहीं मिल रही है। दुनिया बदल गई।

सभापति महोदय, अब प्रेसीडेंट ओबामा की नयी सरकार आई है। बीपी का न्यू ओरलियंस के बाहर ऑयल स्पील हुआ है। प्रेसीडेंट ओबामा ने पूरी दुनिया को हिला दिया और कम्पनसेशन बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से अमेरिका के लिए लाए। हमारा देश भी 25 साल के बाद भीख मांगने की बजाए एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजिशन पर आ गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हम लोग इस डिबेट के बाद थोड़ा

सोचें, उस निष्कर्ष पर आएँ कि आज जो यह देश प्रोमिनेंस में आया है, अमेरिका भी हमारे सामने भीख मांगने के लिए आता है।

कई चीजों के लिए, हाथ मिलाने के लिए, तो क्या हम उस शक्ति से अपने आप देश में खड़े नहीं हो सकते हैं। कुछ कम्पैन्सेशन जो पिछली बार नहीं मिला, फिर से मांगने के लिए क्या हम एकजुट नहीं हो सकते ? अंग्रेजी में एक कहावत है- “To err is human, but to forgive is divine.” मैंने कोई तैयारी नहीं की।

महोदय, मैं मध्यप्रदेश की एक जनप्रतिनिधि हूँ और जिस प्रकार से यहां माननीय सदस्यों ने हंस-हंस कर बातें कही हैं, उन्हें देख और सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने अपनी नेता प्रतिपक्ष से कहा कि मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए। अगर हम जनता को न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय करेंगे। “To err is human” हम सब लोग गलती करते हैं। उस समय जो भी शासन था, उसने गलती की। इस बात को सब मानते हैं, फिर हम उसे क्यों कोसें। हम उसे कोसें नहीं। हमें वह कम्पैन्सेशन चाहिए। हमारी आम जनता लोक सभा टी.वी. के माध्यम से देख रही है कि क्या हम अपने देश की भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित जनता यानी उस आदमी को जो तीन पीढ़ी के बाद अभी भी सफर कर रहा है, उसे न्याय दिला सकते हैं? अगर हम एक हो सकें, तो क्या हम उन्हें न्याय नहीं दिला सकते हैं? हम उस कम्पैन्सेशन को उन्हें दिला सकते हैं।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):**

2/3 दिसम्बर, 1984 को आधी रात के बाद भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली। यह दुनिया की औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है।

इस त्रासदी का शिकार हुए लोग अब दूसरी त्रासदी का शिकार हुए। सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए लोगों को निराशा हाथ लगी। 8 जून भोपाल गैस कांड के मुजरिमों को मामूली सजा और हाथों-हाथ जमानत मिल गई। 25 साल बाद हुए फैसले के बाद 15 हजार लोगों की मौत की सजा सिर्फ 2 साल, 25 साल बाद आए इस फैसले में करीब 25 हजार लोगों की मौत की जिम्मेदार कंपनी पर 11 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है यानि एक मौत पर 55 सेंट (करीब 26 रुपये) क्या एक आदमी की जिन्दगी की कीमत सिर्फ 26 रुपये है।

इस घटना के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को सरकारी कवच प्राप्त है। भारत सरकार और न्यायपालिका ने एंडरसन के प्रति नरम रुख अपनाया जिसके चलते एंडरसन भारत से भागने में कामयाब हो गया। एंडरसन को भगाने में केन्द्र सरकार की भूमिका थी। देश को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस ने सरकार से यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख वारेन एंडरसन को भारत लाने और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने को कहा लेकिन अब तक 'वॉरेन एंडरसन' को भारत न लाया जा सका। यहां तक की एंडरसन को भारत से फरार होने के लिए भी 'सरकारी विमान' मुहैया कराया गया ऐसा क्यों ? नटराजन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

एंडरसन को बचाने में भारत सरकार का भी हाथ था। आर.बी. लाल ने खुलासा किया कि नब्बे के दशक में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सी.बी.आई. को निर्देश मिला था कि यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष एंडरसन की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के मामले में ढिलाई बरती जाय। केन्द्र के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा की वारेन एंडरसन को भगाया जाना जरूरी था क्योंकि लोग उसे मार देते, उसे फटाफट जमानत मिल जाती और इसमें अमेरीका से जरूर दबाव सरकार पे पड़ा होगा सरकार इसको स्पष्ट करे यह मेरी मांग है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 25 साल के अंतराल के बाद त्रासदी से ग्रस्त लोगों को क्या न्याय मिला?

* Speech was laid on the Table.

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस भयंकर त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए जिससे भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके।

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Bhopal gas tragedy no doubt was one of the most tragic incident in independent India. Thousands of people died, injured and still suffering is a question of great concern for all in our country.

It is again a matter of great shame that even after 25 years of the incident of fair judgement of the case has not yet come. It is pointed by many and the media that there were serious lack of responsibility from the part of the officials concerned with the safe operation of the Union Carbide Plant. But, the judgement on the case has not reflected these serious lapses and after 25 years a too meager punishment was ordered by the Courts.

What is more alarming is the reported that, again it will take 25 more years according to the formalities of litigation in our Courts to have a review and completion of formalities. This is an injustice to the poor victims of the tragedy, who are still suffering the calamities of the tragedy.

What is now happening, I think is just politicizing the matter, and I do not think that those accuse the Government for non-action are saints, as during the last 25 years all major parties had their own share in the governance of this country

It should be also our concern that, in future all necessary measures have to be taken to avoid such accidents and to see the laws are to be framed to check escape of culprits by using the Courts in the country and delaying the proceedings in such a way that the very relevance of the case is eroded and the victims are left for un-ending suffering.

What is needed at this our is to think of the relief to be given to the poor victims. I am not justifying the concerned people in their negligence that caused the culprits escaped from the clutch of law, but trying to draw the attention of this August House to listen to the need of the hour, that there should be an attempt from the part of the authorities concerned that the poor victims of the tragedy have to be taken care of and rehabilitate them in such a way that those who are destined for prolong suffering and treatment have to be provided with necessary facilities.

* Speech was laid on the Table.

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Dr. Max Daunderer, internationally famed German toxicologist, arrived in the Madhya Pradesh capital with a large supply of sodium thiosulphate- the only known antidote for cyanide poisoning, within a week of the Bhopal gas tragedy. But the doctor was forced to leave the country, reportedly under threat of his life. Why? And now why a concerted campaign against the use of sodium thiosulphate?

A feeling is gaining ground that at the decision-making level in the Madhya Pradesh Government and at the Centre, there is a strong lobby working in liaison with Union Carbide. That a systematic attempt is being made by an influential section to cover up the extent and scope of damage lethal methyl isocyanate (MIC) gas can cause to the internal system of the human body. And to thereby help the multinational escape paying reasonable compensation to the victims of the tragedy. Sources allege that soon after the MIC leakage from Union Carbide Bhopal pesticide plant, the multinational corporation pressed its public relations operations in top gear. Scores of public relations specialists were hired to contain public hostility and alarm. And many Indians, it seems, became willing performers in the multinational's design.

First, a controversy raged over the killer effect of MIC-even though the tragedy was there for everybody to see. Then a storm blew up on the line of treatment for gas victims. Now, a new controversy has been triggered as to whether the case against Union Carbide is sustainable in US court of law, and whether the people entrusted with the task of sorting out the issue of compensation to the MIC victims have been "obliged" into adopting a laissez-fair attitude or are being led up a blind alley in American courts. Simultaneously, there would appear to be an insidious attempt to disprove that the cause of the havoc in Bhopal was cyanide-poisoning.

Union Carbide, in fact, has been exceptionally touchy about the cyanide-poisoning theory right from the time of the tragedy. Even though the prognosis of

* Speech was laid on the Table.

Dr. Heeresh Chandra, Head of the Forensic Department, Hamidia Hospital, Bhopal where the autopsies of all those who died because of MIC- exposure were conducted was that the cherry-red blood of the victims indicated cyanide poisoning. Dr. Max Daundere, who arrived in Bhopal on December 4, 1984, with a large supply of sodium thiosulphate, the only known antidote for cyanide poisoning, suggested that the drug be administered to all victims. But it was not. Instead, Dr. Daunderer was asked to leave the country (see box). Why? Was someone afraid that his continued presence would only confirm cyanide poisoning in the MIC-exposure cases? That would have pushed up the quantum of compensation astronomically. And this is where the role of the anti-thiosulphate lobby starts appearing dubious.

About-turn: Ever since an Indian Council of Medical Research (ICMR) team identified cyanide-poisoning as the cause of the gas victims' plight, and recommended sodium thiosulphate treatment, the lobby has been frantically trying to persuade the Council to issue a directive that treatment with the drug is no longer necessary. And it seems to have succeeded. It is said that Dr. Ishwar Das, commissioner for rehabilitation of gas victims, and Dr. N.P. Mishra head of the department of medicine, Gandhi Medical College, Bhopal, went to Delhi on September 5, 1985 to press the anti-thiosulphate case. Though Dr. Mishra returned after a day stay, Dr. Das stayed back in the capital about a week. And soon, the directive came. Rather an abrupt about-turn for the ICMR. It is also strange that nobody has cared to raise the issue of the dangers of treatment with bronchodilators and steroids, which are being widely used on those suffering from MIC exposure. These not only have adverse after-effects on the human body, they also do not guarantee a permanent cure, reveal medical sources. As a result, so far, it is largely the symptoms that have been treated, not the real cause. It would appear that the considered opinion of many leading doctors-both in the country and abroad-carries little weight with the decision-makers. Or Union Carbide, for that matter.

Within hours of the Bhopal tragedy, Dr. Avashia, medical director, Institute Plant, USA, sent a telex message to the Bombay, Delhi and Bhopal offices of Union Carbide, on December 3, 1984, suggesting : “If cyanide poisoning is present, administer sodium nitrite and sodium thiosulphate. If the patient does not respond to the amyl nitrite or if severe exposure is suspected, administer intravenously 0.3 gm sodium nitrate at the rate of 2.5 =5 ml a minute, followed by injection of 12.5 gm sodium thiosulphate at the same rate and via the same needle and vein.” But the suggestion did not reach the medical community. Was it suppressed?

Even the initial recommendation of the ICMR that sodium thiosulphate be administered to those showing symptoms of cyanide poisoning was short-circuited. In the second week of December, the director of health services, Madhya Pradesh, ostensibly on an order from the Union Health Ministry, banned the use of sodium thiosulphate. It was only after a fatal lapse of two months that this decision was officially reversed. But no clear guidelines were issued. Nor was any arrangement made drug’s availability in the quantity required for detoxification of the affected people. Of the over one lakh needing sodium thiosulphate, only five per cent have been lucky enough to get the injection, informs K.N. Pradhan, Member of Parliament from Bhopal.

Pradhan feels that Union Carbide was aware of the possibility of cyanide poisoning in the event of leakage of MIC. The multinational, however, claimed that the gas was harmless and not a killer. But then, certain sections point out, an admission to the contrary would have left the company highly vulnerable in compensation cases. The Carbide vice-president for health, safety and environmental affairs, Jackson Browning, said in March this year that the corporation would sponsor a metabolism study on animals to see whether a single large exposure to MIC could lead to cyanide poisoning. Curious indeed, considering that in a report on MIC published by Union Carbide in 1976, it is clearly stated that thermal decomposition of methyl isocyanate may produce

hydrogen cyanide. More curious is the fact that all information about the nature of the gas which leaked from the Bhopal plant as well as the autopsy findings were withheld for the medical community as well as the public by both Union Carbide and the Government.

The medical officer of Union Carbide, Dr. Jaeger of the World Health Organisation, and the committee set up by the MP Government to enquire into the cause of the deaths insisted that there was no evidence of cyanide poisoning and only the lungs and eyes of victims were affected. The role in this regard of Dr. M.N. Nagu, director of health services, MP, is also intriguing. Dr. Nagu, it is said, kept the ICMR recommendation regarding sodium thiosulphate to himself. He also did not release the thiosulphate stock that he had for some time. When faced with a hostile demonstration, he told a delegation of the Sangharsha Morcha that the drug was available to 'whoever wants to have it'. But he did not arrange for its supply. Could his attitude have something to do with the fact that his brother, R. N. Nagu, a former inspector-general of police, had a Rs. 4 lakh- a year contract for the security arrangements at Carbide's Bhopal plant. When contacted, Dr. Nagu said he had no time to meet PROBE. So, it was impossible to get his clarification.

Dubious role : The man most blamed in the thiosulphate controversy, however, is Dr. N.P. Mishra. He was among the first to suggest that the MIC victims needed only bronchodilators and steroids. This was in tune with the Union Carbide stand. Incidentally, Dr. Mishra has been a long-time medical consultant to Union Carbide. He also visited the USA after the tragedy despite a government order prohibiting him from doing so. When asked how he was allowed to go, Chief Minister Motilal Vora claimed that he got to know about Mishra's trip only after the doctor had left the country.

It is also telling that Dr. Mishra, R.N. Nagu and a few others have been used in the British Broadcasting Corporation's television film, the Poison City, to give the impression that the Bhopal tragedy was the result of callousness on the part of the state and Central Governments. It is learnt that Union Carbide rather

keen on using the film in its defence in court. And while Dr. Mishra's role in the film may be dubious, his continuing opposition to sodium thiosulphate is inexplicable

The ICMR minutes show that on February 14, 1985, at a meeting which discussed the findings of clinical trials conducted by a team of doctors under noted cardiologist Dr. P.S. Narayanan, it was decided to recommend thiosulphate for MIC victims who showed respiratory, gastrointestinal and neuro-muscular complications- all symptoms of cyanide poisoning. Dr. Mishra also attended this meeting and pointed out that out of 200 victims who had been administered thiosulphate injections, two had shown signs of adverse reactions. To which Dr. Narayanan responded that of 90 victims who were administered 322 injections under his close observation, only two had shown any sign of a reaction. Dr. Mishra's objection was thus overruled, and the ICMR decided to recommend sodium thiosulphate for the gas victims.

Further Dr. Mishra, on behalf of the department of medicine, deposed before a gathering of scientists on May 4 that in his study of 200 cases, 60 per cent got relief with sodium thiosulphate. Why, then this subsequent volte face?

Curiously enough, neither the ICMR nor the MP Government released the thiosulphate recommendation. Dr. M.N. Nagu, for reasons best known to him, sat on the ICMR report. The state health department, too, chose to keep various findings under wraps. As Dr. Punuavratha Goon of the Drug Action Forum and Dr. A.R. Phadke of the Medico Friends Circle- who are helping the gas victims point out, /dr. Daunderer had demonstrated the presence of cyanide in blood gas victims as early as December 4, 1984. The two trials conducted by the ICMR further confirmed cyanide poisoning and proved beyond doubt the efficacy of sodium thiosulphate in treating it. But the report is yet to be seen.

Then again, what prompted the ICMR, shortly before the Union Government appointed a committee to investigate the gas tragedy, to declare that there was no reason to believe that there would be any long-term effect of MIC

poisoning on the human system? This opinion though subsequently denied-greatly helped those who wanted to underplay the tragedy. And came in handy for the anti-thiosulphate lobby-which seems determined to establish that the theory of cyanide poisoning is sheer nonsense, despite Dr. Heeresh Chandra's assertion that even today, thiosulphate is effective in treating MIC cases. According to Dr. Phadke, too, it is advisable to administer thiosulphate to all the victims. For studies in the West have shown that cyanide poisoning can be chronic. But, he says, it will take over a month to give thiosulphate injections- even if they are available to the MIC affected population of about 1.5 lakh. For the 10 clinics in Bhopal are severely handicapped by a lack of trained personnel.

Suspicious activities : There are other sides to the thiosulphate controversy, too. The Madhya Pradesh government spokesman and the anti-thiosulphate lobby describe the whole thing as a question of conflicting medical opinion. Dr. Basaria, former Congress mayor of Bhopal who is so said to be a beneficiary of free medical aid from the USA, feels that the controversy is unnecessary. Many responsible citizens among them two Congress (I) MPs and a senior Doctor also believe that the tank from which the lethal gas leaked out contained some new chemical, which either went out of control or was "deliberately released" on the poor people of the areas as "part of a diabolical chemical warfare experiment." While this may sound somewhat far-fetched, the activities of Union Carbide's research and development center at Bhopal do raise suspicions.

While the pesticide plant had been running at a loss for some years, the company continued to make investments of up to Rs. 20 crore in it every year. To screen new formulations, it is claimed. The unit has 2,700 sq ft of the most sophisticated greenhouses and two hectares of farmland. Surprisingly, however, it conducted studies without getting projects cleared by the high-level screening committees of the Government of India of which the secretary, Ministry of External Affairs, and the defence adviser are members. The company also conducts biological research in the strategic area of North-East India. When Dr.

Vasadarja, secretary, department science and technology in the Prime Minister's Secretariat at the time when technical sanction for the Bhopal research and development center was given, was asked whether he was aware that the center conducted studies on lethal chemical and bacteriological formulations, he said I was not.

Against this backdrop, it is interesting to note how, over the years, the multinational has been pains to keep men of means under obligation. A Congress (I) leader is the Carbide lawyer. Besides, prior to tragedy, the company's guest house in Bhopal was always at the disposal of the ruling party. A Central minister used to stay there whenever he visited the city. During the Congress (I) regional conference, many Central ministers were accommodated there. It is always alleged that senior politicians and civil servants were "obliged" by giving their relation jobs in the company "on fat salaries". In fact, among those on the Carbide payroll is the nephew jobs of a former education minister. According to a Congress (I) MP, even Chief Ministers were accorded "lavish hospitality by Union Carbide when they visited the USA." This nexus of big business, bureaucrats and politicians is what, perhaps, stands in the way of justice being done to the gas victims. Some allege that it is the main reason why the N.K. Singh Commission, constituted by the State Government to enquire into the gas tragedy, has not made any headway yet.

Sources reveal that neither Union Carbide nor the State Government are cooperating with the commission. The Chief Minister, however, denies that there is any move to wind up the enquiry. "Not at the moment," he asserts. But then, his government, too, seems to have done little in the matter. It has not yet identified all the victims and the dimension of the damage. Nor has it made out a case for suing Union Carbide. The commissioner of claims is still nearly 10 months after the tragedy-wading through the files to classify the victims. The Tata Institute survey on the gas victims has been another joke- with only 11 wards adjacent to the Carbide factory have been covered by it.

The Tata Institute survey could identify only 9,000 persons who are suffering from the after-effects of MIC exposure-when local doctors put the figure around 1.5 lakh. The survey also took an inordinately long time to be completed. One reason for this is said to be the institute's insistence on taking the data collected to Delhi for processing by computer-even though computer facilities are available in Bhopal. It is learnt that for two months, the papers did not reach the Capital. A subsequent station-to-station hunt for the consignment led to its recovery from the godown at an obscure railway station between Gwalior and Jhansi. Was a deliberate attempt made to "lose" the papers in transit? Or was this just another instance of bureaucratic apathy? Is there a motive behind the latent callousness?

Prolonging misery : Every non-official agency has placed the number of those who died in the tragedy at between 3,000 and 10,000. But the State Government has arrived at a static figure of 1,754 dead. The comparatively low official figure is bound to help Carbide when it comes to paying compensation. Besides, only 1,196 of the dead have been identified to data. This apart, the Government has not been able to classify the injured, the disabled and the affected. And the Chief Minister claims there is progress in the work? To claim compensation, as K.N. Pradhan puts it, the Government needs to prepare a sound case with a detailed medical and clinical report on the victims. But this, again, is not there. Its absence is only proving of advantage to those who do not appear too keen that sodium thiosulphate should be administered to the MIC victims. For acknowledging the efficacy of this drug would be tantamount to accepting the fact that the victims are suffering from cyanide poisoning. There are other indications, too, that a deliberate attempt is being made to prolong the misery of the gas victims by denying them effective treatment.

The mid-August, the Madhya Pradesh health department got a consignment of 10 lakh tablets Rheo-dur a bronchodilator from Key Pharmaceuticals Inc, Miami, Florida, for treatment of gas victims. The medicine, worth around \$ 50,000

(about Rs. 6 lakh) was donated by the company to a Bhopal gas victims' relief organization of Indians settled in the USA, headed by one Dine Chandra. The organization, reportedly through some "helpful sources in the Prime Minister's Secretariat," succeeded in persuading the Government to waive duty on the consignment. Only later was it discovered that the donated tablets' expiry date was September 1985. But this did not deter the authorities from distributing the tablets to gas victims that too, it is alleged, without informing them about the expiry date. One can only wonder why this was done. And what could have been the motive behind sending an expired batch of life-saving medicine for the Bhopal victims?

It is being alleged in certain quarters that there is a move to establish that the general physical condition of the Bhopal victims-predominantly from the low income group was such that the system was more susceptible to MIC exposure than a healthy individual's would have been a result, the gas had a more crippling effect than it would have on a "normal" person. In this way, it is said, the multinational hopes to minimize its responsibility in the Bhopal tragedy. Be the ploy would fail if it is convincingly established that cyanide poisoning is the cause of the gas victims' misery. Which is why the determined opposition to thiosulphate, allege sources.

Can this be true? Are human lives so expendable when it comes to safeguarding a multinational's interests?

***श्री प्रेमदास (इटवा):** आज लोक सभा में भोपाल गैस काण्ड पर चर्चा हो रही है । बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 25 वर्ष बाद आज भी राहत पूरी नहीं हुई । न ही पूरा न्याय मिला आखिर कब तक लोग भारत के अन्याय सहते रहेगे आप को हमको कानून का साथी बनना पड़ेगा आज आपसे में एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा है । दोनो के बीच में जनता पिस गई मेरी राय है तुरंत आवश्यक कदम उठा कर दुबारा जाँच करके प्रति परिवार को एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए मकान दिया जाये । हमारे लोक सभा क्षेत्र में ग्राम बिजौली के एक परिवार भोपाल गैस काण्ड से पीड़ित हुआ । उसके पिता की मृत्यु भी हो गई थी आज भी आंखों से विकलांग है आज भी उसको पूरा न्याय नहीं मिला इतना बड़ा काम होने के बावजूद हमारी सरकार निराश बैठी रही बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरा देश लोक सभा पर आशा लगाये बैठा है । अगर इस चर्चा में न्याय नहीं मिला तो कहा मिलेगा मेरी राय है तुरन्त अधिक से अधिक रोजगारों से जोड़ा जाये और रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाये ।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I am very thankful to say few words regarding Bhopal Gas Tragedy. During 3rd December 1984, toxic methyl isocyanide gas release from Union Carbide India Ltd. (UCIL) pesticide plant killing about 15000 people injuring at least five lakhs others, millions left sick.

Chief Judicial Magistrate Mohan P. Tiwari gave a judgment in connection on the company and seven of its officials for criminal negligence in the world's worst industrial disaster and sentenced the seven two years jail.

There is an opinion among all the section that the delay in judgement is a denied judgement. Most of the members accused the CBI for the long pending investigation. Union Law Minister M.Veerappan Moily has aptly described lower court judgement on the Union Carbide disaster as an example of justice buried and rightly reiterated need for fast-tracking such cases and ensuring proper investigation.

Our Law Minister has assured and asserted that case against former Union Carbide Chief Warren Anderson has not been closed. He is a fugitive. It will be continuing to take action against him.

The compensation of 470 million dollar is given by Union Carbide. The process of distribution of compensation to the victims of Bhopal Gas Tragedy commenced in 1992. Rs.1548/- crores has been awarded as on 31st October 2009 to 5,74,372 claimants of the Bhopal gas leak disaster fund to the eligible by the Welfare Commission.

The Government should give more compensation. It is the public opinion.

The same history should not be repeated. The Law machinery and the investigation agency should not delay in the future. The tragedy is unforgettable and unwarranted one. The Government and the Government machinery should be more alert by taking precautionary measures to avoid such fatal tragedy.

* Speech was laid on the Table

The atomic energy generation should also be followed the protective devices. Every development should be made by giving more protection to the human beings.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Mr. Chairman, Sir, I fully agree with the hon. Member who spoke last. ... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय मंत्री जी, यह मध्य प्रदेश का मामला है और मध्य प्रदेश में सभी लोग हिन्दी समझते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप हिन्दी में बोलें। ... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी, मुझे मालूम है कि आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let him speak.

श्री श्रीकांत जेना : हिन्दी में बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिन्दी में एक समस्या है। हम तो उड़ीसा से आते हैं। मेरी कठिनाई यह है कि हिन्दी में जो जैन्डर बायस है, वह उड़िया में नहीं है। इसलिए हिन्दी बोलने में थोड़ी कठिनाई है। मेरे द्वारा हिन्दी बोलने में कहां पुल्लिंग लगेगा और कहां स्त्रीलिंग, इस बारे में कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेजी में बोलूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिन्हें अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा।

इस डिबेट की श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जो लास्ट स्पीकर थीं, उनकी बात से मैं बिलकुल सहमत हूँ कि जिस गम्भीरता से इस मुद्दे को सदन में लेना चाहिए, उतनी गम्भीरता से नहीं लिया गया है। यदि हम इस मुद्दे को और सीरियसली लेते, तो अच्छा होता। जो हो चुका है, वह हो चुका है। अब आगे क्या करना है, उसके ऊपर यदि हम ज्यादा ध्यान दें, तभी हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इस दिशा में सी.जे.एम. कोर्ट में जो निर्णय हुआ, वह बात अखबार में आई। उन लोगों को दो साल का पनिश्मेंट मिला। उसके बाद सारी दुनिया और हमारे देश ने कहा कि यह क्या हुआ, बस दो साल की सजा? इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद यदि यही सजा देनी थी, तो फिर इतने दिन क्यों बिताए, दो साल की सजा को भी बन्द कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, बल्कि सच्चाई यह है कि यह बात सभी आदमियों के मन में आई। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि यह क्यों और कैसे हुआ, यह बात सबके मन में आ गई।

महोदय, इस बहस को जिस ढंग से नेता विपक्ष ने सदन के सामने रखा, मुझे लगा- That is your right, how you present the case. But it was tuned in such a manner that it looked to me as if you are pointed politically than towards the serious matters involved in this kind of a disaster. It is one of the serious disasters that has happened in modern India.

It is a challenge for all of us. It is a challenge for the Parliament; it is a challenge for the industrialists; it is a challenge for everyone including the law-makers as to what to do. I fully agree with the hon. Member Shri Pinaki Misra when he explained his position that in this country human life has no meaning. What kind of compensation is inbuilt where everything is wanting in our law itself? We need to enact such laws which can take care of this kind of human loss whether caused by motor cycle accident or train accident or a disaster like this kind? What kind of law is really in place today and whether anything is wanting or not? Therefore, this matter is a serious matter which needs to be very carefully deliberated, discussed and we must arrive at a conclusion as to what exactly we need to do as a Parliament. This is not a challenge for the Congress Party; this is not a challenge for the BJP or any other political party. It is a challenge for everyone of us whether we can really conclude in such a manner so that the people will have confidence on us and on the Parliament and the Government, whoever may govern whether in the State or in the Centre.

My senior colleague Shri Chidambaram will be deliberating shortly because this debate is going on in both the Houses. He is there and he will be coming over here after speech, he will also add whatever needs to be added because there are many issues which the hon. Members would be wanting answers from him and he would certainly do that. But I will confine myself only to the issues that were raised.

I need not go to the past. But without referring to the past, we cannot go to the future. The main issue is about the compensation as Shri Mulayam Singhji has said: कि जिसको कम्पेंसेशन मिल रहा है, जिन्होंने एक्जुअली सफर किया है, उनको भी नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको जो मिलना चाहिए था, उनको वह भी नहीं मिला है और जो फिर मिलने वाला है, वह मिलेगा कि नहीं, इस पर प्रश्न-चिन्ह इनके दिल में है। यह सच है कि बहुत सारे लोगों को शायद जो भी कम्पेंसेशन दिया गया है, वह कम्पेंसेशन ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको नहीं मिला है, जो कम्पेंसेशन मिला था। जो नेता विपक्ष ने बताया था कि this was an out of court settlement

which has been amply clarified by many hon. Members and by Shri Manish Tewari. I endorse that view. The fact is that it was determined by the Supreme Court, not by any out of court settlement. That settlement was for 470 million US dollars, that was about Rs.710 crore then. It was not immediately disbursed. It was disbursed after 1992. The total disbursement was of Rs.3,058.44 crore because of the accumulation of interest and variation in the exchange rates. The total disbursement was of Rs.3,058.44 crore though the recommendation was for 470 million US dollars which comes to Rs.710 crore because of this interest and variation in the exchange rates. The category was again decided by the Supreme Court. For death category, it was from Rs.1.00 lakh to Rs.5.00 lakh; for permanent disability, it is from Rs.50,000 to Rs.2.00 lakh; for temporary disability, it is from Rs.25,000 to Rs.1.00 lakh; for minor injury, it is up to Rs.20,000; for loss of belongings, it is Rs.15,000; and loss of live stocks, it is up to Rs.10,000. Now the Cabinet took a decision and I must thank the Home Minister who was chairing the GoM. And whatever was the recommendation of the GoM, that was approved by the Cabinet and this is being now implemented.

Joshiji was demanding Rs.10 lakh for death cases. That has been sanctioned. You asked Rs.4 lakh for permanent disability. That amount has been sanctioned. For cancer cases you asked for Rs.2 lakh. That has been sanctioned. For total renal failure cases you wanted Rs.2 lakh to be given. That has been sanctioned. For temporary disability it is Rs.1 lakh. What you asked for has already been done. This amount is being given. The total amount that would be required is about Rs.669 crore and that is being provided by the Government of India.

The *ex gratia* will be disbursed by the Welfare Commissioner of Bhopal Gas Leak Tragedy. As you all know, under the Bhopal Gas Leak Disaster Processing of Claims Act 1985 and the schemes there under disbursement is being done by the Welfare Commissioner. Welfare Commissioner is not just a person of the rank of a High Court judge but he is a sitting High Court judge. His Deputy is also a District judge. Claims were adjudicated by Deputy Commissioners having

the rank of a civil judge Class-I. Appeals against the orders of the Deputy Commissioners were considered by Additional Welfare Commissioner having the rank of District Judge Selection Grade. Revision appeals were disposed of by Welfare Commissioner. The cases registered were 10,01,723. Cases decided were 10,01,722. One case is still pending for disposal. Number of awarded cases was 5,58,246.

So, this is not being done by anybody, this is being adjudicated by a sitting High Court judge as Welfare Commissioner there.

SHRI PINAKI MISRA : What about the complaints which have not been awarded? Are they finally rejected?

SHRI SRIKANT JENA: All claims have been settled except one.

On the basis of this Welfare Commissioner's adjudication, the disbursement took place. Due to accrued interest and exchange rate variation, an extra amount of Rs.1,503 crore was available with RBI as on 3rd July, 2004. As a one-to-one *ex gratia* that was also given to those who have been awarded earlier. The amount was given to them.

Pending issues relating to disbursement of *pro rata* compensations have been settled. Now, this *ex gratia* which has been sanctioned by the Cabinet will be given to those who have already received a lesser amount of compensation. Suppose somebody has taken Rs.2 lakh for a death case, they would be given Rs.8 lakh. This way this has been framed and decided by the Cabinet.

Apart from this, the Government of India sanctioned Rs.102 crore as immediate relief and rehabilitation between 1985 and 1989. Action plan on medical, economic, social and environmental rehabilitation was approved in 1990 and implemented by the State Government. Total outlay of Rs.250 crore with a cost sharing between Central Government and the State Government was 75:25 ratio. Implementation was completed in 1999.

As regards medical rehabilitation, seven hospitals, five civil dispensaries, two polytechnics, three dispensaries each of homeopathy, unani, and ISMH engaged medical care and treatment of gas victims.

Now, I come to economic rehabilitation – 42 work sheds and 152 industrial sheds were constructed for training of youth and unemployed to get opportunities. About social rehabilitation – 2,486 houses constructed for widows of gas victims; pension sanctioned to 1,077 widows and amount distributed to mothers and children. About environmental rehabilitation – construction of drains, plantation of trees, and augmentation of drinking water supply was done.

In April, 2003, the Government of India sanctioned money under the Jawaharlal Nehru Urban Rural Renewal Mission for a drinking water project, out of which Rs.14.18 crore was provided to Bhopal Municipal Corporation for providing safe drinking water through pipelines to 14 localities around the Plant site. According to the State Government, the project has been completed.

Sir, 36 wards, out of 56 wards of Bhopal were affected by gas affected by the State Government. The people of those areas in these wards received free medical treatment. As regards compensation, it was paid to the claimants, from all 56 wards; however, the claims from the un-notified 20 wards needs to be medically substantiated in order to approve the claims. The issue of notification of remaining 20 wards was also considered by GoM headed by Shri Arun Jaitley, the then Law Minister, in 2003 and was decided to keep the matter closed.

Now, the State Government of Madhya Pradesh is asking to add these 20 wards and include the 56 wards. But that was closed then. ... (*Interruptions*) It is a process which has been done. I am not insinuating any motive or anything but I am stating the fact before the House so that let everybody know.

There has been a number of deaths during the period when claims were made. Many people said that the number of people died was 15,000 or 20,000 but actually this was determined by the Welfare Commission. Its exact figure was

5,295. ... (*Interruptions*) The other death cases - दस हजार से ज्यादा क्लेम हुआ था, लेकिन वेल्फेयर कमीशन ने कहा कि यह गैस लीकेज में नहीं हुआ, उसके बाद हुआ है।

It was decided by the Welfare Commissioner; neither you nor myself can do anything about that. ... (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप उन्हें दे रहे हैं जिनकी मौत पर मौत हुई है। बाद में भी मौतें हुई हैं। बहुत से लोग अपाहिज हो गए थे, उनकी बाद में मौत हो गई, वे 25 हजार से कम नहीं हैं।

श्री श्रीकांत जेना : यह केस उस समय वेल्फेयर कमीशन के पास दिया गया था। वे हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने सब अपील सुनने के बाद जो बताया और निर्णय लिया, उसी निर्णय के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार कार्यवाही कर रही है। उसमें अगर ऐसा कोई केस है और वह वेल्फेयर कमीशन के सामने आए - they can also take a decision on that. This is regard compensation. The issue of legal chronology - उस बारे में श्री चिदम्बरम जरूर बोलेंगे, लेकिन मेरे पास जितनी इन्फार्मेशन है, वह मैं आपके सामने रख देता हूं। If it does not satisfy you, he can also give certain clarifications on that also. The FIR was registered at Hanuman Ganj Thana on 3rd December, 1984 under Section 304A of the IPC.

It was after the incident took place on 3rd December. The case was transferred to the CBI and was registered as case number RC 384S; the CBI had submitted charge sheet in the court of the CJM on 1st December 1987, against 12 persons including Warren Anderson, the then Chairman of the UCC under Section 304 Part II. The Court of Sessions Judge, Bhopal framed charges on 8th April 1993 under Section 304 Part II, culpable homicide amounting to murder and 304, 306 and 429 of IPC with or without the aid of Section 35 of IPC.

Then the real issue came up. It was done not by the Government, but by the Supreme Court. On 13th September 1996, the Supreme Court quashed the charges under Section 304 Part II and directed framing charges under Section 304 (a) rash and negligence act, amounting to death and 336, 337 and 338 of IPC with or without the aid of Section 35 IPC. It was done in 1996 by the Supreme Court. The charges were reduced. So, I am not taking a political position here. From 1996 till today, they did not do anything; and recently only the Cabinet took a decision to

file a curative petition before the Supreme Court to change the decision of the Supreme Court. So, if one points a finger at any Government, then, one can decide it. ... *(Interruptions)* The point is that the Supreme Court took that decision; the decision was not challenged. ... *(Interruptions)* Everyone knows that; you are all hon. Members; I will not go to that extent. But the point is that somehow, somewhere we have all failed. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat. Only the Minister's statement will go on record. Nothing of others will go on record. Please take your seat.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I do not want any argument. Hon. Member, please take your seat. Whatever they say need not be recorded. Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, please sit down.

... *(Interruptions)*

श्री मुलायम सिंह यादव : बहुत लोग ऐसे हैं, जिनको पता ही नहीं कि लिस्ट बन रही है या नहीं? वे गरीब मोहल्लों के लोग थे। हमने पता लगाया है कि वे अति गरीब हैं। वे लोग उस लिस्ट में अपना नाम नहीं दे पाये। उनको पता ही नहीं कि कब जांच हुई? उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे काफी लोग मरे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : मैं मुलायम सिंह जी की बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो क्लेम करने के लिए नहीं आ पाये। उनका क्लेम कोई बिचौलिया ले गया होगा, लेकिन यह एक सीरियस मामला है। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी यह बात कर रहा था कि ऐसे जो केसेज हैं, अगर आपके नोटिस में भी कुछ

* Not recorded.

ऐसे केसेज आये हों, तो आप उन्हें सरकार और वेल्फेयर कमिशन के सामने लायें। उसमें जितनी संभव कार्रवाई हो सकती है, उसे जरूर किया जायेगा।


सुषमा जी, मैंने इसलिए कहा कि डिसीजन हुआ कि 304 (ए) को 304 (दो) में परिवर्तन करने के लिए क्यूरेटिव पेटिशन फाइल की जाये। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने बोला कि आपने क्यूरेटिव पेटिशन फाइल की है। ...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : नहीं, अभी फाइल चल रही है। This is under process by the Law Ministry.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने कहा कि क्यूरेटिव पेटिशन डालनी है। जीओएम ने निर्णय लिया है, यह मैंने बोला है। मैंने वर्तमान सरकार का अभिनंदन किया है। ...(व्यवधान) मैंने वर्तमान सरकार का अभिनंदन किया कि जीओएम ने जो सिफारिश की है, उसमें यह कहा कि क्यूरेटिव पेटिशन डालनी है और उस क्यूरेटिव पेटिशन में 304 (ए) को 304 (दो) में वापिस लाया जाये।

श्री श्रीकांत जेना: इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया कि अगर इस बात को आप पहले बोलकर अन्य बातों को बाद में बोलतीं, तो अन्य बातों को बोलने की जरूरत ही नहीं होती।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने पहले जिन बातों को बोला, उनमें से हरेक बात तथ्य पर आधारित है। सभी के कागज हैं, मैं दोबारा से बोलना नहीं चाहती हूं। मैंने पहले जो बातें कही, वे भी तथ्य पर आधारित थीं और बाद में जो क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में आपका अभिनन्दन , वह भी सही किया।

SHRI SRIKANT JENA: The other decision that was taken by the Cabinet is submission of additional material in support of extradition of Anderson. Anderson came to India on 6th December, 1984 and visited Bhopal on 7th December, 1984. He was arrested, taken to custody on 7th December, 1984 by the State Police. He obtained bail from the Police Station on furnishing a personal bond of Rs.35,000 with one surety. He then returned to Delhi on the same day.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : He did not return but was sent to Delhi. It was a great send off. Do not say that he returned. He was sent by a State plane.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Why a Government aircraft was provided to...
(Interruptions)

SHRI SRIKANT JENA: Shri Basudeb Acharia, let me complete.

MR. CHAIRMAN : You address the Chair.

SHRI SRIKANT JENA: Let me complete. Whatever questions Members have, they can put those questions and the Home Minister is there to answer them.

What I was saying was that he returned to Delhi on the same day and shortly thereafter left the country.

MR. CHAIRMAN: Order please. Mr. Minister, address the Chair.

SHRI SRIKANT JENA: He came to Delhi on the same day after obtaining the bail.

SHRI BASU DEB ACHARIA : He flew to New York and thereafter led a luxurious life in New York.... (*Interruptions*)

SHRI SRIKANT JENA: I was stating the facts available to me, supplied to me by different Departments of the Government. I am stating the facts.

By the Order of 15th January, 1989 all criminal proceedings relating to or arising out of Bhopal Gas Leak Disaster were watched by the Supreme Court. However, the said Order was reviewed by the Supreme Court on 3rd October, 1991 and the criminal proceedings were restored. Anderson did not appear before the court subsequently and wilfully jumped bail and violated the bail conditions. Warren Anderson was accused no.1 in the criminal case no.8460 by 1996 in the court of CGM Bhopal and a non-bailable warrant of arrest was issued by CGM Bhopal on 10.4.92 against Anderson and was declared absconder and the trial was bifurcated. The story is simple. He obtained the bail and ultimately he is absconding.

The CBI initiated extradition proceedings in September 1993. The issue remained in correspondence between CBI and MEA until 2001. Meanwhile, legal advice was obtained from the US Law Firm and from the Attorney-General of India. I will not quote the opinion of the Attorney-General. It has already been quoted. Accordingly, a request for extradition was sent on 5.5.2003 requesting that Anderson be extradited to stand trial for offences under Sections 304 part (2), 324, 326 and 429 read with Section 35 of IPC. The US rejected the request on the ground of not meeting the requirement of dual criminality.

Now, the Government of India has taken a decision. I am upgrading the situation as taken by the Cabinet. The Cabinet took this decision. The CBI was asked to frame the charges. The Ministry of External Affairs and the Ministry of Law are in consultation. The Extradition Treaty between US and India is taken into consideration.

The CBI has already brought out the charges which will comply to the US-India Extradition Treaty so that Mr. Anderson can be extradited. Now this is being processed after the decision of the Cabinet in this regard. I am sure this will take very shortly to bring him back. We are trying our best.

The other issue was raised regarding the liability of Dow Chemicals. Dow Chemicals has taken over this Company subsequently. The Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India has filed a writ petition No.2802 of 2004 before the High Court of Jabalpur, Madhya Pradesh, praying that the respondents 4, 5 and 6, namely, Dow Chemicals Company, USA, the Union Carbide Corporation and Eveready Industries India Limited should be directed to deposit an amount of Rs.100 crore. At that time, it was Rs.100 and now we have said that it should be Rs.310 crore. Recently, the Department has filed the petition for advance for environmental remediation of the UCIL Plant.

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह 90,000 करोड़ कह रहे थे, आप 310 करोड़ रुपए कह रहे हैं।

श्री श्रीकांत जैना: रेमिडिएशन के लिए जो एस्टीमेट आया है, after consulting the technical experts, it was decided that Rs.310 crore will be required. This petition has already been filed before the High Court of Jabalpur. So, we are chasing the Dow Chemicals. It is not that we are not chasing them. We have no soft corner for the Dow Chemicals and they have to be scrutinized. Recently, they applied for three permissions from the Ministry of Agriculture concerning pesticides. As the CBI has filed a charge sheet, the process of clearing those licences is stopped. On the basis of this, already a show cause notice has been issued to Dow Chemicals.

Sushmaji must be knowing that a Gujarat Government's PSU called Gujarat Alkalies and Chemicals Limited has signed an MoU with Dow Chemicals

and now they are working together. We are trying our best to pursue this issue. The Cabinet has directed the Department of Chemicals and Petrochemicals to pursue this case before the High Court of Madhya Pradesh so that the liability could be fixed. It is not that nobody would be liable. The Law Minister has already stated publicly that the liability cannot go to the thin air. When there is an agreement between the UCIL and the Dow Chemicals, the liability of UCIL has to be borne by somebody. In the meantime, the Government of India has decided that since the determination by court will take some time and we need money for remediation, the money is being sanctioned and Rs.310 crore are being given by the Government of India to the Government of Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh Government has been asked to take charge and they have agreed for that... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you address the Chair. How much more time do you require?

SHRI SRIKANT JENA: Sir, the High Court of Madhya Pradesh had set up a Task Force under the Secretary, Department of Chemicals and Petro-Chemicals in the year 2005 for overseeing the rendition activities. Out of 390 MTs of stored toxic wastes lying in UCIL, 40 MTs of lime sludge has been disposed of in the treatment, storage and disposal facilities at Pithampur in June, 2008.

श्रीमती सुषमा स्वराज  : मत करो यह काम।

श्री श्रीकांत जेना: यह हो चुका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक काम तो किया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मत करो यह काम। प्रीतमपुरा में बहुत थोड़ा रसायन गया है और अभी से वहां हाय-तौबा मच गयी है। बार-बार लोग कह रहे हैं कि दूसरा भोपाल घटेगा। भेज दो अमरीका वापिस, उन्हीं के यहां जाकर कचरा जमा होने दो। जहाज में भरकर भेज दो।

SHRI SRIKANT JENA: It is one of the most important issues. It was decided that this will be incinerated at Ankleswar in Gujarat... *(Interruptions)* बसुदेव जी, यह बड़ा

महत्व का सवाल है कि जो टॉक्सिक वेस्ट यूनियन कार्बाइड की साइट पर पड़ा है, जब तक उसे जलाया नहीं जाता है, तब तक यह चलता रहेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। इसे अमरीका भेजो।

SHRI SRIKANT JENA: The Gujarat Government also accepted that. Then, subsequently, the Gujarat Government came before the Supreme Court saying that they have a lot of toxic waste and this incinerator is not sufficient. Therefore, it should be वहां नहीं लेना चाहिए। It has to be incinerated. It is not a very high grade technology this incineration cannot be done. There are many countries where incinerators are being owned publicly and privately as well. The incinerator in Pithampur maintains all standards and those have been certified by the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board as well. Therefore, a situation should not be created whereby it looks as if something wrong is going to happen. It is not so. Such wastes across the world are being incinerated and this waste also has to be incinerated, if not, at Ankleswar, then at some other place. This is a project of the Madhya Pradesh Government. The Government of India has contributed some money in that. Therefore, it can be incinerated and the process is on and whatever is required for that it is being done.

There was a hue and cry raised about the 40 tonnes of lime sludge being incinerated. Two years back there was a review and the review was satisfactorily conducted by an agency, namely, NEERI and also by the State Government. Ultimately, the State Government was satisfied that there was absolutely no contamination around the facilities at Pithampur also.

Sir, there were issues also raised about alleged contamination of ground water of wells and tube-wells in villages at Tarapur situated at around 500 metres away from the Shikor landfill at Pithampur. The State Government of Madhya Pradesh has reported that Madhya Pradesh Waste Management Project which is a division of the Ramky Environment Engineering Limited has developed this site at Pithampur, Indore for the purpose of disposal of toxic wastes. By developing this

disposal site all the relevant technical and scientific aspects have been duly taken care of in order to ensure that the waste deposited in the landfill did not leak or seep into the ground water causing contamination. The Shikor Landfill site has been constructed in accordance with the guidelines of the Central Pollution Control Board and by applying the latest technological design wherein the floors and walls of the landfill have been secured with prescribed standardized SDPL liners, in addition collection systems has also been installed.

In view of those two provisions, the likelihood of contamination of ground water becomes zero. A public hearing has been held in connection with the landfill site in Pithampur. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, how much time do you require further?

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I would complete it in hardly two to three minutes. Therefore, we should not create any apprehension that I am coming from a State and hence, that site should not be used. We can prove this. Sushma Ji, you may bring any technical team. The State Government and the Central Government agencies will see to it and we will convince the people and the villages around the Pithampur site that this incinerator is not going to harm anybody. ... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, सवाल नई तकनीक का नहीं है। जिन्होंने कचरा डाला है, वे अपने कचरे को अपने देश में ले जाएं। हमारे देश में कचरा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। पीतमपुरा में कचरा नष्ट नहीं किया जाएगा। कचरे को अमरीका भेजा जाए। अगर भोपाल से बंद कन्टेनर में कचरा जा सकता है, तो वह कचरा अमरीका भी भेजा जा सकता है। ... (*Interruptions*)

SHRI SRIKANT JENA: I will come to the most important issue which is about the taking over of BMHRC, the Super Speciality Hospital. That hospital has been taken over by the Government of India. We have filed a petition before the Supreme Court. The Supreme Court has accepted it and the Government of India has already taken over that Hospital. Therefore, I would summarise.

The Government of India has taken a serious view on the health issue, the remediation issue, the legal issue and the compensation issue. The Cabinet took

the decision regarding the extradition of Mr. Warren Anderson converting Section 304 A to Section 304-II and other legal aspects which could have been taken after the 1996 decision of the Supreme Court.... *(Interruptions)*

SHRI YASHWANT SINHA : You have been in office for 16 long years after 1984 and you are trying to put everything on those six years that we were in office. This is what you are doing now. All the time you are saying not to politicise the matter. It does not behove of you, Mr. Jena. Do not forget that you were sitting here with us at one time. Now that you have gone to the Congress, do not speak like this. ... *(Interruptions)*

SHRI SRIKANT JENA: You also left and joined BJP. ... *(Interruptions)*

SHRI YASHWANT SINHA : How did Anderson travel to Delhi from Bhopal? ... *(Interruptions)*

श्री श्रीकांत जेना : आप मेरी बात तो सुन लीजिए!...*(व्यवधान)*

Shri Yashwant Sinha, I have greatest regard and respect for you. ... *(Interruptions)* You have no patience to listen. ... *(Interruptions)* If you have made up your mind to walk out, then it is a different matter altogether. But you should have the minimum courtesy to listen. ... *(Interruptions)* Why do you not listen? ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take  your seats.

... *(Interruptions)*

SHRI SRIKANT JENA: Shri Yashwant Sinha is a very senior Member. I have personal respect and regard for him. He has every right to ask any question or clarification. He commented that I was on the other side and now I am with Congress. But I have not changed the destination. In politics, the philosophy cannot be changed, but he has changed the philosophy and that is the whole worry. I have not changed the philosophy. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: Shri Jena, have you finished?

... (Interruptions)

SHRI SRIKANT JENA: Ultimately, the extradition of Warren Anderson is the subject matter. *... (Interruptions)* I conclude by saying that, as has been mentioned by Shri Mulayam Singh Yadav, if the compensation does not reach the right people, if anybody is left out, then it should be taken very seriously. I am all with you. If you bring this issue about anyone who is affected, I am sure we will certainly look into that. *... (Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister to take the floor.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Except Home Minister's reply nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: I have already called the Home Minister.

... (Interruptions)

* Not recorded.


THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Shrimati Sumitra Mahajan, I have understood your problem and I have understood your anguish and I will answer that.

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : With the consent of the House, we can extend the time of the House till the Minister's reply.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We will take up 'Zero Hour' afterwards.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Mr. Chairman, Sir we have had a long debate. As usual, some parts of the debate were acrimonious, but that was to be expected. I was hoping that 25 years later we can all look back with a deep sense of regret and, if I may say with respect, with a sense of guilt that we did not address the grave issue in the manner it should have been addressed in 1984. At the end of this debate and at the end of my reply, I can ask all the hon. Members of this House that we must send the message to the victims of the Bhopal Gas Tragedy that we share your grief, we share your sorrow and we acknowledge that and we do so with a sense of guilt that successive Governments and successive Lok Sabhas did not address this issue with a seriousness with which it should have been addressed.

A number of people have died. A total of 5,295, a number which my friend gave is a number certified by the Welfare Commissioners as having died for the proximate cause was a leakage of the gas. That does not mean that more people did not die. I will be the first one to admit that more people died. All that my learned friend was saying is that Commissioners said that the proximate cause of death being the gas applied only to 5,295. The Commissioners may be right and the Commissioners may be wrong. In fact, I am inclined to think the Commissioners may have been wrong in that matter. A total of 10,000 others died. They were treated as injury cases.

Sir, hindsight, of course, makes us all wiser. We are looking at the matter 25 years behind. But let me remind you of the famous couplet:

“The moving finger writes and having written moves on not all your tears wash out the verdict”.

All that happened which was right is right, all that happened which was wrong is wrong. Nothing that we do, nothing that we say can wipe out a word of it. All that we can do now is to set right things which went wrong to the best of our abilities. When I chaired the GoM that was my approach. I told the hon. Prime Minister that 25 years later, we can perhaps set right some things, and we cannot set right some other things. But I will in four days give you a report so that we can try to do things which we ought to have done earlier, but we failed to do so. But let us make a sincere attempt now.

I can certainly understand the anguish of the Leader of the Opposition. If in the course of her speech, she did become, to some extent, polemical even that I understand. The business of the Opposition is to expose the Government. Therefore, if she had pointed fingers at the Government of the day, I have no quarrel. All I am pointing out is that we are sitting in the Fifteenth Lok Sabha. The law was passed in the Eighth Lok Sabha. Most of the judgments were delivered when the Ninth Lok Sabha was sitting. Most of the remedial action could have been taken in the Tenth Lok Sabha. One grave judgment was delivered when the Eleventh Lok Sabha was sitting. Many of the legal issues could have been addressed in the Twelfth and Thirteenth Lok Sabhas.

We are now in the Fifteenth Lok Sabha. Therefore, while the hindsight makes us wiser, since many of us were Members of those Lok Sabhas also, I think we should approach the matter with a certain sense of humility that we have made mistakes and let us try to correct the mistakes to the extent possible.




My friend has explained how the compensation issues were decided. In fact, neither the Government of India nor the Government of Madhya Pradesh – of whichever political party – had anything to do with the compensation issues. The compensation issues were decided in the judgements of 15th February, 1989; 4th May, 1989 and 3rd October, 1991. Today, after 20 years, we have asked the Attorney-General to examine whether a Curative Petition can be filed to reopen the compensation. We take support from one paragraph of Justice Pathak's judgement where the Judge said: "Those who have a sense of injustice will find justice at our door." Whether we again say with humility that what we are doing 20 years later could have been done all these years! We did not. So, until that matter is reopened, if it is reopened and until that matter is re-decided, if it is re-decided, we have to accept the fact that the Union Carbide was saddled only with the compensation of 470 million. But the same court said: "If additional compensation has to be paid, it must be borne by the Central Government." We are not running away from that liability. We accepted the liability willingly as a liability we have to bear for the people who suffered in Bhopal.

Guidelines of how this compensation should be distributed and to whom it should be distributed were laid down following certain observations of the Supreme court on 13th April, 1992 and 8th September, 1992. That was the time of the Tenth Lok Sabha.

A sitting High Court Judge was the Welfare Commissioner. District Judges were appointed Deputy Welfare Commissioners and Civil Judges were appointed Authorities of the First Instance. Every single case – I would appeal to Shri Mulayam Singh Yadav to bear with me – went through this process – the Civil Judge, the District Judge and the High Court Judge. No Government had anything to do with deciding who will get what compensation. The categorisation was made by the Judges; the compensation was decided by the Judges. In fact, the Judges gave an average compensation of Rs.1.03 lakh in the case of death and in the case of injuries, it ranged from Rs. 1 lakh to Rs.8 lakh. Subsequently, due to the

exchange rate variation and interest, more money was available. Therefore, the Government decided on a 1:1 additional payment. If someone has got Rs. 1.03 lakh, he got another Rs. 1.03 lakh. If somebody got Rs.2 lakh, he got another Rs. 2 lakh. That is how, we initially distributed Rs. 1,548 crore and, on a 1:1 basis, we have set apart Rs.1,548 crore out of which Rs.1,509 crore has already been distributed. And, 11,745 persons who got the first instalment have not come forward to claim the second instalment but the money is available. If they come, even that money will be given to them.... (*Interruptions*) It has all been publicized. Therefore, in these cases, before the Cabinet decision, a person got an average of Rs.2.06 lakh; the injury cases got compensation according to the Award.

The average compensation paid originally in the injury cases was Rs. 25,145 plus an additional amount of Rs. 25,145, totally Rs. 50,290. We have now given an additional *ex gratia* amount and my learned friend has already read out the amounts to you. In the case of death it will be Rs. 10 lakh, in the case of permanent disability it is Rs. 5 lakh, in cancer cases it is Rs. 2 lakh, in the case of total renal failure it is Rs. 2 lakh, in the case of temporary disability it is  Rs. 1 lakh. This recommendation was made by the Government of Madhya Pradesh, which was represented by my good friend, a senior political leader Shri Babulal Gaur and this is a unanimous recommendation including this recommendation. ... (*Interruptions*) I chaired it, I know and I have got the minutes. The Cabinet has accepted it without changing a comma or a full stop.

Now, in 1985 when the Bill was debated, when the scheme was placed before Parliament, when the compensation judgements came between 1989 and 1991, when the guidelines for distribution of compensation were made in April, 1992 and September, 1992, when the categorization was made by the Welfare Commissioners between November, 1992 and October, 2003 – they took 11 long years to deal with each claim – when all this happened, it occurred to nobody, it occurred to no Government in place at that time, it occurred to no one in the Lok Sabha at that time that we should go and revisit all these decisions and reopen all

these decisions. That is why I said, let us close this debate by sending a message to the people, 'yes, mistakes were made; we are trying to correct the mistakes.'

Sir, now let me turn to the liabilities. The original FIR mentioned the charges under Section 304 (A). Subsequently, charges were framed. But kindly remember that charges were framed only against the accused other than Warren Anderson, A10 and A11 because the cases were bifurcated. Warren Anderson, A10 and A11 did not appear before the court, they were declared absconders and the cases were bifurcated. The case was against Keshub Mahindra and others. The charges were framed under Section 304 Part-II, under grave section of the IPC, read with Section 35 of the IPC. That is the case which went to the Supreme Court. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Mr. Home Minister, will you please yield for a minute?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : आपने यह कहा कि वॉरेन एंडरसन के खिलाफ चार्जिस नहीं बने।

SHRI P. CHIDAMBARAM: 'Bifurcated', I said.

श्रीमती सुषमा स्वराज : दो, तीन, चार, पांच उनके खिलाफ बने, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं बने, क्योंकि इंडियन लॉ यह कहता है कि चार्जिस सुनने के लिए एक्ज्यूज्ड को कोर्ट में खड़े होना जरूरी है। चूंकि वह अपीयर नहीं हुआ, इसलिए उसके खिलाफ चार्जिस नहीं बने। इसलिए नहीं बने कि केस उसके खिलाफ नहीं था, इसलिए नहीं बने कि वह अपराधी नहीं था, यही स्कीम ऑफ थिंग्स क्वात्रोची के केस में इस्तेमाल की गई, उसे भगा दिया गया, वह अपीयर नहीं हुआ, इसलिए चार्जिस फ्रेम नहीं हुए। Don't mislead the House. Tell the House that charges were not framed against Anderson because he could not appear in the court and he could not appear in the court because he was flown away to America. ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the FIR was filed on 3.12.1984; charges were framed against all the accused on 30.11.1987 under Sections 304 Part-II, 324, 326, 429 read with Section 35 of the Indian Penal Code; on 1.12.1987 summons were issued to Warren Anderson and others; on 15.11.1988 a bailable warrant was

issued against Warren Anderson; on 1.1.1992 a proclamation was published in a US newspaper, an order of attachment was issued and on 10.4.1992 a non-bailable warrant was issued. These proceedings culminated in Warren Anderson, A10 and A11 being declared as absconders. The case, therefore, proceeded against the other accused.

That is the case which went to the Supreme Court.

I think there is a bit of lack of understanding of what went to the Supreme Court. The case that went to the Supreme Court was not the case and Warren Anderson was not a petitioner, A10 and A11 were not petitioners, Keshav Mahindra and others went. That case, and what I say will be some bearing when I come to another issue a little later, was decided by a Bench consisting of Justice Ahamadi. Justice Ahamadi pronounced the judgement where he quashed the charges there and said, 'try them under 304(A).

What is the conclusion? The conclusion is charges were quashed only in respect of Keshav Mahindra and others. Charge was not quashed for Warren Anderson in A10 and A11. That charge still remains and there is a story behind it. If the Leader of Opposition will bear with me, there is a story to that. The charges were quashed only vis-à-vis Keshav Mahindra and other accused, the charge against Warren Anderson and A10 and A11 were not quashed because they were not part of that petition before the Supreme Court.

The question of extraditing Warren Anderson came up. The CBI sent its proposal to the Government in September 1993. It was being examined in the Government, tossed up and down until 2001. So, none of us escaped liability, between 1993 to 2001... (*Interruptions*) Everybody. But that time, the CBI said, "we must seek extradition for the graver charges of 304 (II), 324, 326 and 429".

The Government of the day in April 2001 obtained the opinion of a US Law Firm which said, "The extradition request is misconceived, no charge can be sustained under these grave sections and therefore, the extradition will not find favour with the US Government". The Government of the day sought the opinion

of the learned Attorney General of the day, who also said, “The charges cannot be sustained under the graver sections”.

The External Affairs Minister of the day submitted a note to the Prime Minister and the Prime Minister asked the Law Minister to examine it. The Law Minister said that the graver charges could not be sustained. Therefore, if at all it can only be under 304 (A), let me point out that this conclusion of the Government of the day was based upon a misconception that the judgement in Keshav Mahindra applies to Warren Anderson. Warren Anderson was not a petitioner before the Supreme Court. Assuming the judgement in Keshav Mahindra is right, even if it is right, it did not apply to Warren Anderson.

But let me compliment the CBI, which is often ridiculed as it was ridiculed this morning. The CBI stood its ground and said, “nothing doing, our request for extradition will be under 304 (II)”. This is perhaps one of the reasons why they do not like the CBI.

I did not bring Sohrabuddin. The Leader of Opposition brought Sohrabuddin and I am obliged to answer... (*Interruptions*) I will answer them on Sohrabuddin... (*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD : Who raised Sohrabuddin?... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: She raised Sohrabuddin... (*Interruptions*) She mentioned Sohrabuddin... (*Interruptions*) I will answer them on Sohrabuddin today... (*Interruptions*) I did not raise Sohrabuddin... (*Interruptions*) Despite the view taken by the US Law Firm, the then Attorney General and the then Law Minister, CBI stood its ground and said, “we have to seek extradition for 304 (II)”.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: CBI put it down during NDA regime; it was May 2003. It was our Government.... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: All I said was that CBI, which you ridicule, which you criticize, did not accept the opinion of your Ministers and stood the ground and said it must be under 304 (II) ... (*Interruptions*) CBI is neither under your Government, nor under my Government. CBI, in the judgement of the Supreme

Court, is under the CVC and independently reports only to the CVC. But the Leader of the Opposition brought Sohrabuddin and if the House agrees let me reply on Sohrabuddin. ... *(Interruptions)* I did not bring Sohrabuddin; you brought Sohrabuddin. Since she brought Sohrabuddin, let me answer Sohrabuddin. ... *(Interruptions)* Sohrabuddin's case was originally investigated by the Gujarat Police. ... *(Interruptions)*

You cannot try to interrupt me. You brought up Sohrabuddin; you will have to hear me on Sohrabuddin.... *(Interruptions)* Please hear me.... *(Interruptions)*

Sir, I did not tell the Leader of the Opposition what she should speak. She should not try to tell me what I should speak.... *(Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : You said CBI put it down. I am only asking you to tell the year. It was May 2003.... *(Interruptions)*

SHRI P. CHIDAMBARAM: I said so. ... *(Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : During the NDA regime, CBI put it down.... *(Interruptions)*

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sohrabuddin case was originally investigated in 2005. In 2005, Sohrabuddin case was originally investigated by the Gujarat police. The Gujarat Government transferred the case from the regular police to the CID of Gujarat Police in 2006. The case was investigated by the CID of Gujarat Police from 2006 to December 2009. During that period, the Gujarat CID, the Gujarat Police arrested 14 people on the ground that the killing of Sohrabuddin was a fake encounter; 14 people were arrested by the Gujarat police. ... *(Interruptions)* Please listen to me. Therefore, to argue today that Sohrabuddin was not killed in a fake encounter goes against the case of the Gujarat Government itself. Whether a man is a good man or a bad man, under the law of this country, nobody can be killed in a fake encounter. ... *(Interruptions)*

SHRI YASHWANT SINHA : What about Azad? Why was he killed?... *(Interruptions)*

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am answering. I know you will raise it, and I will answer. ... (*Interruptions*) Sit down. I know you will raise it. ... (*Interruptions*) I am answering Yashwant ji. I am going to answer Azad. Please sit down. I am answering that also.

Therefore, Sir, it is the Gujarat Police which admitted that it was a fake encounter and arrested 14 people. Then the matter was taken to the Supreme Court by a member of the family of Sohrabuddin. Supreme Court by an order, if I recall right, dated 16th of January, 2010 – I am speaking from memory – said the case should be transferred to the CBI. The case did not go to the CBI at the instance of the Government of India; the case went to the CBI at the instance of the Supreme Court of India. So when you say that the case was handed over to the CBI and the CBI is a bad agency and the CBI will not investigate, you are not criticising or pointing a finger at the Government of India, you are pointing a finger at the Supreme Court of India.

After the CBI took over the case, a charge-sheet was registered on the 1st of February, 2010 and then the CBI arrested the 15th person, Ajay Chudasama. The 15th person was arrested by CBI; 14 persons had earlier been arrested by the Gujarat Police. Now to stand up and say that Sohrabuddin is not a fake encounter, that nobody is responsible for the killing of Sohrabuddin, nobody knew who killed Sohrabuddin, this is the most outrageous attack on the judiciary of this country and the most outrageous attack on the premier investigating agency of this country.

Now you ask me about Azad.

SHRI YASHWANT SINHA : Has the CBI proceeded against the Andhra Police?... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down; I will answer.... (*Interruptions*)

Why do you not sit down? Let me answer.... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Why has not the CBI proceeded against Andhra Police?... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Why is he jumping up? Let me answer about Azad. I am not running away.

Sir, the worst allegation that has been made is that Azad, who was reportedly killed in an encounter, was not killed in an encounter and that it was a fake encounter along with another person staged by the Andhra Pradesh Police. That is the allegation made. But Azad is a good man or a bad man, it is not for me to judge. ... (*Interruptions*) Just a moment. Let me answer. You want an answer. ... (*Interruptions*) He raised Azad and I am answering him. Whether Azad is a good man or a bad man, I am not here to judge. But Azad is a suspect and is an accused in many cases of Andhra Pradesh. That does not mean he has no right to life. That does not mean that you can kill him in a fake encounter. Azad is involved in several murder cases, according to the Andhra Pradesh Police. The death of the former Speaker of Andhra Pradesh, Shri Sripad Rao; the former Home Minister of Andhra Pradesh, Shri Madhava Reddy; the attempted assassination of Shri Chandrababu Naidu and the attempted assassination of Shri Janardhan Reddy – these are all cases in which his name is coming up, according to the Andhra Pradesh Police, not according to me. According to the Andhra Pradesh Police, he was killed in an encounter.

The allegation being made is that it is a fake encounter. On that, when someone met me and said that an inquiry must be held, I said: “Yes. Of course, I will ask the Andhra Government because the encounter was in Andhra Pradesh.” There is no allegation against anyone of the Government of India. So, I said: “You please go and meet the Andhra Pradesh Government. If they want to order an inquiry, they are welcome to order an inquiry.” In fact, they have met the Home Minister of Andhra Pradesh, and according to newspaper reports, she has promised an inquiry. I am the first person to say, the day I took over as Home Minister I said: “If a Central agency arrests a person, he shall be produced before a court in 24 hours and no fake encounter shall be staged in respect of any Central agency’s arrest.” ... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : One of your colleagues has alleged – the Railway Minister has alleged – that Azad was killed. ... (*Interruptions*) She demanded a judicial inquiry. You respond to that. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the Minister's reply.

(*Interruptions*) ... *

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. I will answer. ... (*Interruptions*)

Sir, all political parties represented in this House are also in the Andhra Pradesh House. The CPI is there; the CPI (M) is there; the Telugu Desam is there; the Congress Party is there; the BJP is there. I think, the BJP was there and not there. Now you have got one MLA in the Assembly. You raise it in the Andhra Pradesh House; pass a Resolution; ask for an inquiry; hold an inquiry; go to the court and ask for an inquiry. I will give you all the resources at my command to help you hold an inquiry. Get an inquiry done. I have no problem. ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Why do you not order an inquiry? ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: How can I order? Under what law? ... (*Interruptions*) Just a moment. Let me ask my most distinguished non-lawyer friend, under what law do I order an inquiry. Tell me. ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Your colleague has said that it was a murder. Therefore, you should order an inquiry. ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. I will answer. What I am asking my non-lawyer friends is this. Under what law, do I order an inquiry? If it is a fake encounter, it is a crime. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not make any comments.

SHRI P. CHIDAMBARAM: If it is a fake encounter, it is a crime; a crime committed in Andhra Pradesh. Under List II, Police, law and order crime is a State subject. Under what law, does the Central Government order an inquiry into an

* Not recorded.

offence committed in Andhra Pradesh? He may not have an answer today. ...
(*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : I am not a lawyer. ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: That is precisely I am saying. You take my word. You go to the Andhra Pradesh High Court with a petition asking for CBI inquiry. Why can your Party not do that? ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : No, you can do that. ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Why should I do that? I am not making any allegation. ... (*Interruptions*)

... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : You are not carrying any responsibility!...
(*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, Mr. Yashwant Sinha... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : You are talking also like Mr. Gill... (*Interruptions*)
He was talking yesterday: “Why do you not proceed under the Right to Information Act?”... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Banerjee, please take your seat... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am not making any allegations about this incident. During the same period, a number of CPM Maosits had been arrested. During the same period, a number of Maoist leaders had been arrested and produced before the court... (*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD : You are diverting from the main issue... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: During the same period, 142 people... (*Interruptions*)
She raised about Sohrabuddin; he raised about Azad... (*Interruptions*)

You raised this issue. You will get an answer... (*Interruptions*)

Please sit down, Kirti... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the reply of the hon. Home Minister.

*(Interruptions) ...**

SHRI P. CHIDAMBARAM: The most notable contribution made by the Government of the day in 2001 was to somehow derail the extradition proceedings. Fortunately, that effort failed. The extradition proceeding was, indeed, filed on 5/5/2003 by the MEA and those petitions are now being pursued by giving additional information, additional evidence, which is now available in the trial court. That acknowledges it 5/5/2003.

Sir, now, we deal with one subject of toxic wastes. About toxic wastes, we have found, based on the Report of Nivee, NRGI, NGRI and IICT, that there are different kinds of toxic wastes on this site. It appears that this plant was dumping toxic wastes long before this gas tragedy occurred. It is estimated that there are 1.1 million tonnes of contaminated soil; 1 metric tonnes of mercury spillage; 1,500 metric tonnes of corroded plant; 150 metric tonnes of underground dumps; and then, 350 metric tonnes of stored hazardous residues including TARI residues.

Much of this predates 1984. Now, although this tragedy occurred in 1984, not until 2008 were these agencies commissioned to give a report. These agencies were commissioned to give a report in 2008, and that after, the High Court of Madhya Pradesh directed that some agency should be asked to give a report. Second, there is accumulative negligence over several years. These reports have now come on the 30th of June, 2010.

It was agreed in the GoM by the Government of Madhya Pradesh, and this was approved by the Cabinet, that the responsibility of remediation will be entrusted to the Government of Madhya Pradesh. The Government of Madhya Pradesh will suitably empower the Department of Gas Tragedy Relief and Rehabilitation. They will grant enhanced financial powers so that remediation and environmental cleanup are completed in a time bound manner. An Oversight Committee will be established at the level of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests with the Minister in the Government of India

* Not recorded.

as the Chair and the Minister of the Government of Madhya Pradesh as the Co-Chair. That Oversight Committee has since been notified by the Ministry of Environment and Forests.

It is the Government of Madhya Pradesh and the Oversight Committee, which have to work out the remediation processes. Let me assure the hon. Members that we are completely open to any suggestions of how remediation should take place. We are not dogmatic; we are not inflexible in this.

We want remediation to take place. We want this toxic waste to be incinerated or removed or destroyed in a manner that they are fully incinerated or destroyed in a manner that they do not cause further environmental hazard and in a manner that they do not harm public health. The matter is entirely in the hands of the Government of Madhya Pradesh subject to the Oversight Committee, and I say on behalf of the Government of India we are willing to work fully in close cooperation with the Government of Madhya Pradesh.

Sir, I come to the end of my reply. We have addressed to the best of our ability compensation issues. We have addressed to the best of our ability the legal issues. A curative petition will be filed. It is almost ready to be filed, and we have addressed to the best of our ability remediation measures. There will still be issues which linger on, issues relating to the health of the people and medical care for them.

Now, again over the last several years we have allowed the Bhopal Memorial Hospital Trust to decline, and their many services were stopped. One of the first thing we did was, ask the Supreme Court to discharge the responsibility of the Trust and hand over the hospital to the Government of India, which the Supreme Court has now passed orders that we can take over the hospital. The hospital will be taken over and run by the Department of Atomic Energy and the Department of Health.

Fortunately, there is a corpus of Rs.436 crore in this hospital. Financial projections made for the next five years show there will be a deficit every year.

Many Departments are non-functional. Salaries are lower than salaries paid by the Government of Madhya Pradesh to its doctors. Many posts are vacant. All this will be addressed in a time bound manner, and I assure you, as the Chair of the GoM, the GoM will supervise that these things are implemented in a time bound manner.

The ICMR had established a Research Centre in Bhopal in 1984 to conduct epidemiological and clinical studies. They published some papers in 1987 and 1994. But then the ICMR stopped its work on 31.12.1994. Again, there is accumulated neglect for about 15 years. We have now directed the ICMR to set up a full-fledged Research Centre in the place and this centre will now do research in respiratory diseases, eye-related diseases, cancer, total renal failure, genetic disorder, congenital disorder, women-related medical issues and second generation children related medical issues.

We have also directed that the Research Centre will be set up and commissioned within 90 days of the Government's decision. An Empowered Committee with the Chairmanship of the Secretary, Department of Health is being set up. All the victims of Bhopal gas tragedy, the family members of the dead, injured, seriously injured, disabled, renal failure, cancer, have got identity cards. That job has been done very well by the Government of Madhya Pradesh. All of them, for the rest of their lives and for all ailments, all diseases, are given free medical treatment in the BMHT Hospital, in the six ancillary hospitals, nine day care centres, three Unani hospitals, three Homeopathy dispensaries and three Ayurveda dispensaries. All of them will get complete free medical care all through their lives and their children will get free medical care. All those who have been identified will get free medical care.

Let me also say this with some trepidation because I do not have the full authority. If we find that there are cases which have not been compensated, if some cases do come up, if the commissioners are persuaded to look into the matter if compensation can be given, I assure you we will be able to find the money. We will give them compensation, if any such cases come up.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Why is there a wide variation in the figure?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have answered it.

Therefore, let me conclude by saying I did not wish to be polemical; I did not wish to be partisan but I was forced to answer a charge against the CBI bringing in Sohrabuddin and then bringing in Azad. But please let us keep that as a separate narrative.

The main narrative on which I want to emphasize is, all of us must approach this over the next 5-10 years with a spirit of humility and with a sense of guilt.

We have not done all that Governments and Parliament should do. But let us, beginning today, address issues in a spirit of cooperation and non-partisanship.

SHRI BASU DEB ACHARIA : How Mr. Warren Anderson was allowed to escape? Who provided the aircraft?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have just been informed that Shri Arjun Singh, intervening in a debate in the Rajya Sabha, has made a speech. Let me get a copy of that and answer it if necessary. You will also get a copy of it.

SHRI BASU DEB ACHARIA : You do not have the information. We are walking out.

18.41 hrs

*At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other
hon. Members left the House*

MR. CHAIRMAN : Now Zero hour. Shri Ratan Singh.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे राजस्थान राज्य में पेयजल के निदान के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग उठाने के बारे में समय दिया। राज्य को आवंटित सभी जल संसाधनों का समुचित व लाभकारी उपयोग हो, इस दिशा में यमुना जल, सतलुज और व्यास जल की परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन आवश्यक है। साथ ही कुशल जल प्रबंधन के लिए दावित सिंचाई पद्धति को अपनाना, नहरी व्यवस्था का सुदृढीकरण, पाइप लाइनों में जल छीजक को कम करना, री-साइकलिंग द्वारा जल शुद्धिकरण, जल का कृषि व बागवानी कार्यों में उपयोग तथा वर्षा के जल का संरक्षण सम्मिलित किया जाना चाहिए।

वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 49,747.20 करोड़ रुपये लागत की 83 महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें जल संरक्षण, जल छीजक कम करना, जल शुद्धिकरण व वर्षा के जल का संरक्षण कर जल प्रबंधन की दिशा में जल की एक-एक बूंद का उपयोग करना शामिल है। ...(व्यवधान) राज्य के समुचित विकास के लिए स्वच्छ पीने योग्य जल की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार के सीमित साधनों व धन स्रोतों को देखते हुए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान किया जाना नितांत जरूरी है, ताकि वर्तमान में चालू की गयी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चालू रखा जा सके तथा श्रद्धेय स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी के भारत निर्माण के सपने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके लिए वर्तमान में 10 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की विशेष वित्तीय सहायता जारी कर कुल 50 हजार करोड़ रुपये की राशि पांच वर्ष में राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जमीनी हकीकत को समझते हुए तथा राज्य की सामाजिक आपदा को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विशेष सहायता, धनराशि उपलब्ध कराकर जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करे, जिससे राजस्थान वासियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): सभापति महोदय, आपने मुझे रावेर संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मामला उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा रावेर लोक सभा मतदान संघ महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में है जहां से पूरे देश को केला सप्लाई होता है। हर रोज पांच हजार मीट्रिक टन केला नार्थ इंडिया में आता है जिसमें सब राज्य हैं। दो महीने से वहां के केला उत्पादक किसान और व्यापारी परेशान हैं, जिसका कारण हैल्थ मिनिस्ट्री का एक कायदा है।

हैल्थ मिनिस्ट्री के एफडीए डिपार्टमेंट ने पीएफए एक्ट के अनुसार बनाना राइपेनिंग करने वाले सभी व्यापारियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करना शुरू किया है। उनके सभी गोडाउन्स सील किए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके पश्चात् व्यापारियों ने केले की खरीद बंद कर दी है। बनाना एक पेरिशेबल फ्रूट है, करोड़ों रूपए का बनाना आज किसानों के खेतों में खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए। इस एक्ट के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड यूज करने पर बैन है, लेकिन हमारे व्यापारी एथिलीन और एथिफॉ यूज करते हैं जिन पर कोई बैन नहीं है। केन्द्र सरकार के ही कृषि मंत्रालय के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 28 तारीख को एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि एथिलीन और एथिफॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन हैल्थ मिनिस्ट्री के एफडीए के अधिकारी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हैल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों को इसकी सूचना मिलनी चाहिए और जो व्यापारी केले की प्राधिकृत (ऑथराइज्ड) राइपेनिंग करते हैं, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसे बंद करना चाहिए, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गयी है, उसे वापस लेना चाहिए, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको छोड़ देना चाहिए। यही मेरी मांग है।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, चार जुलाई को हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक अत्यंत दुखद घटना घटी। वहां रामगढ़ जिले में मां छिन्मस्तिका का एक बहुत ही पवित्र मंदिर है, जो एक सिद्धपीठ भी माना जाता है। चार जुलाई की रात को वहां कुछ शरारती तत्व मंदिर के अंदर घुस गए और उन्होंने मां के मंदिर, मां की प्रतिमा को तोड़ा, वहां जो बहुमूल्य सामान थे, उनको चुराया। एक बहुत शर्मनाक घटना वहां पर घटी। खुशी की बात यह है कि दोनों समुदायों के लोगों ने इसके बाद आंदोलन किया कि उन शरारती तत्वों को पकड़ा जाए। आज के दिन मैं इस सदन में यही बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हम लोगों ने कुछ दिनों बाद इस बात की मांग की थी, कि जिला पुलिस बल सक्षम नहीं हो रहा है उन अपराधियों को गिरफ्तार करने में, इसमें किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग का हाथ है। वही लोग इस तरह का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह मांग की थी कि इसमें झारखण्ड सरकार, जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सीबीआई जांच कराए। दुर्भाग्य से आज तक न इस मांग के ऊपर कार्रवाई हुई है, न ही अपराधी पकड़े गए हैं। इसलिए आज आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से, नारायणसामी जी यहां बैठे हैं, झारखण्ड के राज्यपाल इनके निकट मित्र हैं, मैं विशेष आग्रह कर रहा हूं कि झारखण्ड सरकार को आप निर्देश दें कि वह तत्काल इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे ताकि अपराधी तत्वों पर कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो सके और उनको इसके लिए दंडित किया जा सके।

श्रीमती जे. शांता (बेल्लारी): महोदय, मैं कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। यह समस्या रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण में उत्पन्न होने वाली बाधा से संबंधित है। वैसे बेल्लारी ही देश का शायद पहला ऐसा जिला है जहां दो-दो रेडियो स्टेशन हैं। एक रेडियो स्टेशन बेल्लारी में है जबकि दूसरा एफएम रेडियो स्टेशन है, जो वहां से 60 किलोमीटर दूर हॉसपेट में है। वहां का पूरा क्षेत्र ऊंची पहाड़ियों से घिरा है जिसके कारण रेडियो तरंगें श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाती हैं और कार्यक्रमों का प्रसारण बाधित होता है।

पिछले सात वर्षों यह रेडियो स्टेशन केवल रिले सेंटर के रूप में काम कर रहा है जहां बेंगलुरु से कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। पहले केवल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही प्रसारण होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। रेडियो स्टेशन के निर्माण तथा विस्तार का काम चल रहा है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। मैंने इसके बारे में जुलाई, 2009 में सूचना तथा प्रसारण मंत्री को पत्र भी लिखा था।

मेरा सरकार से तथा मंत्री जी यही अनुरोध है कि बेल्लारी में रेडियो स्टेशन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही वहां जल्द से जल्द आवश्यक उपकरण लगाए जाएं। मैं यह भी अनुरोध करूंगी कि इन सुविधाओं के आने तक वहां बेंगलुरु से रिले प्रसारण को 12.00 बजे के बाद भी जारी रखा जाए।

श्री मनोहर तिरकी (अन्नीपुरद्वार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दार्जिलिंग की वर्तमान बिगड़ती हुई गंभीर आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विश्वविख्यात शैल शहर को बचाने की प्रक्रिया शीघ्र चालू की जाए।

महोदय, विगत तीन सालों से दार्जिलिंग की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हिंसापूर्ण और अगणतांत्रिक आंदोलन चलाने से पूरा पहाड़ और समतल अस्त व्यस्त हो गई है। लगातार बंद करना, विरोधी दलों को राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग न लेने देना, उनके घरों को जला देना, जन प्रतिनिधियों का दार्जिलिंग प्रवेश में बाधा देना, खुले आम नेताओं की हत्या, स्थानीय निकायों, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी चुनाव रोकना, सविधान के खिलाफ काम करना, किसी तरह का टैक्स न देना, हर सरकारी आफिस को बंद कर देना और विकास के सभी कामों को बंद कर देने से जन जीवन परेशान है।

दार्जिलिंग का मुख्य उद्योग पर्यटन और चाय है, जो कि बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तिस्ता हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण का काम रोक दिया है, जिससे निर्माण खर्चा दिन पर दिन बढ़ रहा है। वहां स्कूल-

कालेजों में पढ़ने के लिए देश भर के विद्यार्थी आते हैं। उनकी पढ़ाई बंद होने जा रही है। जी.एल.पी. (गोरखा लैंड पर्सनल) के नाम पर समानान्तर पुलिस तैयार कर प्रशासन अपने हाथों में ले रखा है।

इस आंदोलन को दार्जिलिंग पहाड़ से हटाकर समतल के दुवार्स में लाया गया है। जिससे गोरखा और आदिवासी, बंगाली, बिहारी, राजवंशी तथा अन्य जातियों में तनाव फैल गया है। इतने दिनों का सौहार्द भ्रातृत्व बोध को भयंकर साम्प्रदायिक भेदभाव में बदला जा रहा है।

महोदय, राज्य सरकार हमेशा से ही भारतीय नेपाली लोगों तथा पिछड़े सम्प्रदायों के विकास के लिए वचनबद्ध है। पहाड़वासियों की भावनाओं को मर्यादा देते हुए दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिल गठित की गई थी। लेकिन गोरखा हिल कौंसिल दार्जिलिंग की मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं कर पाई है। फिर से विकास के लिए क्षमताशील विकल्प व्यवस्था ग्रहण की जाए, इस बारे में चर्चा चलाई जा रही है।

हम छोटे-छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में नहीं हैं। हमारा अनुभव छोटे राज्यों जैसे झारखंड, मेघालय, नागालैंड इत्यादि राज्यों का है। केन्द्र सरकार त्रिपक्षीय वार्ता के लिए आमंत्रण कर दार्जिलिंग में शीघ्र शांति कायम करे, यही मेरा निवेदन है।

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, in Tamil Nadu, NH-47 that passes through Coimbatore and Tiruppur Districts is being widened now as a six-lane highway. Right now, the section between Sengampalli and Walayar is witnessing the progress in this widening work. Cultivable lands and residential plot areas from the private people are being acquired by the Government for the purpose of widening the road. The compensation that is being paid to the land owners are very low. Towns like Sengampalli, Perumanallur, Avinashi, Karumathampatti are situated on this highway. In these areas, the open market value of land per acre is Rs. 1 crore. The valuation by land registration authorities remain much less than the open market value and it is less than Rs. 10 lakh per acre. Due to this, the land owners are getting only 1/10th of the value of their land when they hand over their land for public purpose to the Government. So there is a need to pay adequate compensation considering the fact that these farmers are not able to purchase land in other areas with that meagre money to carry on their farming activity to earn their livelihood. At a time when Government are taking measures to help ease the burden of people to contribute to our economy, these poor and marginal farmers who offer their lands to the Government must not be left in the lurch to fend for themselves. They have offered their land for a common cause to the Government so that Government may provide to the public a six-lane highway. This factor must be borne in mind when compensation is paid to such farmers and must be helped to carry on with their livelihood elsewhere. The compensation must help them to rehabilitate themselves. Hence, I urge upon the Government to pay compensation commensurate with the market value as a better deal for they have contributed for the betterment of the public roads system. Thanking the Chair for the opportunity, I conclude.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Sir. The work under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) has been continuing for more than three years in my Parliamentary constituency. Purulia district comprises of 20 blocks; 170 Gram Panchayats; three Municipalities and more than 2,500 villages. The work is going on, but the work regarding electric supply under the RGGVY has not been completed. The standard of equipment being provided for electric supply under the RGGVY is of very low standard.


We appeal, through you, to the Minister that the poor people, backward people, Scheduled Tribes people, Scheduled Castes people and those who are living in remote villages, that is, more than 9 or 10 blocks are affected with Maoist activities and many events are taking place on a day to day basis.

Electricity is most essential nowadays for the benefit of the poor people, students and all sections of inhabitants, but the work has not been completed. An assurance was given that the work will be completed by 31 March 2010, but the work has not been completed till today. Most of the tolas under the mozas are not being electrified. Therefore, my humble submission, through you, to the Minister is that the work for a backward district in West Bengal under RGGVY should be completed immediately. This is my humble submission to you.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Sir. I would like to utilize this opportunity to bring an important subject to the attention of this august House for a timely solution. It is regarding one of the upcoming mega-projects of India, namely, the International Container Transshipment Terminal at Vallarpadam, Cochin. This project is considered as the prestigious port-project of our country. I would like to congratulate our hon. Prime Minister and the UPA Chairperson for bringing such a mega-project, which is going to be a prestigious project for India.

19.00 hrs.

The terminal is immensely seeking "relaxation in cabotage law" for its smooth opening and getting pace in operations. This transshipment project is facing a crisis in its initial stages.

But as we know, Cabotage provisions under the Merchant Shipping Act restrict operation of foreign flag ships between  Indian ports. Implementation of

this law may be destructive for a new mega project like Vallarpadam because it will be beaten on the prospects of this super project, as we don't have sufficient transit infrastructure to meet the demands for the transshipment and it will lead to delay in the operations of cargo vessels along with extra costs.

If the terminal gets the cabotage relaxation it will allow foreign shipping vessels to carry cargo between Vallarpadam and other Indian ports. This special privilege is expected to help the port to ensure faster pooling of cargo and their delivery. Everybody believes this will enable the terminal to attract the Indian cargo, now being transhipped at the neighbouring ports of Colombo, Singapore and Dubai.

The transshipment hub needs the back-up of feeder services to pool cargo from other Indian ports and to deliver imported cargo to the final destinations. If, Indian feeder operators do not have the capacity to provide the required service then the foreign lines should be allowed to operate between the terminal and Indian ports. According to trade estimations, annually around three million TEUs of Indian cargo is transhipped through Colombo alone. If this traffic can be handled at Kochi, there will be a considerable saving in transit time and costs for Indian shippers. It is claimed that if Vallarpadam is given the cabotage relaxation, at least one million TEUs of the three million TEU of Indian cargoes now being handled at Colombo can be diverted to Kochi.

In fact, the Vallarpadam project itself was conceived of with the objective of developing a transshipment hub in India to help the country's sea trade.

I am sure that if the relaxation on cabotage for Vallarpadam is not considered, it will be adverse to the growth of entire Indian shipping industry along with degradation of Vallarpadam project. In fact as per the cabotage law, the trans-shipment containers coming from abroad and bound for other Indian ports, and containers originating in Indian ports and transhipped at Cochin on their way to overseas destinations, can be treated as domestic cargo. It is a vital clause in the

Merchant Shipping Act and if it is being implemented strictly for a new port such as Vallarpadam, definitely it will adversely affect the potential of this project.

As we know the terminal is being set up at a cost of 500 million US dollars and is expected to be commissioned in near future and it will have the capacity to handle 1.2 million TEUs annually in the first phase and three million TEUs on full completion of the project.

So my request to the Government, especially to Shipping Ministry, is that urgent instructions may be given to the Director General of Shipping for relaxing the cabotage law, aiming at convenience and for the smooth opening in operations and development of this India's prestigious project. .

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Thank you very much for giving me this opportunity. A bypass road has been constructed on NH-4 in my constituency, Hubli-Dharwad, which is the second biggest city after Bengaluru. This bypass is a 30-kilometre stretch which has been constructed and this has been constructed under BOT (Build, Operate and Transfer). This bypass was constructed well before the Golden Quadrilateral between Bengaluru and Pune, that is, on National Highway 4. But after conversion, during Atal Bihari Vajpayeeji's period, into four-lane of this National Highway 4 between Bengaluru and Pune, this bypass remained as a single lane. That has become a bottleneck. From the outskirts of Hubli, from a place called Gabbur, to Narendra at Dharwad outskirts, it is a single lane. Bengaluru to Pune, it is a six-lane highway, but between Hubli and Dharwad bypass, since it is under BOT, still it is remaining as a single lane and it has become a bottleneck.

Now, the traffic has increased manifold. After completion of the work by 2004 end, till now this bypass on the National Highway itself has remained a single lane. It is causing a lot of traffic hazards, and a lot of accidents have already taken place. That is why, many a time, I have met the Minister and requested him to convert this bypass into a four-lane or a six-lane as the NH-4 is under consideration for conversion into a six-lane. The Government should convert the

bypass or persuade the BOT holder to convert it into a six-lane. Otherwise, people are already agitating. Many people have died in accidents.

I urge upon the Government to immediately to look into the matter and either persuade the BOT holder or to take over from the BOT holder after due payment to him and convert it into a six-lane. Thank you.


श्री भूदेव चौधरी (जमुई) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका ध्यान शून्यकाल के माध्यम से बिहार राज्य के जमुई लोकसभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो मेरा जमुई क्षेत्र है, यह क्षेत्र अपने आप में एक संवेदनशील क्षेत्र है। गरीब बाहुल्य तथा अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिले में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जिससे क्षेत्र के दलितों और गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा के पठन पाठन से वंचित रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जमुई जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किये जाने के निमित्त सरकार आवश्यक कार्रवाई करे।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): With the permission of the Chair, I wish to bring an important issue to the notice of the hon. Minister of Steel. Salem Steel Plant was started in 1970s. At that time, for the use of the plant operation and for the residency use, the Steel Plant authorities laid a pipeline for taking water from Poolampatti. From Poolampatti to the plant site, a bitumen tar road was formed for maintaining the pipeline. The villagers on either side of the said road were allowed to use the road. Even now they are using the said road. Now the road was in a bad shape with many potholes and it would no longer be used. If it is re-laid with pucca metal topping, it would be very useful for both the public and the employees also to maintain the pipeline. So, I request the hon. Minister of Steel to take up the issue on an urgent mode and allot sufficient fund for relaying the road at a length of nearly 25 kilometres. If not possible to take up the work at a stretch, the relaying work may be taken up in a phased manner at least. I hope the hon. Minister will pay heed to my request.

RAJKUMARI RATNA SINGH (PRATAPGARH): I would like to bring to your kind notice that in the year 2006, the Government of India started BRGF fund

which was for the backward regions of India and over 250 districts were taken up and over 30 districts in Uttar Pradesh and my district Pratapgarh was taken up. But in Uttar Pradesh, we find that the work is going very slow. In all these years, only one set of funds has come. Money has reached Pratapgarh for only one year, that is, the year 2007-2008 of a sum of Rs.18.66 crore. For the year 2009-10, the funds have just been recently released about one week ago. The remaining years, 2006-07, 2008-09 and 2010-11, no funds have come and the schemes which have been taken specially for the years 2006-07 and 2008-09 do not have the same relevance now. Through you, I would request you to ask the Rural Development Ministry that in Uttar Pradesh where the funds are not going, these new set of things should be taken up and they should be sanctioned with the recommendations of the MPs. Just now, the MP is not being involved in the sanctioning process and we feel that as this is a fund completely given by the Government of India and the State Government has no financial involvement in this, there should be a new guideline given because this fund is only for five years. And only two years the money has come to Uttar Pradesh. The new guidelines should be taken and the funds should be sanctioned with the MP's recommendation.

For the year 2007-08, the agencies to which these funds were given were not according to guidelines. So, I would request the Government to ensure that an inquiry is held, especially in Pratapgarh, to find out on what these funds have been spent for the year 2007-08.

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHEERABAD): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the kind attention of the  August House to the dire need to include agriculture related works and its workers in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

The Planning Commission in its recent report has stated that the performance of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme remains patchy despite making a significant overall impact in providing rural job schemes. It is also estimated that only 14 per cent worker households could gain

100 days of work. It was estimated that in 2009-10, some five crore families were provided around 300 crore person-days of work under the prestigious scheme. This was more than three times the employment generated in 2006-07.

In the four years that the job guarantee programme had been in force, it had managed to provide some 600 crore person-days of work at a total expenditure of around Rs. 70,000 crore. What was even more remarkable was the coverage of SCs, STs and women under the scheme. Nowadays agriculture related jobs are vanishing and the workers are migrating and depending on other jobs. We have already set a goal to achieve 4 per cent growth rate in agriculture, but we are hovering around two to three per cent only. This situation needs to be addressed on a war footing to improve the overall growth of our economy for double digit. Agriculture related works need to be included in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme not only in Andhra Pradesh, but all over the country in the current year itself with sufficient allocations.

The share of SC/ST families in the work provided under MGNREGA in the past four years ranged between 51 and 56 per cent while that of women was 41 and 50 per cent during the corresponding period. If the Government includes agricultural works, it will definitely increase the GDP growth rate and poor people will take up these works enthusiastically and as a profession and improve the production of various food items to meet the growing needs of the people of our country. We can also avoid the imports of various food items with such inclusions and can also save the economy.

Jobs will be increased in all the States automatically with the inclusion of Agriculture related jobs in Mahatma Gandhi NREGA by taking it as a pilot scheme and we can bring a second Green Revolution by increasing the minimum days of work to more than 150.

I, therefore, request the hon. Minister of Rural Development, through the Chair, to include agriculture and related jobs under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the current Five-Year Plan.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I would like to associate myself with the issue raised by hon. Member Shri Suresh Kumar Shetkar, of need to include agriculture related and other works in the shelf of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Human Resource Development, through you, to the problems being faced by the students and their parents in Mandya Parliamentary Constituency in Karnataka due to non-existence of a Kendriya Vidyalaya.

The private or public schools situated in my Parliamentary Constituency are charging exorbitant fees and the common people are facing great difficulties in paying such huge amounts. Even though these schools are collecting exorbitant fees, this area lacks good quality English medium schools. There are a huge number of Government servants residing in Mandya. If a Kendriya Vidyalaya is opened in this area, it will be of great help to the middle level and lower level people. The people of my Parliamentary Constituency are demanding for establishment of a Kendriya Vidyalaya there. In this connection, the State Government of Karnataka has submitted a proposal to the Ministry of Human Resource Development, but no action has been taken so far. This is one of the most important proposals in respect of my Parliamentary Constituency Mandya. Therefore, I urge upon the Union Government to consider establishing a Kendriya Vidyalaya in Mandya on top priority basis for the benefit of students and parents in the Constituency.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): I would like to raise an important matter of public importance regarding the health of the people of this country due to huge shortage of doctors. There is an acute shortage of doctors and paramedical



staff; and it is assuming alarming proportions. According to the latest data on rural health statistics, a huge number of posts sanctioned for medical staff in primary and community health centres are lying vacant. In the case of primary health centres, there are 5,300 vacancies of doctors; 7,300 vacancies of health care workers and 1,700 health assistants. The situation is grim in community health centres, where about 4,000 posts of specialists, 5,000 posts of pharmacists, and 5,600 posts of lab technicians are lying vacant. There is also a dire need of 10,000 nurses.

Secondly, as per the Planning Commission's study, the country is short of six lakh doctors, 10 lakh nurses. It reports that the doctor to patient ratio is one is to 10,000. This is a crisis.

The reason for shortage varies from State to State. But this is an integral part of the National Rural Health Mission; in spite of this, the situation is very serious. Experts in this field feel that more than the vacant positions, the doctors also do not attend to the patients which is a genuine cause of concern.

Hence, I request the Minister of Health and Family Welfare to ponder over this issue in all seriousness, and fill up the vacant posts so that poor people are taken care of better.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हू कि केन्द्र सरकार के अधीन एवं स्वामित्व में संचालित दिल्ली स्थित भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की परिनिर्वाण भूमि (मृत्युस्थली) गत सात वर्षों से बदहाल, सुनसान, अनजान एवं अपमानजनक अवस्था में है। यह परिनिर्वाण स्मारक 26, अलीपुर रोड दिल्ली स्थित है। वर्ष 2003 में एन.डी.ए. सरकार के समय में इस परिनिर्वाण भूमि को निजी व्यक्ति से लगभग 16 करोड़ रुपये में खरीद कर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके सम्मानजनक विकास की एक कार्य योजना बनायी गई थी लेकिन केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद यू.पी.ए. की सरकार ने इसे भुला दिया। अनेक बार मांग करने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और अभी तक परिनिर्वाण भूमि उपेक्षित पड़ी है।

सभापति महोदय, उल्लेखनीय है कि परिनिर्वाण भूमि देश के दलितों का चौथा धाम है। डॉ. अम्बेडकर की जीवन-स्मृति के चार महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो दलितों के चार धाम हैं। पहला-जन्मभूमि, महु-

म.प्र., दूसरा-दीक्षाभूमि, नागपुर-महाराष्ट्र, और तीसरी चैत्यभूमि (अंत्येष्टि स्थल) मुम्बई में है। ये तीनों स्थान सम्मानित हैं जहां लोग बाबा साहेब के लिये प्रार्थना करते हैं व नतमस्तक होते हैं, लेकिन दिल्ली स्थित परिनिर्वाण भूमि पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां ताले लगे हुये हैं और एक मोमबती भी नहीं जलाई जाती है। बाबा साहेब की परिनिर्वाण भूमि के विकास के मामले में केन्द्र की वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल रही है।

सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि इस संबंध में यू.पी.ए.सरकार नींद से जागे और डॉ. अम्बेडकर के इस स्मारक-निर्वाण भूमि के विकास की कार्य-योजना को तत्काल प्रारंभ किया जाये। वहां पर बुद्ध विहार का निर्माण किया जाये। उनके जीवन की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया जाये। परिनिर्वाण भूमि को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये। इसके सम्मानजनक संचालन एवं सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये। इसके आगामी विकास हेतु एवं वृहदभूमि की उपलब्धता कराने हेतु इस स्मारक के भवन के आसपास के सभी बंगलों को भारत सरकार द्वारा खरीदकर अधिगृहीत किया जाये एवं इस क्षेत्र में सभी का स्थल बनाकर वहां सौंदर्य एवं गरिमापूर्ण वातावरण का निर्माण किया जाये। प्रतिवर्ष 6 दिसम्बर को परिनिर्वाण भूमि में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाये। दैनिक गतिविधियां संचालित की जायें। महात्मा गांधी जी की दिल्ली स्थित समाधि राजघाट के बराबर परिनिर्वाण भूमि को दर्जा व सम्मान दिया जाये और संसारभर से भारत आने वाले राजनयिकों को सरकार द्वारा इस परिनिर्वाण भूमि पर ले जाकर पुष्प अर्पित कराने का कार्यक्रम चलाया जाये। डॉ. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धाजलि सभा में देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधान मंत्री जी उपस्थित हों।

...(व्यवधान) प्रतिवर्ष 6 दिसम्बर को परिनिर्वाण भूमि में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, केन्द्र सरकार प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र की योजनाओं के माध्यम से खर्च कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं के लिए जो धन जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं इस संबंध में अपने जनपद महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूं। सर्व शिक्षा अभियान में पिछले तीन वर्षों में 67 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मेरा आरोप है कि उसमें से कम से 20 करोड़ रुपये ... (व्यवधान) *की बलिवेदी पर चढ़ गए हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुझे

* Not recorded.

बताया है कि वर्ष 2007-08 में 1,70,185, वर्ष 2008-09 में 1,68,831 और वर्ष 2009-10 1,22,419 प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए यूनीफार्म बनायी गयी। कुल 4 करोड़ 61 लाख की यूनीफार्म बतायी गयी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महाराजगंज जनपद की पांच से नौ वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों की जनसंख्या 1,65,732 थी। यदि हम महाराजगंज की जनसंख्या की वृद्धि दर को इसमें जोड़ लें तो भी वहां इस काल में 1 लाख 90 हजार से अधिक लड़कियां नहीं हैं। जबकि 1 लाख 70 हजार लड़कियों की ड्रेस बनवाकर सौ रुपये प्रति ड्रेस के हिसाब से निकाल लिया गया।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : That word will not go on record. That will be deleted.

श्री हर्ष वर्धन : मैं आपसे एक मिनट चाहता हूं। मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि 1 लाख 70 हजार लड़कियां प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही हों। मैं यह कह रहा हूं कि सर्व शिक्षा अभियान और बीआरजीएफ में प्रक्रिया की जो दिक्कतें हैं, बीआरजीएफ का पैसा जिला योजना समिति से पारित होकर प्रदेश समिति में आता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति इसे पारित करती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि संघीय व्यवस्था की बात करके इसे समाप्त न किया जाए। इस सदन के 5-6 सदस्यों की समिति महाराजगंज में जाकर जांच कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लूट है, उसका महाराजगंज उदाहरण है। उसकी जांच की जाए, यदि मेरा आरोप गलत सिद्ध होता है तो मैं इसी सदन से कहता हूं कि मैं इस्तीफा देकर यहां से चला जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लूट को समाप्त करवाया जाए, केवल संघीय व्यवस्था के नाम पर इसे दबाए रखने का कोई तात्पर्य नहीं है।

SHRI TAPAS PAUL (KRISHNANAGAR): I would like to bring to the notice of the august House that kidnapping, abduction of women, kidnapping of children, young girls, housewives are happening in West Bengal. They are lured for going out to work as domestic helps, but in reality, they are sucked into the whirl of flesh trading. It is really a big social problem. People all over India are not getting any help from administration. In this context, I want to draw the attention of the House to the saddest part that my constituency Krishnanagar is also victim of such a crime. Girls and women are sold to different places in different parts of the country, and also Bangladesh. In Chapra village which is under my constituency, nearly 30 girls were abducted and sold to different places. The people of that village formed a group awareness campaign to save the poor girls but they are not

getting any support from the local administration. I am very much embarrassed to say that my constituency, Krishnanagar, West Bengal is facing such kind of a crime. It is a matter of regret that in most of the cases, the poor victims could not be detected.

I appeal to the hon. Home Minister of India, through you, Sir, that proper steps to stop this unhealthy practice should be taken to save the girls and housewives.

वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक आदिवासी लड़की को नंगा करके घुमाया। मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर को बोलना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You are allowed to raise only one matter.

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, श्री तापस पॉल जी ने जिस विषय पर बोला है, उस विषय के साथ मैं भी आपसे आपको सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मोर हत्या के बारे में आकर्षित करना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति में मोर का विशिष्ट स्थान है। धार्मिक मान्यता मुजब मोर शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन है। पक्षियों की गणना में वह पक्षीराज है। राष्ट्रीय मान्यतानुसार भारतीय संविधान ने उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है। ग्रीक, इजिप्ट, सिरीया इत्यादि देशों की संस्कृति में भी मोर का मानभरा स्थान है। पड़ोसी देश बर्मा ने भी उसे राष्ट्रीय दर्जा दिया है। मोर के सौन्दर्य से सभी चिर-परिचित हैं। उसके पंख तो और भी लाजवाब हैं, इस सौन्दर्य मोहने मोर पंख का व्यापारीकरण कर दिया है।

सभापति महोदय, देश के कई स्थानों में मांगलिक एवं सामाजिक समारोह में भी मोर मांस खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोर पंख भी निर्दयता से निकाले जाते हैं और विदेशों में भेजे जाते हैं। ये 1500 रुपए में बेचे जाते हैं। जंगल में रहने वाले असामाजिक तत्व भी मोर के बच्चों की 400-500 रुपए में खरीदी एवं बिक्री करते हैं और मोर के अंडे को कृत्रिम तरीके से फलीभूत करके, मोर के पंख को निकाल कर बेच देते हैं एवं मांस भक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, मोर पंख के लिए जहर का भी प्रयोग किया जाता है।

सभापति महोदय, देश भर में मोर मौत हत्या के संदर्भ में हुए सर्वेक्षण अनुसार पांच प्रतिशत पंख और मांस हेतु मोर हत्याएं हुई हैं और आठ प्रतिशत अकस्मात कुत्तों के हमले, बिजली करंट इत्यादि से हुई हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कॉलम 44 के अनुसार मोर पंख का व्यापार करने की छूट है,

जिससे शिकारी बिना डर से मोर हत्याएं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोर पक्षियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि सरकार मोर हत्याएं बंद करने हेतु कठोर कानून बनाए और निर्दयी तरीके से हो रही मोर हत्याएं बंद करने हेतु उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: श्रीमती जयश्रीबेन पटेल जी ने जिस विषय पर बोला है, उस विषय के साथ मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Recent incidents disclose that terrorist outfits have shifted their operational base to communally balanced and harmonious States like Kerala. Kerala, which is a State known for communal and religious harmony, has become the target of some national as well as international terrorist outfits. Kerala has a long history of religious harmony. It was the great patriotic fighters like Kunjali Marakkar who supported Hindu kings to fight against foreign invaders. Many are unaware of the fact that the great epic Ramayana is not the sole monopoly of Hindus. Kerala has Mappila Ramayana which was authored by Muslim poets and sung by Muslims. When the Hindu fanatics destroyed the Babari Masjid and calamity broke out, it was the Muslim brothers who protected their Hindu brothers in Kerala. One can see in Kerala a synagogue, church, mosque and temple in close vicinity. The communal harmony of Kerala was achieved by great reformers and the Indian National Congress. Some terrorist outfits are purchasing real estates in coastal areas and supporting uneducated youths to destroy the religious harmony. These outfits are functioning under the fake banner of Human rights organizations with secular name and style. Last month's incident in which a professor's hand was brutally chopped off in the presence of general public by the activists of terrorist outfits was an eye-opener. The pamphlets seized in repeated raids conducted in the havens of these outfits confirm their national and international link. I appeal to the Government to gather intelligence and to prevent the destruction of communal harmony. I also request

the Government to conduct an inquiry by National Investigation Agency to bring to light the tacit operations of these terrorist groups.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। उससे ऊपर की तरफ हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और पंजाब का एरिया पड़ता है। हमारे यहां घग्घर नदी की बाढ़ आई हुई है। पहाड़ी एरिये में जब बर्फ पिघलती है, तो वह पानी, नदी के रूप में प्रवाहित होता है और कभी-कभी, तीन, चार या पांच सालों में बाढ़ आती है। अब उस बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि यह पानी पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान, भारत सरकार से मुआवजा भी लेता है कि घग्घर नदी का पानी हमारे यहां तबाही मचा गया तथा दूसरी ओर वह बांध बनाकर इस पानी का यूज भी कर रहा है।

महोदय, जहां मेरा इलाका है, जिसमें नहरें बनी हुई हैं जैसे अनूपगढ़ ब्रांच बनी हुई है और ब्रांचें बनी हुई हैं। इनमें अनूपगढ़, घड़साना, रावड़ा, 365 हैड, खाजूवाला और पूगल आदि आते हैं, उनमें नहरें बनी हुई हैं, लेकिन यदि अनूपगढ़ के पास बिंजौर में बांध बनाकर इस नदी के पानी को रोक दिया जाए, तो एक तो पाकिस्तान को जो मुआवजा भारत को देना पड़ता है, वह नहीं देना पड़ेगा और दूसरी ओर उस एरिया में नहरी पानी के लिए जो आंदोलन होते हैं, वे नहीं होंगे। वहां पानी के लिए लोग लॉ-एंड-ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, उससे भी हम बच जाएंगे। इससे वहां के जो किसान हैं, वे खुशहाल हो जाएंगे और खेती के माध्यम से वे अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। इससे एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट पंजाब में है, वैसी ही राजस्थान के हमारे एरिये में हो जाएगी। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि अनूपगढ़ के पास, बिंजौर में बांध बनाकर इस पानी को रोकें।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, today is the 103rd Martyrdom Day of Shaheed Kshudiram Bose, the first Indian freedom fighter hanged by British Rulers in pre-Independent India on 11th August 1908. I believe the entire country including this august House would pay rich tribute to this great son of our soil.

As you are aware, Shaheed Kshudiram Bose symbolized fearlessness, determination, devotion and selflessness for the liberation of the motherland India through the uncompromising path of armed struggle which created a deep impact both on the countrymen and on the British rulers, proper evaluation of 'their role in freedom movement starting from Kshudiram Bose to Bhagat Singh is earnestly

required. Some textbooks in Independent India have labeled them as 'extremists' like the British rulers - which is neither a fact nor it has got any relation with such devoted brand of freedom fighters, which needs rectification and replacement with proper textual history. Rather I believe, propagation and cult of their characters and life struggles will help to make our present generation of youths and students as superior human beings, more responsible for the society and the country.

Therefore, I would request the Central Government to take up this matter of proper evaluation of their role of uncompromising trend in Indian freedom struggle history and to publish it in textual form for the appraisal of all. I would also request the Central Government to install a full size statue of Shaheed Kshudiram Bose in the Parliament House premises.

श्रीमती कमला देवी पटले (जांजगीर-चम्पा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।

मैं सदन का ध्यान लेह में हुई भयंकर प्राकृतिक त्रासदी की ओर दिलाना चाहती हूँ। आपदा की भयावहता इसी से पता लगती है कि लेह में बादल फटने से हवाई अड्डा, स्कूल, दफ्तर एवं गांव के गांव बह गए। कुछ भी नहीं बचा है। हजारों जानें गई हैं। हजारों घायल हैं तथा हजारों लापता हैं। इतनी भयंकर तबाही हुई है कि दूर-दराज के इलाकों में राहतकर्मियों को पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं।

महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के काफी मजदूर वहां कमाने-खाने गए हुए थे। मेरे संसदीय क्षेत्र जांजगीर-चाम्पा जिले के, यानी एक ही जिले के 22 मजदूर मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। 26 लोग घायल हैं और 44 लोग लापता हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जो मृतक हैं, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, घायलों के इलाज के लिए सरकार धन मुहैया कराए तथा लापता लोगों की खोज कराई जाए और उनकी वहां से छत्तीसगढ़ वापसी की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

MR. CHAIRMAN : The House now stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

19.36 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, August 12, 2010, Sravana 21, 1932 (Saka).*

